चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 24 अक्टूबर–30 अक्टूबर 2011 | मूल्य 5 रुपये

टॉप सीक्रेट फाइल की कहानी क्या है

पेज-3

पूरा देश अव्यवस्था का शिकार है

पेज-5

बुलंदी की दहलीज़ पर शेखावाटी की महिलाएं

पेज-7

साई की महिमा

पेज-12

संघ ने अन्ना का सबसे बड़ा नुक़सान किया

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

मनीष कुमार

क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक पौरुषविहीन संगठन हो गया है. क्या संघ परिवार देश में ख़ुद किसी आंदोलन को शुरू करने का सामर्थ्य खो चुका है. क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस कदर वैचारिक पतन हो गया है कि नौजवानों को सड़कों पर उतारने की उसकी शक्ति ही ख़त्म हो गई. क्या संघ परिवार का अपने पूर्णकालिकों, नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों से विश्वास उठ गया है या फिर हमें यह मान लेना चाहिए कि संघ भी देश के उन संगठनों की तरह हो गया है, जो सिर्फ़ नाम के देशव्यापी संगठन हैं, लेकिन उनमें कोई ऊर्जा नहीं है. ये बातें इसलिए उठ रही हैं, क्योंकि मोहन भागवत के बयान भ्रमित करने वाले हैं. यह सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं, क्योंकि अगर आडवाणी जी की रथ यात्रा में पैसे देकर लोगों को लाया जा रहा है, लिफाफे में पैसे देकर अख़बारों में ख़बरें छपवाने की कोशिश हो रही है तो यह संघ परिवार के लिए एक शर्मनाक स्थिति है.

अन्ना हजारे के आंदोलन पर मोहन भागवत का एक बयान आया कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ चलाए जा रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं के आंदोलन को उनके संगठन का समर्थन है. मोहन भागवत का यह बयान अन्ना के आंदोलन को कमज़ोर करने वाला बयान है. जिन आरोपों को लेकर कांग्रेस अन्ना को बदनाम और कमज़ोर करने की असफल कोशिश कर रही थी, मोहन भागवत के एक बयान से कांग्रेस के वे सारे आरोप सही साबित हो गए. समझने वाली बात यह है कि अन्ना सरकार से लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एक सशक्त क़ानून की मांग कर रहे हैं. अन्ना का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन एक सामाजिक पीड़ा का आंदोलन है और सभी धर्म–जाति के लोग पीड़ित हैं. बस अंतर सिर्फ़ इतना है कि टीम अन्ना ने इस पीड़ा को समझा और आंदोलन को खड़ा किया. अन्ना का आंदोलन आम आदमी की प्रतिष्ठा से जुड़ा है. मीडिया को भी अन्ना के आंदोलन को किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जोड़ना चाहिए. विभिन्न दलों के जो नेता अन्ना के समर्थन में उतरे हैं, उन्हें आम आदमी जैसा ही समझना चाहिए.

अन्ना हजारे के आंदोलन पर मोहन भागवत का एक बयान आया कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ चलाए जा रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं के आंदोलन को उनके संगठन का समर्थन है. मोहन भागवत का यह बयान अन्ना के आंदोलन को कमज़ोर करने वाला बयान है.

बहस इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि अन्ना को संघ का समर्थन है या नहीं. सवाल दूसरा है. क्या देश की जनता को यह हक नहीं है कि वह किसी आंदोलन को अपनी बुद्धि से आंक सके और यह जान–समझ सके कि अन्ना के आंदोलन का प्रारूप क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, उनके आंदोलन की अच्छाई क्या है बुराई क्या है, क्या उनके आंदोलन को समर्थन करना चाहिए या नहीं. आम देशवासियों के स्वतंत्र रूप से चिंतन–मनन के हक़ को छीनने की कोशिश हो रही है. अगर देश में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अन्ना आंदोलन कर रहे हैं तो संघ को भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आंदोलन करने से किसने रोका था. अन्ना के आंदोलन से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर क्यों सोया हुआ था. भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में कालेधन का मामला उठाया था, लेकिन संघ के लोगों को रामदेव की ज़रूरत क्यों पड़ गई, ख़ुद कोई आंदोलन क्यों नहीं किया. इससे तो यही साबित होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जनता के सरोकार से कोई मतलब नहीं है और अगर है तो उसके पास इतनी शक्ति, इतना पौरुष नहीं है कि वह देशव्यापी आंदोलन खड़ा कर सके. जब अन्ना ने एक सफल आंदोलन किया तो उसका श्रेय लेने की कोशिश क्यों हुई.

समझने वाली बात यह है कि अन्ना का आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन है. राजनीतिक आंदोलन से मतलब यह है कि आंदोलन की मांग राजनीतिक है. आंदोलन का असर राजनीतिक दलों पर भी होना निश्चित है. इसलिए अन्ना और उनकी टीम का राजनीतिक दलों से दो– दो हाथ होना टाला नहीं जा सकता है. कोई दोस्त बनकर हमला करेगा तो कोई दुश्मन. कांग्रेस पार्टी दुश्मन बनकर अन्ना पर हमला कर रही है, मोहन भागवत ने दोस्त बनकर अन्ना को खंजर मारा है. इसलिए अन्ना को मोहन भागवत के बयान से ज़्यादा नुक़सान हुआ है. कांग्रेस के दिग्विजय सिंह अन्ना पर संघ के साथ साठगांठ का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है. वह अल्पसंख्यकों को अन्ना के आंदोलन से दूर रखना चाहते हैं. दिग्विजय सिंह इसमें सफल होते या असफल, यह तो बाद में तय होता, लेकिन मोहन भागवत ने ऐसा बयान देकर एक ही झटके में अल्पसंख्यकों और दक्षिणपंथी विरोधियों को अन्ना से अलग करने की कोशिश की. कांग्रेस पार्टी आंदोलन की शुरुआत से ही इसे कमज़ोर करने के लिए कई हथकंडे अपनाती रही.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं

आडवाणी जिस पार्टी के पालक और पोषक रहे और जिसे उन्होंने सरकार बनाने लायक बनाया, अब प्रधानमंत्री पद के मोह में उसी को नष्ट करने में लगे हैं. लालकृष्ण आडवाणी जनचेतना यात्रा के ज़रिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं. इसके लिए उन्होंने ऐसी रणनीति अपनाई है, जिसका असर अगले कई चुनावों तक दिखेगा. आडवाणी की यह यात्रा भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा बीज बो रही है, जिससे पार्टी में हर जगह भस्मासुर पैदा होंगे. यह पार्टी एक अंतहीन गुटबाजी के चक्रव्यूह में फंसेगी. इसका हाल वही होगा, जैसा कि दो परमाणु बम वाले देशों के बीच युद्ध में होता है और जिसमें कोई विजेता नहीं होता. यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार अगले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने की योजना बनाने और उस पर काम करने के बजाय प्रधानमंत्री पद के लिए आपस में लड़ रहे हैं. दो सितारे आमने- सामने हैं, बाकी फ़िलहाल चुपचाप तमाशा देख रहे हैं. लोकसभा चुनाव कब होंगे, यह किसी को पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कम से कम 6 ऐसे नेता ज़रूर हैं, जो अगला प्रधानमंत्री बनने की योजना पर काम कर रहे हैं. फ़िलहाल आडवाणी इस दौड़ में सबसे आगे हैं. ज़ाहिर है, जो लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वे बड़े नेता हैं. इसलिए यह कहा जा सकता है कि भाजपा के सारे बड़े नेता आपस में लड़ रहे हैं, पार्टी ऐतिहासिक गुटबाजी के कुचक्र में फंस गई है, भाजपा नेता अब संघ की बातों को भी टालने लगे हैं, हर नेता तबीयत ख़राब होने का बहाना बनाकर घर में बैठा है, कोई किसी भी गुट में दिखना चाहता है, पार्टी के वरिष्ठ रणनीतिकारों के बीच वार्तालाप बंद हो गया है, सारे नेता अपनी-अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं. निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता

(शेष पृष्ठ 2 पर)

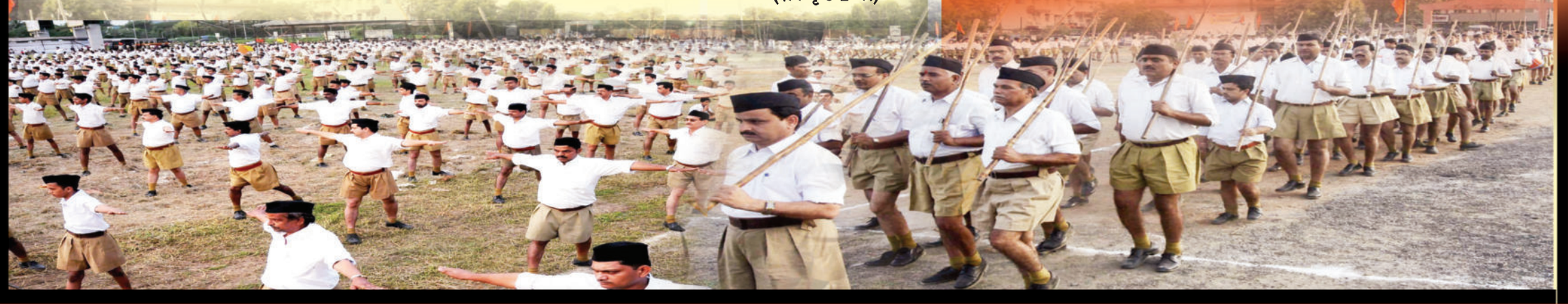

प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष दोनों से नजदीकी होने के कारण ऐसा माना जा रहा है कि पुलक चटर्जी दोनों के बीच की कड़ी का काम करेंगे.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

पीएमओ में पुलक चटर्जी

पुलक चटर्जी प्रधानमंत्री कार्यालय में लौट आए हैं. उन्हें प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव बनाया गया है. उनकी नियुक्ति ऐसे समय में की गई है, जबकि यूपीए सरकार एक साथ कई समस्याओं से जूझ रही है. यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है. उनके पूर्ववर्ती अधिकारी टी के नायर को प्रोन्नत करके प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है. पुलक चटर्जी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के नजदीकी रहे हैं. इससे पहले वह मनमोहन सिंह के निजी सचिव भी रह चुके हैं. प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष दोनों से नजदीकी होने के कारण ऐसा माना जा रहा है कि पुलक चटर्जी दोनों के बीच की कड़ी का काम करेंगे. उनके आने से काम में गति भी आएगी और प्रधानमंत्री एवं सोनिया गांधी के बीच बातचीत में आने वाली रुकावटें कम होंगी. खैर, यह तो समय ही बताएगा कि चटर्जी अपने पद के साथ कितना न्याय कर पाते हैं और उन उम्मीदों पर कितने खरे साबित होते हैं, जो उनसे की जा रही हैं.

नंदा की जगह कौन?

उड़ीसा राजस्व बोर्ड के सदस्य सत्य प्रकाश नंदा को उड़ीसा विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है. इसके साथ ही राजस्व बोर्ड के सदस्य पद के लिए अटकलें तेज हो गई हैं. इस पद के दावेदारों में विकास एवं कृषि उत्पाद आयुक्त आर एन सेनापति, अरबिंदो बेहरा और केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव जी सी पाटी के नाम शामिल हैं. हालांकि पाटी इस समय केंद्र में हैं, लेकिन उन्हें राज्य में भेजा जा सकता है. इन सभी में बेहरा को इस पद पर नियुक्त किए जाने की उम्मीद है, यदि पाटी को केंद्र से अभी न बुलाया जाए. इसके अलावा एक और उम्मीदवार जुगल किशोर महापात्रा हैं, जो अभी वित्त विभाग में मुख्य सचिव के पद पर हैं. ऐसा माना जा रहा है कि इस पद पर नियुक्ति तो उसी की होगी, जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के सबसे करीब होगा.

लाली से सबक

प्रसार भारती के सीईओ बी एस लाली पर आरोप लगने के बाद सरकार इसके अगले सीईओ के अधिकारों में कटौती करने की बात सोच रही है. इसके अलावा प्रसार भारती बोर्ड के सदस्यों की आयु सीमा 62 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष करने का प्रस्ताव है. प्रसार भारती अधिनियम के अनुसार इसके सीईओ को राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के अनुमोदन के बिना नहीं हटाया जा सकता. ऐसा कहा जाता है कि लाली ने इस नियम का फायदा उठाया और पद का दुरुपयोग किया. नए प्रस्ताव में कहा गया है कि इस विभाग का सीईओ अब एकतरफा फैसला नहीं ले सकता. यह प्रस्ताव इसलिए लाया गया, क्योंकि पूर्व सीईओ लाली ने समिति की बात न मानकर एकतरफा फैसला लिया और लाभ उठाया, जिसके कारण प्रसार भारती को काफी बदनामी झेलनी पड़ी.

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

वर्मा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में

वर्ष 1976 बैच के आईएएस अधिकारी उदय वर्मा को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव बनाया गया है. वह इस पद पर रघु मेनन का स्थान लेंगे, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं.

किरण को मिला पंचायती राज

वर्ष 1975 बैच की आईएएस अधिकारी किरण धींगरा को पंचायती राज मंत्रालय में सचिव बनाया गया है. वह ए एन पी सिन्हा की जगह लेंगी, जिन्हें आधिकारिक भाषा मंत्रालय में सचिव बनाया गया है. धींगरा पहले आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में सचिव थीं.

जिंदल उपसचिव बनेंगी

वर्ष 1995 बैच की आईआईआरएस (आईटी) अधिकारी पूजा जिंदल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में उपसचिव बनाया जाएगा. वह रिचा श्रीवास्तव की जगह लेंगी.

सुलेखा बनीं निदेशक

वर्ष 1990 बैच की आईआरएस (आईटी) अधिकारी सुलेखा वर्मा को खेल विभाग में निदेशक बनाया जाएगा. वह प्रमोद अग्रवाल का स्थान लेंगी, जिन्हें विनिवेश विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है.

अजय होंगे संयुक्त सचिव

वर्ष 1986 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. अजय वी प्रसाद को संयुक्त सचिव बनाया जाएगा. उन्हें पेट्रो केमिकल विभाग में एस सी गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया जाएगा.

आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं

पृष्ठ एक का शेष

पार्टी अपने जीवनकाल के सबसे ख़राब दौर से गुज़र रही है. यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की बॉडी लैग्वेज बदल गई है. अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी, ऐसा विश्वास वाला चेहरा कुछ दिनों से फीका पड़ने लगा है. एक ने कहा कि पार्टी के लिए महामृत्युंजय यज्ञ करने की ज़रूरत है. ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता फिर से निराश हो गए हैं. अन्ना और रामदेव के आंदोलन से उनका मनोबल बढ़ा था, लेकिन जिस तरह आडवाणी ने प्रधानमंत्री बनने की जिद पाल रखी है, उससे पूरी पार्टी निराश और कुंठित हो गई है.

संघ ने आडवाणी जी के सामने शर्त रखी थी कि जनचेतना यात्रा शुरू करने से पहले उन्हें यह घोषणा करनी पड़ेगी कि वह यह यात्रा प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं कर रहे हैं. वह नागपुर गए और वहां संघ के पदाधिकारियों से मिलने के बाद गोलमटोल करके उन्होंने यह बयान दे दिया कि संघ ने उन्हें प्रधानमंत्री पद से ज़्यादा दे दिया है. जो बात कहनी थी, उन्होंने साफ़-साफ़ नहीं कही. वह पहला संकेत था कि आडवाणी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं. उनकी यात्रा शुरू हुई, लेकिन उनके रथ को कई शुरुआती झटके लगे. उन्होंने गुजरात से यात्रा शुरू करनी चाही, लेकिन मोदी ने नाराज़गी जता दी. मोदी भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं. उन्होंने भूख हड़ताल करके पूरे मीडिया को अपनी ओर खींच लिया. आडवाणी को अपनी रथ यात्रा बिहार से शुरू करनी पड़ी. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी राजनीतिक दुश्मन ही हैं, लेकिन आडवाणी ने मोदी को पटना की रैली से चिढ़ाया और कहा कि अगर सुशासन देखना है तो बिहार देखना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यह सुनकर सन्न रह गए कि आडवाणी जी ने यह क्या कह दिया. क्या गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों में सुशासन नहीं है. दरअसल, यात्रा के दूसरे दिन आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी को विभाजित कर दिया. पार्टी में जो लोग मोदी के समर्थक हैं, उन्हें संकेत मिल गया कि आडवाणी जी का मतलब क्या है. दुविधा में वे बड़े नेता हैं, जो तटस्थ दिखना चाहते हैं. इस बयान के पहले सुषमा स्वराज और अरुण जेटली भी आडवाणी के रथ पर थे. तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए दिल्ली लौट आए. लेकिन जैसे ही आडवाणी ने नीतीश के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी पर हमला बोला, अगले ही दिन सारे नेता वापस आडवाणी के साथ थे. प्रधानमंत्री पद के एक और दावेदार हैं पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह. योजना के मुताबिक़, उनकी यात्रा मथुरा से शुरू हुई. उमा भारती को राजनाथ सिंह के साथ रहना था, लेकिन वह आडवाणी के रथ पर जा कूदीं और उन्होंने ऐलान कर दिया कि आडवाणी जी ही भारतीय जनता पार्टी के सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं. यह सरासर पार्टी लाइन और आरएसएस की अवमानना है, इसलिए पार्टी प्रवक्ता शाम को टीवी पर यह कहते नज़र आए कि उमा भारती का यह व्यक्तिगत बयान है, पार्टी ने किसी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित नहीं किया है.

नरेंद्र मोदी ने अपना स्टैंड कड़ा कर लिया है. उन्हें लग रहा है कि वह पार्टी में अकेले पड़ गए हैं. उनके सबसे क़रीबी मित्र अरुण जेटली ने भी उनका साथ छोड़ दिया है. पार्टी में संजय भाई जोशी की वापसी को मोदी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. फिर आडवाणी की यात्रा और प्रधानमंत्री बनने की उनकी जिद की वजह से मोदी अकेले पड़ गए हैं. मोदी का बर्ताव भी एक कारण है, जिसकी वजह से संघ और भाजपा के नेता उनसे दूरी बनाए रखना चाहते हैं. मोदी के अलावा अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी और नितिन गडकरी भी इस दौड़ में शामिल हैं. सब एक से बढ़कर एक रणनीतिकार हैं, इसलिए यह समझना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन किसके साथ है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आडवाणी की रथ यात्रा को सफल बनाने में पूरी ताक़त लगा दी. पैसे भी बांटने का आरोप लगा, लेकिन हक़ीक़त यह है कि बिहार और मध्य प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों में अगर लोग आडवाणी की रथ यात्रा के साथ नहीं जुड़ते हैं तो इसका मतलब यही है कि चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा के विपरीत जाने वाले हैं.

आडवाणी जी को संघ ने अच्छी सलाह दी कि वह अब प्रधानमंत्री पद का मोह छोड़ दें, लेकिन जब पत्रकार उनसे इस बारे में सवाल पूछते हैं तो वह नाराज़ हो जाते हैं. आडवाणी जी देश के सबसे वरिष्ठ नेता हैं. उन्हें तो कम से कम यह समझना ही चाहिए कि अन्ना हजारे के साथ लोग इसलिए हैं, क्योंकि उनमें एक संत नज़र आता है. आडवाणी के व्यक्तित्व से वह संत ही ग़ायब हो चुका है. भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सबसे बड़ी गलती यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव और अलग- अलग रथयात्राओं से अटल बिहारी वाजपेयी ग़ायब हैं.

संघ ने अन्ना का सबसे बड़ा नुक़सान किया

पृष्ठ एक का शेष

अन्ना की टीम दिग्विजय सिंह के हमले को क़रारा जवाब दे रही थी, लेकिन मोहन भागवत का बयान आते ही वह डिफेंसिव हो गई. अन्ना हजारे को यह कहना पड़ा कि मैं ईश्वर को मानने वाला हूं और ईश्वर को साक्षी रखकर कहूंगा कि रामलीला मैदान में आरएसएस का एक भी कार्यकर्ता 12 दिनों में एक बार भी मुझे आकर नहीं मिला और न मेरे आंदोलन में दिखाई दिया. मोहन भागवत के बयान की वजह से अन्ना कमज़ोर पड़ गए और उन्होंने ख़ुद को सीमित दायरे में बांधने का मन बना लिया. एक बार फिर संपूर्ण क्रांति का दीप जलने से पहले ही बुझता दिख रहा है. इसका अर्थ यही निकलता है कि कांग्रेस की तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आंदोलन के ख़िलाफ़ है. मोहन भागवत ऐसा बयान देकर किसी बड़े भाई की भूमिका की ओर इशारा करना चाह रहे थे. वह यह बताना चाह रहे थे कि अन्ना के आंदोलन की सफलता के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन है. जबकि हक़ीक़त कुछ और है. संघ के पास अब न वह ताक़त है और न वैसे पूर्णकालिकों और कार्यकर्ताओं का समूह है, जो किसी आंदोलन को सफल बना सकते हैं. संघ परिवार अपनी ही समस्याओं में उलझा हुआ है. संघ परिवार के संगठनों के बीच आपसी मतभेद इतने ज़्यादा हैं, जितने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में नहीं हैं. एक उदाहरण देता हूं, हाल में ही टीवी के एक लोकप्रिय कार्यक्रम में बताया गया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन है. इस पर भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग इतने नाराज़ हो गए कि कोर्ट चले गए और उन्होंने चैनल से माफ़ी मांगने के लिए कहा. मोहन भागवत जानते हैं कि संघ के संगठनों में अब न तो ऊर्जा है और न उसे चलाने वाले कमिटेड लोग हैं. लगता है कि संघ की उपयोगिता और वर्चस्व कायम रखने के लिए मोहन भागवत ने ऐसा बयान दिया. मोहन भागवत के इस बयान से भ्रम फैल गया. उन्होंने न सिर्फ़ कांग्रेस को अन्ना के खिलाफ बोलने का मौक़ा दिया, बल्कि लोगों की नज़रों में संघ को भी कठघरे में खड़ा कर दिया.

मोहन भागवत के बयान ने तो यही साबित किया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा हमेशा छिपा हुआ रहता है. संघ जो भी कार्य करता है, वे खुले रूप में नहीं होते हैं. उसका काम पर्दे के पीछे होता है. भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर भी वह जनता के सामने आकर आंदोलन नहीं करता है. जबकि यह मुद्दा ऐसा है, जिससे पूरा देश त्रस्त है. जब अन्ना हजारे बिना संगठन, बिना कार्यकर्ताओं और बिना किसी राजनीतिक बैकअप के ऐतिहासिक आंदोलन कर सकते हैं तो संघ जैसा संगठन इससे भी बड़ा आंदोलन कर सकता था. इसलिए यह सवाल उठता है कि संघ ने ऐसा क्यों नहीं किया. क्या संघ ने अपनी साख खो दी है, क्या देश के कोने-कोने में फैले इस संगठन ने जनता का रुख़ समझने में गलती की या फिर जनता के सरोकारों से अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया है. मोहन भागवत के बयान को इसी संदर्भ में समझने की ज़रूरत है. रामदेव के आंदोलन पर रामलीला मैदान में पुलिसिया कार्रवाई के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आडवाणी को लोकसभा से इस्तीफ़ा देकर आंदोलन करने के लिए कहा था. आडवाणी ने संघ का सुझाव ठुकरा दिया. संघ ख़ुद को असहाय महसूस करने लगा. अगर संघ के नेताओं को अपने संगठन, पूर्णकालिकों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर भरोसा होता तो वे आडवाणी के बिना भी देश में आंदोलन छेड़ सकते थे. लोगों का समर्थन भी मिलता, लेकिन संघ ने ऐसा नहीं किया. जब अन्ना ने आंदोलन छेड़ा और पूरे देश में जनसैलाब उमड़ा, तब संघ के लोग हाथ मलते रह गए. आंदोलन ख़त्म हो गया तो मोहन भागवत ने इसका क्रेडिट लेने के लिए बयान दे दिया कि संघ का समर्थन है. इससे संघ को क्रेडिट तो नहीं मिला, उल्टा वह डिस्क्रेडिट हो गया. एक तरफ तो संघ की किरकिरी हुई, वहीं दूसरी तरफ अन्ना के सामने भी दुविधा की स्थिति खड़ी हो गई.

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

हक़ीक़त तो यह है कि अन्ना के आंदोलन में शामिल लोग आम लोग थे. वैसे लोग, जो राजनीति से घृणा करते हैं. ज़्यादातर लोग तो शायद यह भी नहीं जानते होंगे कि संघ के प्रमुख को क्या कहा जाता है. सरसंघचालक ने वही काम किया है, जो जेपी आंदोलन के दौरान हुआ. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविरों में यह बताया जाता है कि जेपी आंदोलन का संचालन संघ के लोग कर रहे थे. भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग जेपी आंदोलन का क्रेडिट लेने में कभी कोई चूक नहीं करते हैं. जेपी आंदोलन में भी संघ के कार्यकर्ता उसी तरह शामिल हुए थे, जैसे अन्ना के आंदोलन में शामिल हुए. संघ के ये कार्यकर्ता अपने विवेक, बुद्धि और देश के प्रति सद्भाव की वजह से शामिल हुए. मोहन भागवत की बातों को सही तब माना जाता, अगर रामलीला मैदान में शामिल होने वाले लोग सीधे संघ की शाखा से आते. अगर मोहन भागवत की बातों में सच्चाई है तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, संघ का संगठन नहीं है, वहां अन्ना का आंदोलन कौन चला रहा था. मोहन भागवत के बयान ने अन्ना का नुकसान तो किया ही, साथ ही भारतीय जनता पार्टी को भी नुक़सान पहुंचाया. हिसार के चुनाव के बाद अन्ना के आंदोलन का स्वरूप कांग्रेस विरोधी आंदोलन में बदल रहा था. अन्ना का समर्थन स्वत: भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में तब्दील हो रहा था, लेकिन मोहन भागवत के बयान ने सब कुछ उलट कर रख दिया. उत्तर प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अन्ना के आंदोलन का फ़ायदा अब पार्टी को मिलने की उम्मीद कम है. इसकी वजह यह है कि अन्ना के समर्थन में जो लोग सड़कों पर उतरे, वे राजनीतिक नहीं हैं. अन्ना के इशारे पर वह किसी भी पार्टी को वोट कर सकते हैं, लेकिन मोहन भागवत के बयान ने उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि भ्रष्टाचार हटाने की क़ीमत पर क्या देश में सांप्रदायिकता को मज़बूत किया जा सकता है. मोहन भागवत एक बयान देकर अन्ना के आंदोलन का श्रेय लेना चाह रहे थे, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला. कांग्रेस पार्टी की रणनीति कामयाब हो गई, अन्ना कमज़ोर हो गए और भारतीय जनता पार्टी हाथ मलती रह गई.

हर भारतीय को भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आंदोलन करने का अधिकार है. अन्ना सही हैं या गलत, यह फ़ैसला करने का अधिकार है. आज़ाद भारत के सबसे बड़े जनांदोलन पर छींटाकशी करने और भ्रम फैलाने का अधिकार न तो मोहन भागवत को दिया जा सकता है और न दिग्विजय सिंह को. ऐसे बयान देने का मतलब साफ़ है कि इन नेताओं को लोकमत पर विश्वास नहीं है, प्रजातंत्र पर भरोसा नहीं है. राजनीति में शामिल संगठनों को जनमत से डरना चाहिए. राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि अन्ना का आंदोलन आज़ादी के बाद का एक ऐसा पहला आंदोलन है, जिसे जनता का भरपूर समर्थन मिला, जिसे भारत के कोने-कोने में समर्थन मिला. इसमें शामिल होने वाले लोग पैसे देकर नहीं लाए गए थे, उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था नहीं हुई थी. अन्ना और उनकी टीम ने पैसे देकर अख़बारों में ख़बरें नहीं छपवाईं. जनता का समर्थन तभी मिलता है, जब नेतृत्व ईमानदार और अच्छा होता है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरे राजनीतिक दलों को अपने अंदर झांकना चाहिए और खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि उनके संगठन में अन्ना हजारे जैसा व्यक्ति क्यों नहीं है. जहां तक बात श्रेय लेने की है तो आज के दौर में लोग इतने जागरूक हैं कि जो संगठन, व्यक्ति अथवा नेता उनका समर्थन करेगा, उसे वे श्रेय अवश्य देंगे. सबसे बड़ी अदालत जनता की है.

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 33
दिल्ली, 24 अक्टूबर–30 अक्टूबर 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)

प्रबंध संपादक
श्रीनिवास गुप्ता (ठाकुर) (उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/011–23418962
0120–6450888, 0120–6452888
0120–6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120–4783999
+91 9266627366
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि के विवाद में सरकार जानबूझ कर ख़ुद को फंसाती जा रही है और धीरे-धीरे एक ऐसे विवाद में भागीदार बन गई है, जिसमें कोई तथ्य ही नहीं है.

जनरल वी के सिंह जन्म तिथि विवाद

टॉप सीक्रेट फाइल की कहानी क्या है

फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

शशि शेखर

थलसेना अध्यक्ष जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि पर सरकार किस तरीके से विवाद खड़ा कर रही है और तमाम हथकंडे अपना कर उन्हें ग़लत साबित करने पर तुली हुई है, इसका ख़ुलासा जब चौथी दुनिया ने किया, तब देश के मीडिया और ख़ासकर अंग्रेजी मीडिया से लेकर रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों तक ने एक बार फिर से इस विवाद को हवा देना शुरू कर दिया. जनरल वी के सिंह के ख़िलाफ़ सरकार, रक्षा मंत्रालय और वहां बैठे अधिकारी किस तरह साजिश रच रहे हैं, इसका बेहतरीन उदाहरण भारत के अटॉर्नी जनरल गुलाम ई वाहनवती की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने जन्मतिथि विवाद पर अपनी ओपिनियन दी है. फाइल संख्या एफटीएस नंबर 1293/एलएस/11/डेट 11/5/2011 में वह लिखते हैं, मैंने रक्षा मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी (जी एंड एआईआर) द्वारा 6 मई, 2011 को भेजे गए नोट और अन्य ज़रूरी नोट जैसे फाइल संख्या 23 (10)/2011, बी/एमएस नंबर 11 (9) 2007, जिसमें सभी संबंधित दस्तावेज हैं, को ध्यान से देखा. वाहनवती ने इस विवाद पर क्या ओपिनियन दी, सरकार ने इसके बारे में किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझा. पांच सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों ने भी वाहनवती की ओपिनियन को देखना और पढ़ना चाहा, लेकिन सरकार ने इस ओपिनियन को टॉप सीक्रेट बना दिया. चौथी दुनिया के

गुलाम ई वाहनवती की ओपिनियन उनके हस्ताक्षर के साथ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भेजी गई, जहां से 16 तारीख़ को ही उसे रक्षा मंत्रालय भेज दिया गया. रक्षा मंत्रालय पहुंचते ही यह ओपिनियन टॉप सीक्रेट घोषित कर दी जाती है. इस पर लिखा है, डिफेंस सेक्रेटरी ऑफिस, डायरी नंबर-6046+5 फोल्डर्स.., डेट-8 मई 2011, कन्वर्टेड टू टॉप सीक्रेट, नंबर-8/टीएस/डिफे.सेक्रेटरी/2011.

पास रक्षा मंत्रालय की यह टॉप सीक्रेट फाइल मौजूद है. 16 मई, 2011 को गुलाम ई वाहनवती की ओपिनियन उनके हस्ताक्षर के साथ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भेजी गई, जहां से 16 तारीख़ को ही उसे रक्षा मंत्रालय भेज दिया गया. रक्षा मंत्रालय पहुंचते ही यह ओपिनियन टॉप सीक्रेट घोषित कर दी जाती है. इस पर लिखा है, डिफेंस सेक्रेटरी ऑफिस, डायरी नंबर-6046+5 फोल्डर्स.., डेट-8 मई 2011, कन्वर्टेड टू टॉप सीक्रेट, नंबर-48/टीएस/डिफे.सेक्रेटरी/2011. इसके बाद इस रिपोर्ट (ओपिनियन) पर रक्षा सचिव प्रदीप कुमार ने अपने नोट में 18 मई को लिखा कि कृपया रक्षा मंत्री इस ओपिनियन पर ध्यान दें. इसके बाद 19 मई को इस ओपिनियन पर रक्षा मंत्री अपना नोट लिखते हैं कि इस ओपिनियन को प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा जा सकता है.

इस ओपिनियन को टॉप सीक्रेट घोषित करने के बाद सरकार के एक महत्वपूर्ण अधिकारी ने किसी एक आदमी से कहा कि आप आरटीआई का इस्तेमाल करें, हम आपको यह फाइल उपलब्ध करा देंगे. किसी ने आरटीआई डाली और अंत में टॉप सीक्रेट घोषित हो चुकी यह फाइल सार्वजनिक कर दी गई. अब सवाल उठता है कि यह टॉप सीक्रेट फाइल रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने आरटीआई के तहत किसी को कैसे दे दी? क़ानूनन ऐसा नहीं किया जा सकता था और फिर ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी टॉप सीक्रेट दस्तावेज को आरटीआई के तहत नहीं दिया जाता. ज़ाहिर है, इन अधिकारियों ने क़ानून तोड़ने का काम किया है और वाहनवती की ओपिनियन को सार्वजनिक करने के पीछे उनका अपना इंटरेस्ट काम कर रहा था. ध्यान देने की बात है कि अपनी ओपिनियन में अटॉर्नी जनरल वाहनवती ने बताया है कि जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि में संशोधन तर्कसंगत नहीं होगा और इस स्टेज पर इस मुद्दे को किसी भी आधार पर फिर से नहीं खोला जा सकता है. जबकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस जे एस वर्मा, चीफ जस्टिस जी वी पटनायक, चीफ जस्टिस वी एन खरे ने जनरल वी के सिंह की जन्म तिथि पर अपनी राय देते हुए उनकी असल जन्मतिथि 10 मई, 1951 ही मानी थी. जबकि सरकार चाहती है कि जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि 10 मई, 1950 मानी जाए, ताकि वह अपनी पसंद का नया सेनाध्यक्ष नियुक्त कर सके. ज़ाहिर है, टॉप सीक्रेट दस्तावेज को सार्वजनिक करके रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने क़ानून का उल्लंघन किया है. साथ ही नेचुरल लॉ को भी ग़लत साबित करने का अपराध किया है. नेचुरल लॉ यह कहता है कि जन्मतिथि वही सही है, जो किसी के जन्म के समय दर्ज की गई हो या हाईस्कूल के सर्टिफिकेट में दर्ज हो.

शुरू में जब चौथी दुनिया ने जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि के विवाद से जुड़ी सच्चाई और असली जन्मतिथि के बारे में पड़ताल शुरू की तो उससे साबित हुआ कि इस पूरे मामले में सरकार जनरल को निशाना बना रही है और सच्चाई की अनदेखी कर रही है. चौथी दुनिया ने जब इस सरकारी घपलेबाज़ी को छापना शुरू किया, तब कुछ मीडिया वाले सरकार से मिल गए और पूरे माहौल को जनरल के ख़िलाफ़ बनाने की कोशिश में जुट गए. देश की एक महत्वपूर्ण और अपनी पसंदीदा न्यूज एजेंसी (पीटीआई) के एक वरिष्ठ संवाददाता से रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि जैसे हम बता रहे हैं, वैसे आरटीआई डालो. सेलेक्टिव सब्जेक्ट पर आरटीआई डाली गई और ऐसी-ऐसी ख़बरें निकाली गईं, जिनसे जन्मतिथि विवाद पर नेचुरल लॉ की उपेक्षा हुई. इंडिया टुडे पत्रिका ने भी सितंबर के अंक में लाइज ऑफ द जनरल के नाम से लेख छापा. दावा किया गया कि आरटीआई से मिले दस्तावेज के आधार

टॉप सीक्रेट फाइल रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने आरटीआई के तहत किसी को कैसे दे दी? क़ानूनन ऐसा नहीं किया जा सकता था और फिर ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी टॉप सीक्रेट दस्तावेज को आरटीआई के तहत नहीं दिया जाता. ज़ाहिर है, इन अधिकारियों ने क़ानून तोड़ने का काम किया है.

पर यह लेख लिखा गया है, लेकिन चौथी दुनिया इस विवाद से जुड़ी सच्चाई को प्रमुखता से सामने लाता रहा. इसके बाद कई वरिष्ठ पत्रकार आगे आए. मेल टुडे के संपादक भारत भूषण ने अपनी संपादकीय और लेखों के ज़रिए इस मुद्दे पर एक स्टैंड लिया और सरकार के उस तर्क को ख़ारिज़ कर दिया, जिसमें कहा गया था कि जन्मतिथि में बदलाव से नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति पर असर पड़ेगा. आउटलुक पत्रिका ने भी रिटायर्ड मेजर जनरल जी डी बख्शी के लेख को प्रमुखता से छापा. इसमें जी डी बख्शी सरकार पर सवाल उठाते हुए लिखते हैं कि ऐसी हालत में, जबकि करोड़ों की आर्म्स डील पेंडिंग है, तिब्बत में चीन अपनी सैन्य ताक़त बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, रक्षा मंत्रालय जनरल वी के सिंह को निशाना बना रहा है. पूर्व मिलिट्री इंटेलिजेंस अधिकारी एवं इंडियन डिफेंस रिव्यू के एसोसिएट एडिटर आर एस एन सिंह ने भी कई पत्रिकाओं में इस मुद्दे पर अपने विचार रखे. फर्स्ट पोस्ट में प्रकाशित एक लेख में वह सरकार और मीडिया के कुछ हिस्से द्वारा भारतीय थलसेना को राजनीति का शिकार बनाने का आरोप लगाते हैं.

दरअसल, जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि के विवाद में सरकार जानबूझ कर ख़ुद को फंसाती जा रही है और धीरे-धीरे एक ऐसे विवाद में भागीदार बन गई है, जिसमें कोई तथ्य ही नहीं है. चौथी दुनिया की पड़ताल बताती है कि जनरल की जन्मतिथि 10 मई, 1951 है. ऐसा जनरल वी के सिंह के हाईस्कूल सर्टिफिकेट से लेकर सेना के एडजुटेंट जनरल ब्रांच के पास उपलब्ध जनरल से जुड़े सभी दस्तावेजों में दर्ज है. एजी ब्रांच ही सेना के अधिकारियों से जुड़े दस्तावेजों की कस्टोडियन होती है. बहरहाल, सरकार इस देश की बाकी संस्थाओं के साथ जो रवैया अपनाती है, वही वह भारत की थलसेना के साथ अपना रही है. सरकार वर्तमान थल सेनाध्यक्ष जनरल वी के सिंह के खिलाफ जिस साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रही है, उससे एक गलत संदेश तो सेना को मिल ही रहा है, साथ ही सेना में इस चीज को लेकर रोष भी है. जरूरत इस बात की है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के पांच पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की राय को महत्व देते हुए इस विवाद को शीघ्र समाप्त करने की कोशिश करे.

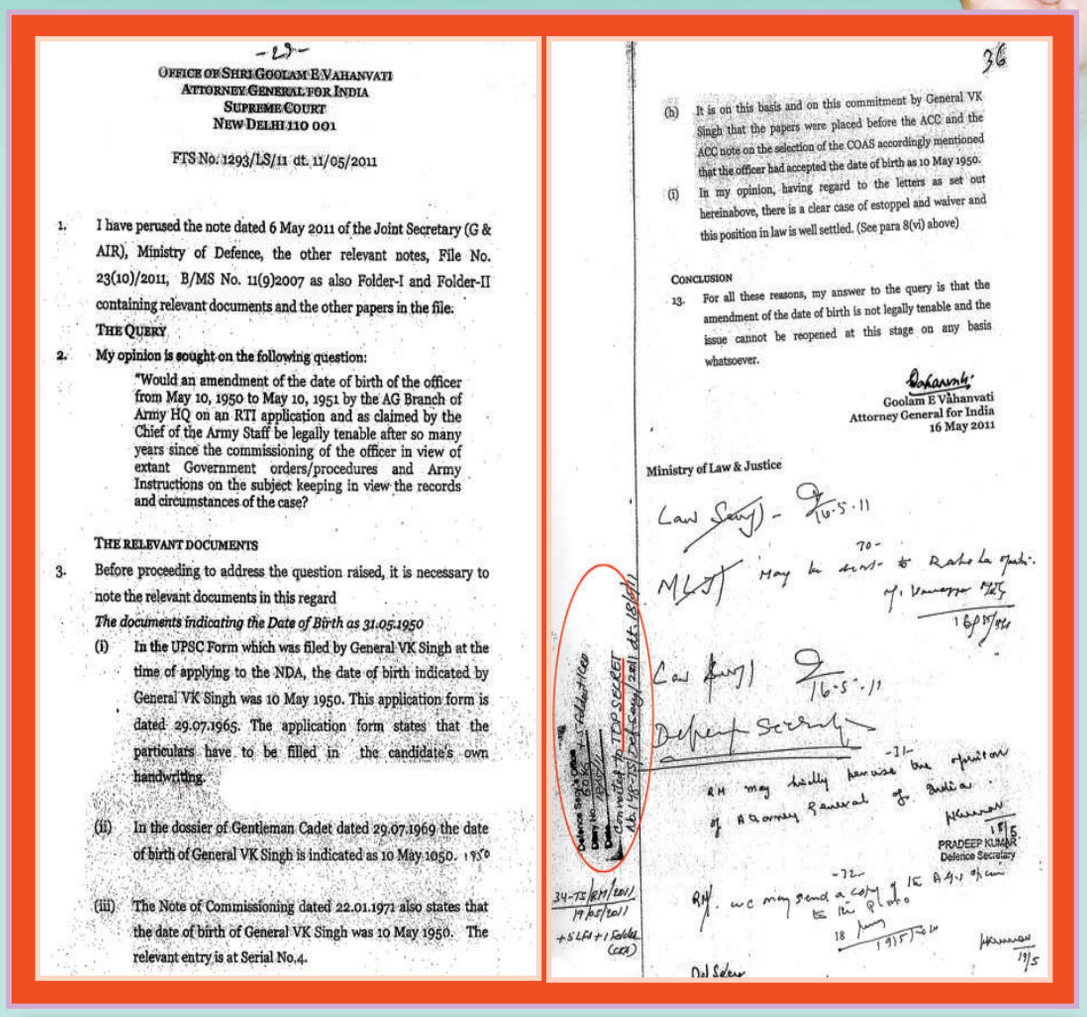

shashishekhar@chauthiduniya.com

-29-

OFFICE OF SHRI GOOLAM E VAHANVATI
ATTORNEY GENERAL FOR INDIA
SUPREME COURT
NEW DELHI 110 001

FTS No. 1293/LS/11 dt. 11/05/2011

1. I have perused the note dated 6 May 2011 of the Joint Secretary (G & AIR), Ministry of Defence, the other relevant notes, File No. 23(10)/2011, B/MS No. 11(9)2007 as also Folder-I and Folder-II containing relevant documents and the other papers in the file.

THE QUERY

2. My opinion is sought on the following question:

"Would an amendment of the date of birth of the officer from May 10, 1950 to May 10, 1951 by the AG Branch of Army HQ on an RTI application and as claimed by the Chief of the Army Staff be legally tenable after so many years since the commissioning of the officer in view of extant Government orders/procedures and Army Instructions on the subject keeping in view the records and circumstances of the case?

THE RELEVANT DOCUMENTS

3. Before proceeding to address the question raised, it is necessary to note the relevant documents in this regard

The documents indicating the Date of Birth as 31.05.1950

(i) In the UPSC Form which was filed by General VK Singh at the time of applying to the NDA, the date of birth indicated by General VK Singh was 10 May 1950. This application form is dated 29.07.1965. The application form states that the particulars have to be filled in the candidate's own handwriting.

(ii) In the dossier of Gentleman Cadet dated 29.07.1969 the date of birth of General VK Singh is indicated as 10 May 1950. 1950

(iii) The Note of Commissioning dated 22.01.1971 also states that the date of birth of General VK Singh was 10 May 1950. The relevant entry is at Serial No.4.

36

(h) It is on this basis and on this commitment by General VK Singh that the papers were placed before the ACC and the ACC note on the selection of the COAS accordingly mentioned that the officer had accepted the date of birth as 10 May 1950.

(i) In my opinion, having regard to the letters as set out hereinabove, there is a clear case of estoppel and waiver and this position in law is well settled. (See para 8(vi) above)

CONCLUSION

13. For all these reasons, my answer to the query is that the amendment of the date of birth is not legally tenable and the issue cannot be reopened at this stage on any basis whatsoever.

Goolam E Vahanvati
Attorney General for India
16 May 2011

Ministry of Law & Justice

Converted to TOP SECRET

PRADEEP KUMAR
Defence Secretary

क्या है पूरा मामला

चौथी दुनिया ने पड़ताल के बाद यह बताया था कि जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि का विवाद जनरल जे जे सिंह और जनरल दीपक कपूर ने जानबूझ कर पैदा किया. 2006 की बात है. जनरल जे जे सिंह को मालूम था कि जन्मतिथि 10 मई, 1950 हो या 10 मई, 1951, जनरल वी के सिंह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो बनेंगे ही, लेकिन जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि अगर 10 मई, 1951 रह जाती है तो लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन पाएंगे. हां, लेफ्टिनेंट जनरल के टी परनायक नए सेनाध्यक्ष बन जाएंगे. इसलिए जनरल जे जे सिंह ने लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह को देश का थल सेनाध्यक्ष बनाने की बिसात 2006 में बिछा दी. वी के सिंह की जन्मतिथि सभी सबूतों के अनुसार 10 मई, 1951 है. उनकी जन्मतिथि पर जल्दबाज़ी में फ़ैसला इसलिए लिया गया, क्योंकि चौथी दुनिया ने यह सारी कहानी छाप दी थी. यह फ़ैसला इसलिए भी लिया गया, ताकि एक ईमानदार जनरल को जल्द से जल्द उसके पद से हटाया जा सके, साथ ही एक ईमानदार और बेदाग़ लेफ्टिनेंट जनरल को नया सेनाध्यक्ष बनने से रोका जा सके. ज़ाहिर है, इस फ़ैसले के पीछे अंतरराष्ट्रीय हथियार माफिया भी हो सकता है, जिसे ईमानदार सैन्य अधिकारियों से नुकसान पहुंचता है. नतीजतन, दबाव बनाने की बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है, जिसमें मीडिया और डिफेंस जर्नलिस्ट भी शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह पूछा कि क्या भारत के थल सेनाध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह की बहू यानी दुबई में काम करने वाले उनके बेटे की पत्नी पाकिस्तान की नागरिक है? अंबिका बनर्जी ने अपने खत के ज़रिए प्रधानमंत्री को यह भी बताया कि कश्मीर में कैसे दुकानों के आवंटन में धांधली हुई और कैसे लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह उस मामले में शामिल थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस खत का जवाब नहीं दिया. अंग्रेजी के एक मशहूर साप्ताहिक ने रिपोर्ट छापी है कि जब यह कांगो में भारतीय शांति सेना के चीफ थे तो वहां रहे कुछ सिपाहियों और अफसरों पर यौन शोषण का आरोप लगा था, जिसकी जांच भारतीय सेना कर रही है. इसके अलावा जब बिल क्लिंटन राष्ट्रपति के रूप में भारत आए तो कश्मीर के छत्तीसिंह पुरा में सिखों की हत्याएं हुई थीं. जांच में पता चला कि इसमें काफ़ी संदेह है कि ये हत्याएं आतंकवादियों ने की हैं. जब जांच की बात आई, तब आरोपियों को बचाने और इस मामले की अनदेखी का आरोप भी लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह पर ही लगा. सवाल यह उठता है कि आख़िर ऐसी कौन सी वजह है कि इतने गंभीर आरोपों में घिरे होने के बाद भी लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह को प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भावी सेनाध्यक्ष बनाना चाहते हैं?

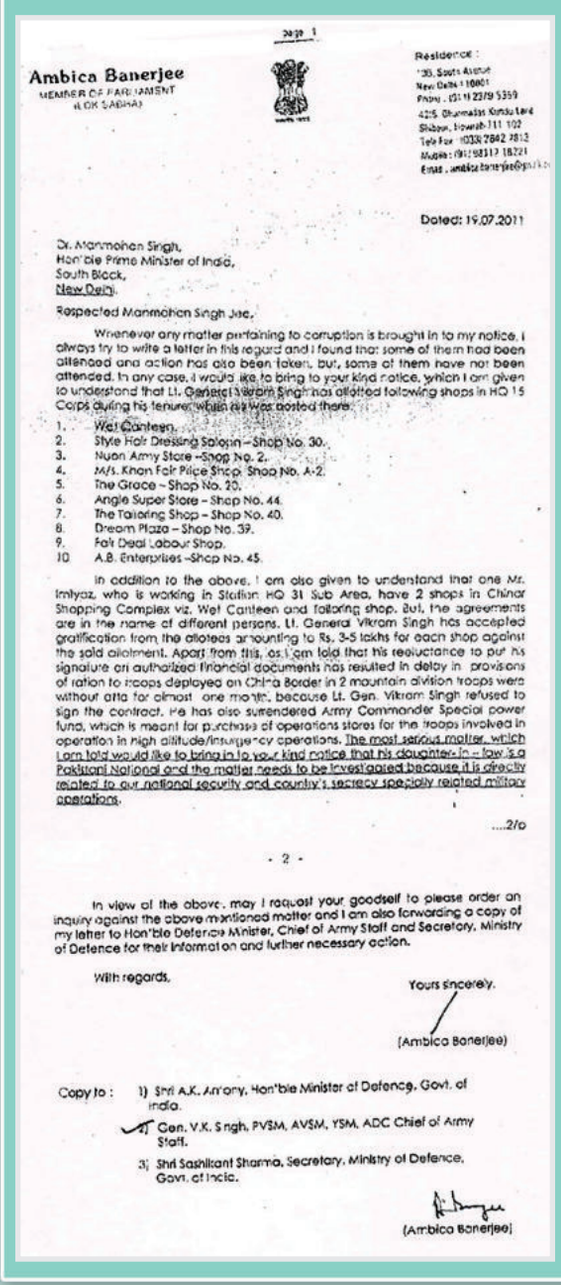

Page 1

Ambica Banerjee
MEMBER OF PARLIAMENT
(LOK SABHA)

Dated: 19.07.2011

Dr. Manmohan Singh,
Hon'ble Prime Minister of India,
South Block,
New Delhi.

Respected Manmohan Singh Jee,

Whenever any matter pertaining to corruption is brought in to my notice, I always try to write a letter in this regard and I found that some of them had been attended and action has also been taken, but, some of them have not been attended. In any case, I would like to bring to your kind notice, which I am given to understand that Lt. General Vikram Singh has allotted following shops in HQ 15 Corps during his tenure when he was posted there.

1. Wet Canteen.
2. Style Hair Dressing Saloon – Shop No. 30.
3. Nuon Army Store – Shop No. 2.
4. M/s. Khan Fair Price Shop, Shop No. A-2.
5. The Grace – Shop No. 20.
6. Angle Super Store – Shop No. 44.
7. The Tailoring Shop – Shop No. 40.
8. Dream Plaza – Shop No. 39.
9. Fair Deal Labour Shop.
10. A.B. Enterprises – Shop No. 45.

In addition to the above, I am also given to understand that one Mr. Imtyaz, who is working in Station HQ 31 Sub Area, have 2 shops in Chinar Shopping Complex viz. Wet Canteen and Tailoring shop. But, the agreements are in the name of different persons. Lt. General Vikram Singh has accepted gratification from the allotees amounting to Rs. 3-5 lakhs for each shop against the said allotment. Apart from this, as I am told that his reluctance to put his signature on authorized financial documents has resulted in delay in provisions of ration to troops deployed on China Border in 2 mountain division troops were without atta for almost one month, because Lt. Gen. Vikram Singh refused to sign the contract. He has also surrendered Army Commander Special power fund, which is meant for purchase of operations stores for the troops involved in operation in high altitude/insurgency operations. The most serious matter, which I am told would like to bring in to your kind notice that his daughter-in-law is a Pakistani National and the matter needs to be investigated because it is directly related to our national security and country's secrecy specially related military operations.

....2/o

- 2 -

In view of the above, may I request your goodself to please order an inquiry against the above mentioned matter and I am also forwarding a copy of my letter to Hon'ble Defence Minister, Chief of Army Staff and Secretary, Ministry of Defence for their information and further necessary action.

With regards,

Yours sincerely,

(Ambica Banerjee)

Copy to:
1) Shri A.K. Antony, Hon'ble Minister of Defence, Govt. of India.
2) Gen. V.K. Singh, PVSM, AVSM, YSM, ADC Chief of Army Staff.
3) Shri Sashikant Sharma, Secretary, Ministry of Defence, Govt. of India.

(Ambica Banerjee)

मुझे लगता है कि यात्राएं बहुत होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन हमारी यात्रा समाज के उस अंतिम व्यक्ति के लिए है, जिसे पिछले 65 सालों में अपना अधिकार नहीं मिला है.

जन संवाद यात्रा

अब गांधी और मार्क्स नहीं, ज़मीन चाहिए

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

इस वक़्त देश में यात्राओं का दौर चल रहा है. मुद्दे तमाम हैं, भ्रष्टाचार से लेकर राजनीति तक, लेकिन इसमें समाज का वह अंतिम व्यक्ति कहां है जिसके उत्थान के लिए गांधी जी ने इस देश को एक ताबीज दिया था? जल, जंगल और ज़मीन पर वंचितों के अधिकार को लेकर शुरू की गई जन संवाद यात्रा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर एकता परिषद के पी वी राजगोपाल से चौथी दुनिया के संवाददाता शशि शेखर ने विस्तार से बातचीत की. प्रस्तुत हैं मुख्य अंश:

यह देशव्यापी यात्रा शुरू करने के पीछे क्या मक़सद है, इससे आप क्या परिणाम निकालना चाहते हैं?

हम एक समग्र भूमि सुधार नीति चाहते हैं. भूमि सुधार का जो मामला है, वह अभी बीच में अटक गया है. तमाम भूमि कहीं सेज के नाम पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, कहीं अधिग्रहण के नाम पर बड़े-बड़े लोगों को दी जा रही है और गरीबों को भूमि देने का जो वादा है, उससे सरकार पीछे हट रही है. ग़रीबों से कहा जा रहा है कि अब भूमि नहीं है बांटने के लिए. सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है. हज़ारों-लाखों एकड़ ज़मीन माइनिंग कंपनियों को दी जा रही है. भूमि सुधार को लेकर सरकार जो लापरवाही बरत रही है, उससे ग़रीबी बढ़ रही है, लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं और हिंसा बढ़ रही है. यह सब समाप्त करने के लिए हम चाहते हैं कि सरकार ग़रीबों के पक्ष में समग्र रूप से एक भूमि सुधार नीति लाए.

देश में कई लोग यात्रा शुरू कर चुके हैं और करने वाले हैं, जैसे आडवाणी, रामदेव, अन्ना हजारे. इनकी यात्रा से आपकी यात्रा किन मायनों में अलग है?

आज़ादी के समय गांधी जी ने इस देश को एक ताबीज दिया था. उसका अर्थ था कि जो कुछ भी करो, उसमें समाज के अंतिम व्यक्ति को नज़र में रखो. मुझे लगता है कि यात्राएं बहुत होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन हमारी यात्रा समाज के उस अंतिम व्यक्ति के लिए है, जिसे पिछले 65 सालों में अपना अधिकार नहीं मिला है, न्याय नहीं मिला है. लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है. अभी तक मैं जहां-जहां घूमा, वहां लोग न गांधी सुनना चाहते हैं और न मार्क्स. वे कहते हैं कि इस नाम पर बात करके हमारे साथ बहुत धोखाधड़ी हुई. हमें चाहिए न्याय, हमें चाहिए ज़मीन. हमारा यह आंदोलन, यह यात्रा समाज के उसी अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए है.

यानी अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने का मुद्दा ही इस यात्रा को अन्य यात्राओं से अलग करता है...

कुर्सी और अन्य मुद्दों के लिए रैलियां और यात्राएं होती रही हैं और अब तो भ्रष्टाचार को लेकर भी आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले, इसे भी लेकर आवाज़ उठनी चाहिए इस देश में. यह नहीं हो पा रहा था. मुझे पैसा (रिश्वत) न देनी पड़े, यह तो अच्छी बात है, लेकिन मैं अगर सुख-संपन्नता से जीता हूं तो दूसरों को भी, पीछे छूटे हुए लोगों को भी कुछ मिलना चाहिए. इसके लिए हमने एक आंदोलन की ज़रूरत को महसूस किया, इसीलिए हमने इसे शुरू किया.

अन्य लोग जो अपनी यात्राएं शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं, क्या उनमें से किसी ने आपसे संपर्क किया? इस मुद्दे पर उनसे आपकी कोई बातचीत हुई?

मैंने सभी से बात की. मैंने अन्ना को चिट्ठी लिखी कि भ्रष्टाचार के विरोध में जो लड़ाई है, उसका अगला भाग यही है. जल, जंगल और ज़मीन में आम लोगों को भी उनका हिस्सा मिलना चाहिए. उस समय अन्ना हजारे सहमत भी थे कि यह सिर्फ़ भ्रष्टाचार का मामला नहीं है. ग़रीब लोगों का मुद्दा भी सक्रियता से उठाना चाहिए. इस विषय पर बाबा रामदेव से भी मेरी बात हुई. उन्होंने आर्थिक क्रांति पर जो किताब लिखी है, उसमें भी वह मानते हैं कि जल, जंगल और ज़मीन का मुद्दा उठना चाहिए. इस देश को राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन सामाजिक-आर्थिक आजादी अभी भी नहीं मिली है. हमारा यह आंदोलन उसी सामाजिक-आर्थिक आज़ादी के लिए है.

जब अन्ना हजारे और रामदेव आपके मुद्दों का समर्थन कर रहे हैं तो क्या वे आपकी इस यात्रा में भी शामिल होंगे?

अन्ना के आंदोलन का पहला चरण ख़त्म होने के बाद एक चर्चा हुई थी कि भ्रष्टाचार के इस आंदोलन को और व्यापक बनाना है. इसमें जल, जंगल और ज़मीन का मुद्दा भी जोड़ना है. इस पर एक एग्रीमेंट हुआ था. मुझे लगता है कि थ्योरिटकली सब एक साथ हैं, लेकिन वे लोग दिसंबर तक भ्रष्टाचार (जन लोकपाल) के मुद्दे पर ही जोर देना चाहते हैं. जबकि मैं मानता हूं कि जल, जंगल और ज़मीन का मुद्दा इस आंदोलन की वजह से शिथिल न हो. दिसंबर में जब बिल पारित होगा, तब शायद अन्ना के पास इस आंदोलन से जुड़ने का समय होगा.

एकता परिषद के लोग कई बार दिल्ली आकर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं. क्या वजह है कि सरकार ने अब तक आपकी मांगें नहीं मानी?

अभी जैसे ही हमने 2 अक्टूबर को अपनी यात्रा शुरू की, वैसे ही प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठी आ गई कि 28 अक्टूबर को नेशनल लैंड रिफॉर्म्स काउंसिल की बैठक बुलाई जा रही है. मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय तीन साल से सोया हुआ था, वह एक लाख लोगों के साथ दिल्ली आने की हमारी घोषणा पर अमल होते देखकर जाग गया है. मार्च में जब मैं अन्ना हजारे के साथ प्रधानमंत्री से मिला था तो मैंने उन्हें याद दिलाया था कि अगर आप नेशनल लैंड रिफॉर्म्स काउंसिल की बैठक नहीं बुलाएंगे तो हमारे पास आंदोलन तेज़ करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा. हालांकि उसके बाद एंटी करप्शन मूवमेंट (अन्ना आंदोलन) ने पूरे माहौल को अपने हाथ में ले लिया था. मुझे लगता है कि अब वह जल्दी-जल्दी कुछ करेंगे.

इस यात्रा के ज़रिए आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं?

हमें एक कंप्रेहेंसिव लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसी तो चाहिए ही चाहिए. आप यह कहकर टाल नहीं सकते कि ज़मीन स्टेट का सब्जेक्ट है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण क़ानून और सेज क़ानून आपके हैं. केंद्रीय क़ानूनों से आप ज़मीनें हड़प रहे हैं. हम कह रहे हैं कि आप एक पॉलिसी बनाओ. यह मालूम करो कि कितनी ज़मीन है, किस विभाग को कितनी ज़मीन देनी है और ग़रीबी उन्मूलन के लिए कितनी ज़मीन उपलब्ध कराई जाए. सरकार ताक़तवर लोगों को ज़मीन देने और उनकी ज़मीन बचाने में जो ताक़त लगा रही है, उसमें से अगर वह दस प्रतिशत भी ताक़त इधर लगा दे तो ग़रीबों को ज़मीन मिल सकती है.

shashishekhar@chauthiduniya.com

तेलंगाना राज्य के नाम पर सियासत

राजीव कुमार

नए राज्य बनाने के लिए देश में अब तक कई आंदोलन हो चुके हैं. अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि इससे स्थानीय लोगों का विकास होगा और कानून व्यवस्था में सुधार भी. कभी सांस्कृतिक एकता की बात की जाती है तो कभी भाषाई एकता की. भाषा के ही नाम पर भारत में राज्यों का गठन हुआ है, लेकिन क्या ये तर्क सही हैं? इतिहास पर नज़र डालें तो इन तर्कों पर विश्वास करने की कोई वजह नहीं मिलती. नए राज्य के गठन से न विकास की गति तेज होती है और न क़ानून व्यवस्था में सुधार. केवल कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होती है. राज्य या देश के विभाजन से जनता को कोई लाभ नहीं होता, केवल नेताओं को अपनी राजनीति चमकाने और महत्वपूर्ण पद पाने का मौक़ा मिल जाता है. भारत के विभाजन का कारण भी यही था और राज्यों को विभाजित कर नए राज्य बनाने की वजह भी यही रही है. आंध्र प्रदेश में तेलंगाना को राज्य बनाने के लिए जो आंदोलन हो रहा है, उसके पीछे भी केवल कोरी राजनीति है. विभिन्न राजनीतिक दल और राजनेता अपने फायदे के लिए इसका समर्थन कर रहे हैं या फिर विरोध. कांग्रेस को छोड़कर लगभग सभी राजनीतिक दलों ने तेलंगाना को अलग राज्य बनाने का समर्थन किया है. ऐसा नहीं है कि उक्त राजनीतिक दलों को क्षेत्र विशेष के विकास की फ़िक्र है, बल्कि इस समर्थन के पीछे कारण कुछ और हैं.

तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) की स्थापना ही इसी मुद्दे पर की गई थी. समिति के नेता चंद्रशेखर राव को उम्मीद है कि नए राज्य के गठन के बाद मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना पूरा हो जाएगा. 2009 के विधानसभा चुनाव में टीआरएस को 16 सीटों का नुक़सान हुआ. इसलिए उसे तेलंगाना का मुद्दा फिर से उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा. राव ने इसके लिए दिन-रात एक कर रखा है. उन्होंने डी श्रीरमालू का अनुकरण करते हुए अनशन भी किया, जिसके बाद तेलंगाना को अलग राज्य बनाने की बात औपचारिक तौर पर मान भी ली गई. इसके लिए जस्टिस श्रीकृष्ण के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन राज्य बनने की नौबत अभी तक नहीं आई. तेलुगूदेशम पार्टी भी तेलंगाना की मांग का समर्थन कर रही है. तेलंगाना क्षेत्र के अपने सांसदों एवं विधायकों के दबाव में उसे यह समर्थन करना पड़ा. जब इन लोगों ने इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया तो चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वह तेलंगाना राज्य बनने का समर्थन करेंगे. चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन इसलिए किया, क्योंकि कांग्रेस का कहना था कि आंध्र प्रदेश की विपक्षी पार्टियां तेलंगाना का समर्थन नहीं कर रही हैं. दरअसल बात यह है कि कोई भी पार्टी गेंद अपने पाले में नहीं रखना चाहती, सभी लोग दूसरे के कंधे पर बंदूक़ रखकर फायर करना चाहते हैं. नायडू भी अपनी स्थिति कमज़ोर नहीं करना चाहते और कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं. यही हालत भारतीय जनता पार्टी की है. उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि पाने के लिए बहुत कुछ है. आंध्र प्रदेश विधानसभा में उसके दो सदस्य हैं. अगर भाजपा तेलंगाना राज्य का समर्थन करती है तो उसे उम्मीद है कि नए राज्य में उसकी स्थिति अभी से बेहतर होगी. भाजपा को ऐसे मौकों का लाभ पहले भी मिल चुका है. झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के गठन के बाद वहां भाजपा को लाभ हुआ. वर्तमान में तीनों राज्यों में उसकी सरकार है. भाजपा तेलंगाना में भी यही दांव आजमाना चाहती है. अगर आज केंद्र में उसकी सरकार होती तो तेलंगाना राज्य बन गया होता. कांग्रेस के लिए स्थिति अलग है. आंध्र प्रदेश और केंद्र मेंउसकी सरकार है. हालांकि कांग्रेस को आंध्र प्रदेश में कुछ सीटों का नुक़सान हुआ है, लेकिन सरकार बनाने के लिए ज़रूरी बहुमत उसके पास है. कांग्रेस की सफलता में मुख्य भूमिका निभाने वाले राजशेखर रेड्डी भी अब नहीं हैं. इसके अलावा उनके निधन के बाद मुख्यमंत्री पद के मुद्दे पर कांग्रेस में काफी उठापटक हुई. अंतत: उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया.

अभी यहां कांग्रेस को एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में अगर वह तेलंगाना की मांग मान लेती है तो उसे दोनों राज्यों में नुक़सान हो सकता है. आंध्र प्रदेश के लोग राज्य विभाजन के विरुद्ध हैं. जगन मोहन भी कांग्रेस के ख़िलाफ़ मोर्चा खोले हुए हैं. ऐसे में तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा देने से आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर हो सकती है. दूसरी तरफ वह इस बात को जानती है कि तेलंगाना बनने के बाद उसका श्रेय टीआरएस को मिलेगा, क्योंकि उसी ने इसके लिए आंदोलन किया. यही वजह है कि कांग्रेस इसे टालने की कोशिश कर रही है. हालांकि सभी पार्टियों के नेता जो तेलंगाना क्षेत्र के हैं, नए राज्य के गठन का समर्थन कर रहे हैं. कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी इस्तीफ़ा दिया. उन्हें पता है कि तेलंगाना के विरोध का मतलब है अपने भविष्य को अधर में लटकाना. चाहे राज्य बने या न बने, चुनाव तो होंगे ही और तब यह मुद्दा ज़ोर-शोर से उठेगा. यही कारण है कि तेलंगाना क्षेत्र के नेता पार्टी के बजाय अपना भविष्य सुरक्षित करना चाह रहे हैं. तेलंगाना हो या कोई अन्य राज्य बनाने का मुद्दा, सभी राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं. एक दशक बीत गया तीन नए राज्यों का गठन हुए, लेकिन अभी तक वहां कोई सकारात्मक परिवर्तन होता नहीं दिखा. इन नवगठित राज्यों की कानून व्यवस्था का हाल किसी से छिपा नहीं है. झारखंड और छत्तीसगढ़ में क़ानून व्यवस्था में गिरावट आई है. उत्तराखंड की स्थिति भी अच्छी नहीं है. अगर विकास होता तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी इतने सक्रिय नहीं होते. फायदा तो केवल नेताओं को होता है. मधु कोड़ा जैसे लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं. छोटे राज्यों को विकास का पर्याय नहीं कहा जा सकता. विकास के लिए चाहिए राज्य-राष्ट्र के प्रति निष्ठावान जनता और ईमानदार नेतृत्व, न कि आंदोलन. तेलंगाना आंदोलन के चलते प्रतिदिन 25-30 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. इसी धन से वहां स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोले जा सकते थे, जिनका फायदा आम जनता को होता, लेकिन यह चिंता किसे है? राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने नेताओं की आंखों पर पट्टी बांध दी है. अब जनता को फ़ैसला करना है. आंदोलन करना है, लेकिन विकास के लिए.

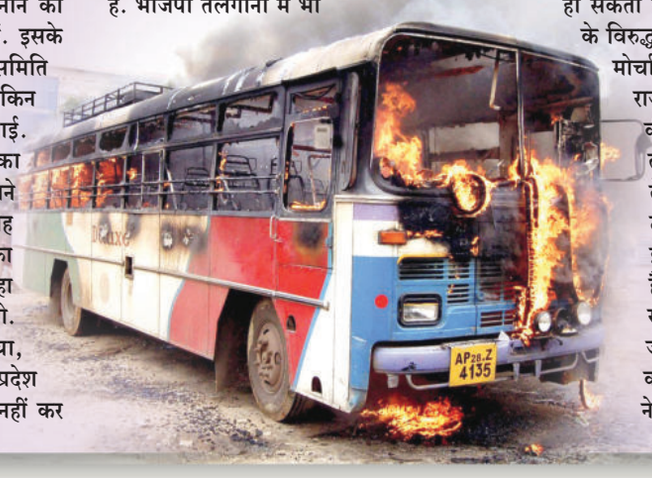

feedback@chauthiduniya.com

इंडियन ऑडिट एंड एकाउंट डिपार्टमेंट ने भी ऐसी कई रिपोर्ट्स प्रकाशित करके इन कमियों की ओर इशारा किया है, जिन पर क़ानून व्यवस्था से जुड़ी संस्थाओं को ध्यान देने की ज़रूरत है.

पूरा देश अव्यवस्था का शिकार है

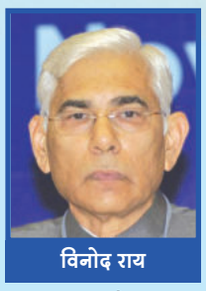

विनोद राय

पुलिस की वर्दी की तरफ सभी की निगाहें टिकी होती हैं और मुझे यकीन है कि यह वर्दी पहन कर और इस उच्च सेवा का हिस्सा बनकर आप लोग भी गर्व महसूस करते हैं. मैं आपका ध्यान सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक कथन की ओर दिलाना चाहूंगा, जिनके नाम पर इस एकेडमी का नामकरण किया गया है. उन्होंने संविधान सभा में कहा था, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी एक औजार हैं, जिनकी अनुपस्थिति में पूरे देश में अव्यवस्था के अलावा मैं और कुछ नहीं देख पाता हूं. मैं समझता हूं कि यह बात उस समय की अपेक्षा आज ज़्यादा प्रासंगिक है. इसका मतलब है कि हमारे प्रति आप लोगों की ज़िम्मेदारी पहले से काफी अधिक हो गई है. आज मैं आपके सामने तीन प्रस्ताव रखता हूं, जिन पर आप लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं. पहला प्रस्ताव यह है कि शासन अपने निम्नतम स्तर पर है, नागरिक सेवकों का नैतिक स्तर कमज़ोर है, सरकार की विश्वसनीयता न्यूनतम स्तर पर है और निर्णय लेने की क्षमता का ह्रास हुआ है. दूसरा प्रस्ताव है कि यह समय देश के लिए घातक है और तीसरा यह है कि इस स्थिति का उपचार हम लोग कैसे करते हैं. हम लोगों को अपनी भूमिका निभानी है. हम लोग इसमें अंतर कर सकते हैं. आइए, अब हम तीनों प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा करते हैं.

पहला प्रस्ताव

हम लोगों के पास ऐसे मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री हैं, जिनमें से कई को उस पद पर नहीं होना चाहिए. कुछ केंद्रीय मंत्री जेल में हैं. उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है. हमारे बीच कई सांसद हैं, जिन पर न्यायालय में कई मुकदमे चल रहे हैं. उन पर अपना मत देने एवं संसद में प्रश्न पूछने के बदले धन लेने का आरोप है. ये सारे उदाहरण उन लोगों के हैं, जो क़ानून बनाते हैं और ऊंचे दर्जे के प्रशासक हैं. नागरिक सेवा में भी हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं. यह कहा जा सकता है कि शासन में नैतिकता की कमी हो गई है. सरकार की विश्वसनीयता कम हो रही है. पुलिस से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है. नागरिक सेवकों की निष्ठा पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं. हमारे अधिकारियों का इस्तेमाल ग़लत कार्यों के लिए किया जा रहा है, जिसके चलते उनकी विश्वसनीयता आज़ादी के बाद सबसे निम्न स्तर पर पहुंच गई है. यह उस संस्था के लिए बहुत चिंतनीय बात है, जिसके बारे में कभी कहा जाता था कि यह देश का लौह कवच है. भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी आज उस जगह खड़े हैं, जहां वे समाज से यह नहीं कह सकते कि हम लोग उस सेवा में हैं, जिन्हें देश का प्रशासन चलाना है. मुझे यकीन है कि हम लोगों में से अधिकांश अपने आपको विश्वास नहीं दिला सकेंगे कि हमने इस देश को आधार प्रदान किया है. आज पुलिस व्यवस्था को सुधार की ज़रूरत है. ऐसा नहीं है कि सही प्रशिक्षण नहीं दिया जाता. मुझे विश्वास है कि इस एकेडमी में आपको सही ढंग से प्रशिक्षित किया जाता है. आपको पुलिस स्टेशन में सुधार करना है, जहां जाने से लोग डरते हैं. मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और अपराधों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. आपसे ऐसे कई सुधारों की आशा है. आपसे उम्मीद है कि इस एकेडमी में जो आपको सिखाया जा रहा है, उसका उपयोग जनता के बीच जाकर करेंगे. अगर ऐसा हुआ तो पुलिस पर लोगों का विश्वास बहाल होगा और आपको भी ख़ुद पर गर्व करने का मौक़ा मिलेगा.

दूसरा प्रस्ताव

मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है. आप सब जानते हैं कि हमारा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा आर्थिक तरक्की कर रहा है. इस समय दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में हमारा योगदान 6.2 प्रतिशत है. वर्ष 2040 से हमारा योगदान 8.8 प्रतिशत होगा. यह उत्साहवर्द्धक है, लेकिन ख़ुश होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है. आपको ध्यान रखना होगा कि चीन 13.7 और संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान एवं जर्मनी जैसे देश 19.4 फ़ीसदी का लक्ष्य हासिल करने में लगे हैं. हमारा आर्थिक विकास भी सुचारू रूप से हो रहा है, लेकिन हमें और मज़बूती हासिल करनी होगी. आज आज़ादी के 64 सालों के बाद भी महज़ 32 रुपये में हम ग़रीबी परिभाषित करते हैं. यह तथ्य हमारे देश के ग़रीबों का मज़ाक उड़ाता है. इसलिए हमें और भी बेहतर वातावरण तैयार करना होगा, क्योंकि यह देश के 1.2 अरब लोगों के भविष्य का सवाल है. आज हर चौक-चौराहे पर आम आदमी अच्छी सरकार और बेहतर शासन के लिए बहस कर रहा है. जब देश की जनता का जीवन स्तर सुधरेगा, तभी हमारे संस्थानों की विश्वसनीयता बढ़ेगी. आप सभी इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं. यह आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप देश के प्रति, अपनी वर्दी के प्रति लोगों का भरोसा जगाएं. भारतीय पुलिस ऐसा करने में सक्षम है. केवल आपको अपना लक्ष्य याद रखने की ज़रूरत है. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का गौरवशाली इतिहास रहा है. मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशिक्षण के बाद जब आप अपना पद संभालेंगे तो इन तमाम जज्बों को अपने अंदर जिंदा रखेंगे और एक बेहतर समाज के निर्माण के भागी बनेंगे. हम सभी सरकारी अधिकारियों को यह समझना होगा कि हमारे लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों को सबसे ज़्यादा महत्ता दी गई है.

सरकार को अपनी ताक़त का इस्तेमाल विशेष परिस्थितियों में ही करना चाहिए. विभिन्न मुद्दों पर अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन जब पुलिस की भूमिका पर बात होती है तो उसे सिर्फ़ आलोचना मिलती है. हमें यह कोशिश करनी होगी कि बेहतर कार्यप्रणाली से अपनी छवि सुधार सकें. आप जब पद संभालते हैं तो शपथ लेते हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ड्यूटी करते समय न अपनी शपथ भूलेंगे और न समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को. बदलते वक़्त के साथ लोगों की सोच भी बदल रही है. जनता चाहती है कि सरकार उसके मूलभूत अधिकारों के अलावा कुछ शक्तियां भी सौंपे. जागरूकता इतनी बढ़ चुकी है कि लोग समाज के विकास के लिए अब जनप्रतिनिधियों की ज़रूरत भी नहीं समझते. वे विकास कार्यों में सीधी भागीदारी चाहते हैं. ऐसी कई ऑडिट रिपोर्ट आई हैं, जिनमें योजना और कार्यान्वयन के लिए जनता की सक्रिय भागीदारी की इच्छा की चर्चा है. यह सही है कि देश की क़ानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस फोर्स और सुरक्षाबलों की संख्या में कमी है. यह बात तब और खुलकर सामने आती है, जब देश पर आतंकवादी हमले होते हैं. पर्याप्त संख्या न होने के बावजूद हम अपने देश और समाज की रक्षा में सक्षम हो सकते हैं, अगर आप सभी उच्च मनोबल और मज़बूत इच्छाशक्ति के साथ काम करें. आज भी हमारे देश की पुलिस पारंपरिक ढर्रे पर काम कर रही है. इसमें बदलाव की ज़रूरत है. मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, अगर क़ानून व्यवस्था के पालन में आप नागरिकों को अपना सहयोगी बनाएं. आप पाएंगे कि ऐसा करने से नतीज़े बेहतर होंगे. ऐसी स्थिति में जब एक नागरिक आपका सहयोगी बनकर क़ानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेगा, तब वह खुद को ज़्यादा जिम्मेदार महसूस करेगा, खुद अनुशासित रहेगा और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहेगा. तब पुलिस बल की कमी के बावजूद आप अपने कर्तव्यों का न सिर्फ़ उचित निर्वहन कर पाएंगे, बल्कि आप आलोचनाओं से भी बचेंगे.

सरकार को अपनी ताकत का इस्तेमाल विशेष परिस्थितियों में ही करना चाहिए. विभिन्न मुद्दों पर अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन जब पुलिस की भूमिका पर बात होती है तो उसे सिर्फ़ आलोचना मिलती है. हमें यह कोशिश करनी होगी कि बेहतर कार्यप्रणाली से अपनी छवि सुधार सकें. आप जब पद संभालते हैं तो शपथ लेते हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ड्यूटी करते समय न अपनी शपथ भूलेंगे और न समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को.

तीसरा प्रस्ताव

इस हॉल में उपस्थित एक समूह अभी अखिल भारतीय सेवा में प्रवेश करने ही वाला है. दूसरा समूह अब तक सरकारी सेवा में 15 साल गुजार चुका है और यह अनुभव कर चुका है कि किसी स्थिति से बेहतर ढंग से कैसे निपटना है. पहले ही इन दोनों समूहों ने स्वीकार किया है कि बदलाव की ज़रूरत है. इससे जनता का विश्वास फिर से सरकार या राज्य में स्थापित हो सकेगा. यही वजह है कि आज मैं आपके बीच हूं और यह अनुरोध करता हूं कि आप ही बदलाव के वाहक बनेंगे. शासन में सुधार की सारी कोशिशें बेकार चली जाएंगी, यदि बेहतर शासन के लिए ज़िम्मेदार अधिकारी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और शुचिता नहीं अपनाएंगे. पुलिस और ऑडिट विभाग के पास दोहरी भूमिका है. एक ओर हम पर सार्वजनिक जीवन में ख़ुद ईमानदार रहने की ज़िम्मेदारी है, दूसरी ओर लोक प्रशासन में शामिल अधिकारियों को ईमानदार बनाए रखने की. कहते हैं, इलाज से बचाव अच्छा होता है. सतर्क, प्रभावी और सक्षम निगरानी व्यवस्था तथा अंकेक्षण प्रणाली जनता के पैसों से चलने वाली संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार ला सकती है. बाहरी ख़तरों के मुकाबले अंदरूनी कमियां देश के विकास और संपन्नता के लिए ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं. आने वाले वक्त में यह कमी भ्रष्टाचार के कैंसर के रूप में फैलती है, समाज में अपराधीकरण बढ़ता है और फिर समाज अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन की उपेक्षा करने लगता है. ऐसी स्थिति में पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है. पुलिस वाले अगर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह ईमानदारी से करें तो समाज से अपराध और भ्रष्टाचार खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा. हमेशा आलोचना होती है कि पुलिस या सुरक्षाबल अपना कर्तव्य सही तरीके से नहीं निभाते हैं, जिसके चलते देश का प्रशासनिक ढांचा विकलांग हो गया है. इस तरह की बहस आज हर गली, हर चौराहे पर हो रही है.

इंडियन ऑडिट एंड एकाउंट डिपार्टमेंट ने भी ऐसी कई रिपोर्ट्स प्रकाशित करके इन कमियों की ओर इशारा किया है, जिन पर कानून व्यवस्था से जुड़ी संस्थाओं को ध्यान देने की जरूरत है. ऑडिट संस्थाओं की पहली ज़िम्मेदारी संसद को जनता के पैसे के सही उपयोग का सही हिसाब देना है. पुलिस का कर्तव्य है कि वह समाज में गैर कानूनी कार्यों में शामिल लोगों पर शिकंजा कसे, ताकि एक अच्छी शासन प्रणाली विकसित हो सके. यहां मौजूद आप सभी इस मुकाम पर इसलिए हैं, क्योंकि आपने पुरज़ोर कोशिश की, मेहनत की. मुझे यकीन है कि आप सभी कर्तव्यपरायणता और देश के प्रति निष्ठा से ओतप्रोत हैं और अपनी कार्यशैली से देश को गौरवांवित करेंगे. यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने कार्यों के ज़रिए आम आदमी की नज़रों में सरकार की विश्वसनीय छवि बनाएं. अगर हम ऐसा नहीं कर सके तो हम भारतीय प्रशासनिक सेवा की गरिमा को खंडित ही करेंगे. अब मैं यह सलाह देते हुए अपनी बात ख़त्म करूंगा कि जब भी आप एक अधिकारी के तौर पर सही निर्णय लेने में असहजता या किसी तरह का दबाव महसूस करें तो सिर्फ़ एक बार देश के ग़रीब आदमी का चेहरा, जो बड़ी उम्मीद से आपकी तरफ न्याय के लिए देख रहा है, याद कर लें. मुझे पूरा भरोसा है कि तब आप सच्चा और खरा फ़ैसला ले पाएंगे और अपनी वर्दी के साथ पूरा न्याय कर पाएंगे. मैं आप सभी की सफलता और बेहतर भविष्य की कामना करता हूं.

(राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आईपीएस अधिकारियों और वहां उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के बीच भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय ने देश की वर्तमान समस्याओं और सरकार की विश्वसनीयता जैसे मुद्दों पर अपने विचार रखे.)

feedback@chauthiduniya.com

मुंगेर के तौफीर दियारा नरसंहार और खगड़िया के अमौसी बहियार नरसंहार की जड़ में भी भूमि विवाद ही थे.

भूदान आंदोलन के 60 वर्ष

सपनों का मर जाना ख़तरनाक होता है

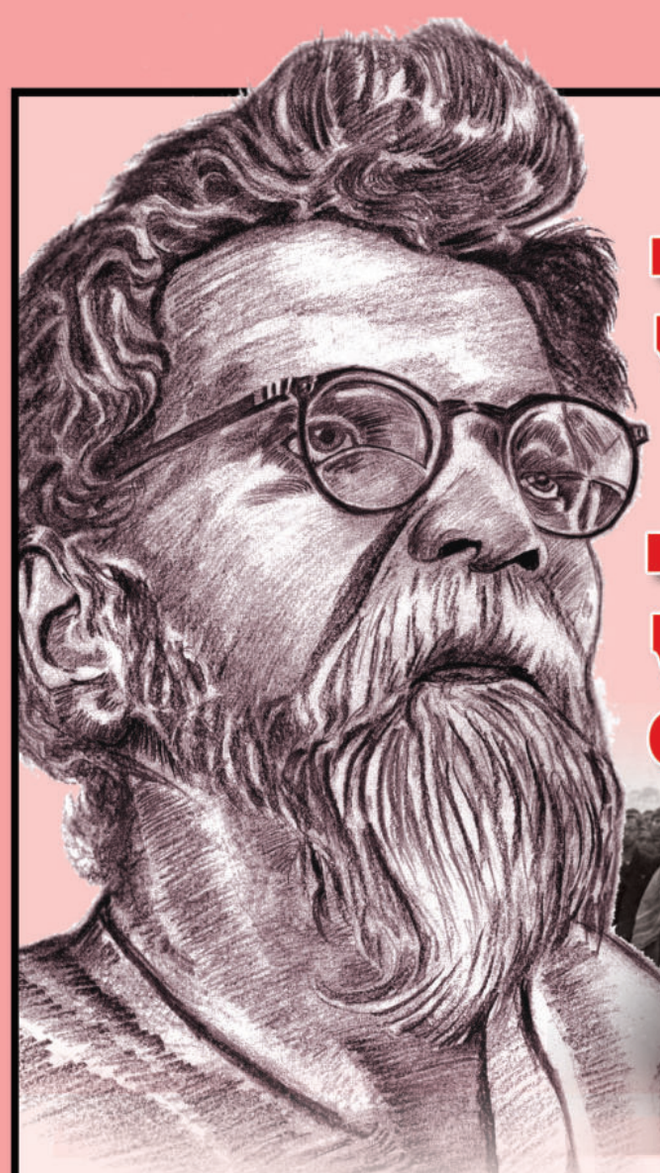

अभिषेक रंजन सिंह

आचार्य विनोबा भावे की अगुवाई में वर्ष 1951 में शुरू हुए भूदान आंदोलन के साठ वर्ष पूरे हो गए हैं. बिहार सहित देश के कई स्थानों पर विनोबा जी के आंदोलन की सराहना की गई, लेकिन इसके ठीक विपरीत बिहार में हज़ारों भूदान किसानों की जमीन खिसक रही है. जिस मक़सद से विनोबा जी ने भूमिहीनों के लिए ज़मीन हासिल की थी, वह पूरा नहीं हो पाया यानी ज़मीन का सही वितरण आज तक नहीं हो सका. बिहार की मौजूदा नीतीश सरकार भी इस दिशा में कोई ठोस क़दम नहीं उठा रही है. नतीजतन बिहार के ग़रीब भूदान किसान अब गांधी–विनोबा का रास्ता छोड़कर हिंसा वाली विचारधारा के करीब जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं. दरअसल भूदान की हजारों एकड़ ज़मीन पर दबंगों की नज़र लग गई है.

सरकार भी दबंगों से भूदान किसानों की ज़मीन बचाने में विफल नज़र आ रही है. सरकारी मालगुजारी रसीद न दिखाने पर भूदान किसानों को उनकी ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है. अगर अंचलाधिकारी भूदान किसानों को उनकी ज़मीन की रसीद नहीं देंगे और पुलिस उनकी ज़मीन हड़पने वाले बाहुबलियों की मदद करेगी तो भूदान किसानों को हिंसा का रास्ता अख्तियार करने से रोकना मुश्किल हो जाएगा. भूदान को लेकर बिहार की तस्वीर दूसरे प्रदेशों से अलग है. विनोबा भावे को अपनी भूदान यात्रा के दौरान सबसे अधिक ज़मीन बिहार में मिली थी. फिलहाल बिहार में भूदान यज्ञ कमेटी के कर्मचारियों की हालत दयनीय है. भूमि सुधार आयोग ने इस कमेटी को मज़बूत करने की सिफारिश की थी, जिस पर अभी तक अमल नहीं हो सका है. बिहार भूदान यज्ञ कमेटी के चेयरमैन शुभमूर्ति के अनुसार, भूदान आंदोलन से 6 लाख 48 हजार 593 एकड़ और 14 डिसमिल जमीन प्राप्त हुई थी, जिसमें 2 लाख 63 हजार 176 एकड़ और 2 डिसमिल ज़मीन कृषि योग्य थी. विनोबा जी ने इन जमीनों को ग्रामसभा के ज़रिए बांटने का प्रस्ताव पारित किया था. हालांकि जून 2011 तक 2 लाख 55 हज़ार 452 एकड़ और 87 डिसमिल ज़मीन का वितरण किया जा चुका है. शेष 2 हज़ार 26 एकड़ और 54 डिसमिल ज़मीन का वितरण नहीं किया गया है. बिहार भूदान यज्ञ कमेटी के मुताबिक़, 5 हज़ार 696 एकड़ और 61 डिसमिल ज़मीन का दानपत्र भी उसने सरकार को सौंप दिया है, जिसे सरकार ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है, लिहाजा उसका वितरण नहीं हो सका. कमेटी के अनुसार, भूदान की ज़मीन 3,86,859 भूमिहीन किसानों में बांटी गई है, लेकिन इनमें से लगभग 50 फीसदी किसान अभी तक ज़मीन पर क़ब्ज़ा नहीं पा सके हैं. इसी तरह करीब 50 प्रतिशत लोगों की जमीनों का दाखिल खारिज नहीं हुआ है. जिन किसानों को कब्जा मिल गया है, उनमें से आधे लोगों की जमीनों का दाखिल खारिज लंबित है. मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, सहरसा, दरभंगा, बक्सर, जहानाबाद, औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, भागलपुर और मुजफ्फरपुर आदि जिलों में भूदान की जमीन से जुड़े काफी मामले लंबित हैं. भूदान यज्ञ कमेटी का कहना है कि बिहार की पिछली सरकारें उसे 23 लाख रुपये का अनुदान देती थीं, जिसे नीतीश सरकार ने बढ़ाकर 70 लाख रुपये कर दिया, लेकिन इतने बड़े काम के लिए, जिसमें 2 करोड़ रुपये की ज़रूरत हो, वहां 70 लाख रुपये की धनराशि पर्याप्त नहीं कही जा सकती.

भूमि विवाद हत्याओं का मुख्य कारण

बिहार में होने वाली हत्याओं पर नज़र डालें तो उनके पीछे सबसे बड़ा कारण है भूमि विवाद. राज्य में हर साल कई लोगों का कत्ल ज़मीन विवाद के कारण होता है. बिहार में अब तक कई नरसंहार हुए, जिनमें ज़्यादातर भूमि विवाद के कारण हुए. मुंगेर के तौफीर दियारा नरसंहार और खगड़िया के अमौसी बहियार नरसंहार की जड़ में भी भूमि विवाद ही थे. क़ानूनी जानकारों के मुताबिक़, बिहार की निचली अदालतों ने भूमि विवाद का निपटारा करने के बजाय उन्हें और अधिक उलझा दिया है. बासगीच पर्चा, ग़लत दाखिल ख़ारिज़, गलत लगान निर्धारण करने में अंचलाधिकारी, डीसीएलआर और अपर समाहर्ता मिसाल कायम कर रहे हैं. चंद रुपयों के लालच में भ्रष्ट अधिकारी यह भी नहीं सोचते कि उनके इस कृत्य से कितनी लाशें बिछ जाएंगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन का लब्बोलुआब दिखा रहे हैं, लेकिन अगर सुशासन का असली चेहरा देखना हो तो उसे बिहार के प्रखंड और अनुमंडल कार्यालयों में बख़ूबी देखा जा सकता है.

अनुमंडल न्यायालय और रिश्वतखोरी

अनुमंडल न्यायालय यानी एसडीएम कोर्ट को निचली अदालत कहा जाता है. यहां ज़मीन से जुड़े विवादों का निपटारा किया जाता है. जिस मकसद से सब–डिवीजन स्तर पर इन न्यायालयों का गठन किया गया था, वह आज तक पूरा नहीं हो सका. इसमें कोई शक नहीं कि बिहार के ज़्यादातर अनुमंडल न्यायालयों में भ्रष्टाचार कायम है. इस बात के गवाह वे हजारों वादी–प्रतिवादी हैं, जो कई वर्षों से अपने मुकदमे के सिलसिले में अदालतों के चक्कर काट–काटकर थक चुके हैं. आंकड़ों के मुताबिक़, बिहार के अनुमंडल न्यायालयों में हज़ारों मुकदमे तीस–तीस साल से लंबित पड़े हैं. न्यायिक व्यवस्था का सबसे बड़ा मजाक तब देखने को मिलता है, जब मुकदमे का फ़ैसला अपने पक्ष में कराने के लिए इन न्यायालयों में खुलेआम रिश्वत की बोली लगाई जाती है. यही वजह है कि बिहार के आम लोगों में यह धारणा बन चुकी है कि एसडीओ कोर्ट में बिना पैसा दिए फैसला होता ही नहीं. न्याय के इस मंदिर को कलंकित करने वाले वे रिश्वतखोर एसडीएम (सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट) हैं, जिनके कार्यालय में विधायक, पंचायत के मुखिया और ठेकेदार मुकदमे की पैरवी के लिए आते हैं. फिलहाल बिहार के अनुमंडल न्यायालय की जो हालत है, उससे आम लोगों को न्याय मिलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती. यहां के अनुमंडल न्यायालयों में भूदान के सैकड़ों मामले लंबित हैं. इसके अलावा अंचल कार्यालय और डीसीएलआर कार्यालय में भी भूदान की जमीनों का बंदरबांट किया जा रहा है. नीतीश कुमार भले ही सुशासन का दावा करते हों, लेकिन सच्चाई यही है कि जिला, ब्लॉक और सब–डिवीजन मुख्यालयों में भ्रष्टाचार के मामलों में कोई कमी नहीं आई है.

नीतीश का महादलित प्रेम

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में महादलित कार्ड खेला, जिससे उन्हें जबरदस्त कामयाबी मिली. विपक्षी पार्टियों को फ़िलहाल इसकी काट नज़र नहीं आ रही है. महादलितों के लिए नीतीश कुमार ने कई लाभकारी योजनाएं चलाईं. ख़ासकर आवासहीन महादलित परिवार को 3 डिसमिल ज़मीन देने का फायदा उन्हें गत विधानसभा चुनाव में मिला. यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह पूछा जाना बेहद ज़रूरी है कि वह महादलितों को कौन सी ज़मीन दे रहे हैं. इसके अलावा सरकार को कई ज़िलों में महादलितों के लिए ज़मीन ख़रीदने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि उसके पास सीलिंग से हासिल की गई हजारों एकड़ भूमि मौजूद है. इसके अलावा गैर मजरूआ आम और भूदान की जमीन भी पर्याप्त है. उल्लेखनीय है कि जमींदारी उन्मूलन के बाद बिहार सरकार ने भू–हदबंदी कानून (सीलिंग एक्ट) के तहत बड़े–बड़े जमींदारों से हजारों एकड़ जमीन हासिल की थी, लेकिन भूदान की जमीन की तरह सीलिंग की जमीन भी आज तक जरूरतमंदों के बीच वितरित नहीं की जा सकी है. पिछली सभी सरकारें सीलिंग की जमीनों को दबंगों से मुक्त कराने में नाकाम रहीं. अगर भूदान और सीलिंग की जमीनों का सही वितरण हो जाए तो बिहार के लाखों भूमिहीनों की ग़रीबी दूर हो सकती है. अफसोस की बात तो यह है कि भूमि सुधार का सब्जबाग दिखाने वाले नीतीश कुमार भी इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहते. दरअसल वह पौधे की जड़ में पानी देने के बजाय उसके पत्तों को सींच रहे हैं.

arsingh@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... बीमार भाजपा

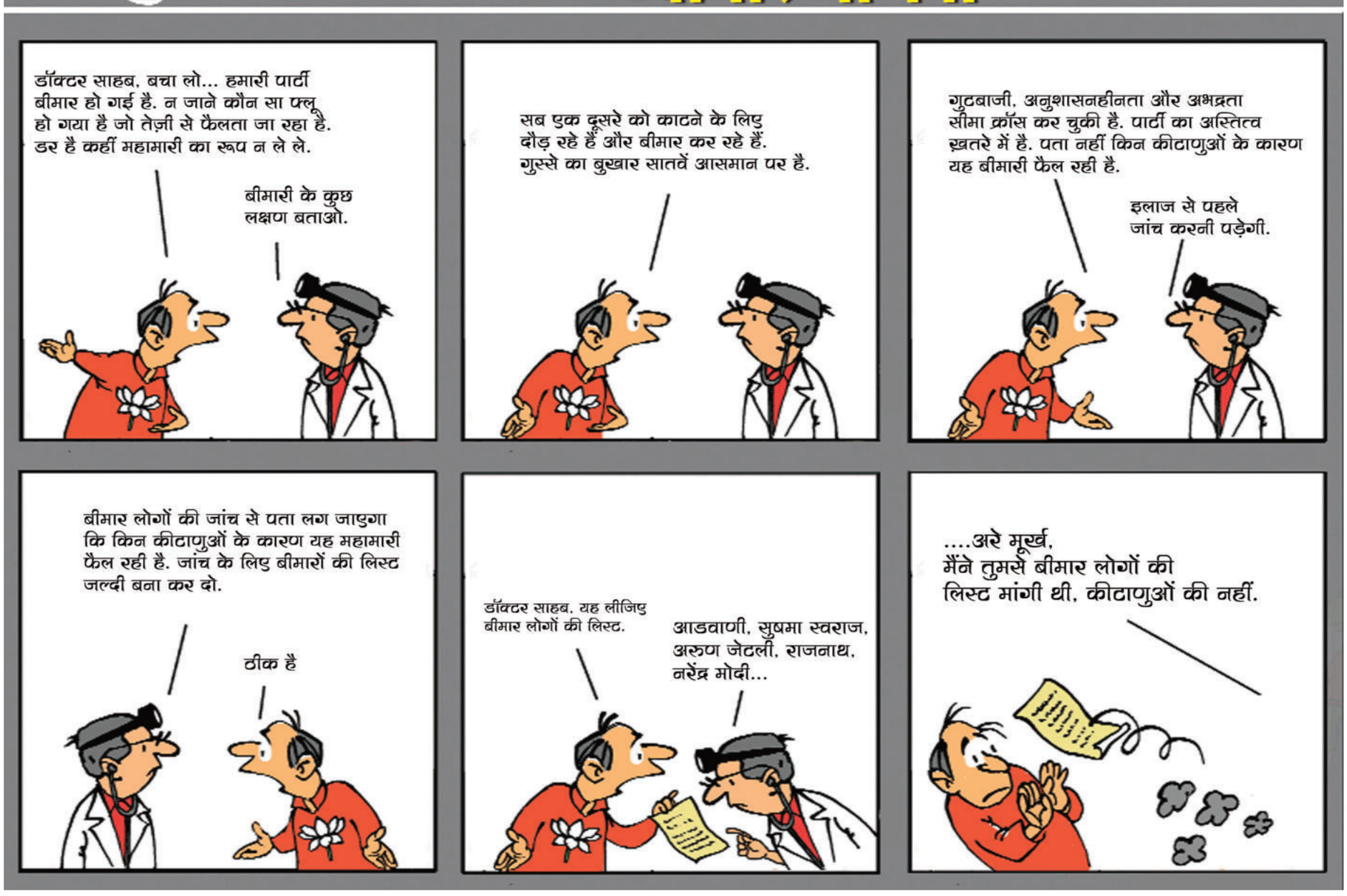

मोरारका फाउंडेशन ने आर्गेनिक टिफिन सेंटर की भी शुरुआत की है. इस सेंटर में जरूरतमंद विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों के लिये घर पर ही टिफिन पहुंचाने का काम किया जाता है.

बुलंदी की दहलीज़ पर शेखावाटी की महिलाएं

वसीम राशिद

राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के गांवो में सभी छोटे बड़े घरों की दीवारों पर ख़ूबसूरत कलाकृतियों के साथ बेटियों के सम्मान में कुछ पंक्तियां भी लिखी नज़र आती हैं. सड़क के किनारे से गुज़रते हर वाहन, व्यक्ति की नज़र इन घरों की दीवारों पर ज़रूर पड़ती है. जहां देश के दूसरे क्षेत्र के गांवों में महिलाएं सम्मान और अधिकार पाने की लड़ाई लड़ रही हैं, वहीं इन गांवों के लोगों ने बेटियों को ये आदर दिया है. परंपराओं और रूढ़ियों में जकड़े गांव के लोगों की महिलाओं के प्रति सोच को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है मोरारका फाउंडेशन ने. राजस्थान के शेखावाटी का झुंझनु ज़िले का नवलगढ़ महिलाओं की प्रतिभा, साहस और जज़्बे का जीता जागता उदाहरण है. सच है जहां विकास की सारथी महिलाएं हों, वहां संपन्नता की लहर को भला कौन रोक सकता है.

स्वयं सहायता समूह

नवलगढ़ की भगवती देवी अपने परिवार के साथ तंगहाल जी रही थीं, मुसीबत ऐसी कि घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे. मोहल्ले में किसी के घर पर चलने वाली स्वयं सहायता समूह की मीटिंग में इनका जाना यूं ही हुआ था पर उसके बाद सब बदल गया. वहां मोरारका फाउंडेशन की तरफ से चलाए जा रहे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी कई आयवर्धक कार्यक्रमों की जानकारियां मिलीं, जिससे भगवती देवी को आशा की नई किरण नज़र आई. समूह से जुड़कर साल भर परिश्रम कर उन्होंने बचत की और समूह से दस हज़ार रुपये का ऋण लेकर अपने बेटे को सब्जी और किराना की एक छोटी सी दुकान करवा दी. ख़ुद घरों पर खाना बनाने के काम से जुड़ी रहीं. बहुत जल्द उन्होंने दुकान और ख़ुद के काम से प्रतिमाह 1000 रुपये की किश्त भरकर ऋण चुका दिया. साथ ही आय होने से बेटी की स्कूली शिक्षा भी शुरू कर दी, इस तरह भगवती देवी के परिवार की आय भी बढ़ी और मान भी बढ़ा. भगवती देवी ने 10 किश्तों में अपना अपना ऋण चुका दिया और साथ में दूसरी महिलाओं को भी ऋण लेकर अपना व्यवसाय शुरू करने की प्रेरणा दी. इनसे प्रेरित होकर अन्य महिलाओं ने भी अपनी क्षमता के मुताबिक़ छोटे-मोटे काम जैसे बूटी-बंधेज, मूंग-मंगौड़ी, बड़ी-तिलौरी, पापड़-अचार, लिफाफे, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई आदि करने शुरू कर दिए. और अब समूह की अधिकांश महिलाएं स्वयं का कोई ना काम या व्यवसाय कर रही हैं. गांव अजीतपुरा की रामा देवी की भी यही कहानी है, समूह से जुड़कर बचत राशि जमा कर इन्होंने अपने परिवार का पेट पालने के लिए जैविक खेती करने के लिए ऋण लिया और अब अपने परिवार के साथ ख़ुशहाल जीवन जी रही हैं. क्षेत्र के कई गांवों में चलाए जा रहे इस स्वयं सहायता समूह से अब तक लगभग 2000 महिलाएं लाभांवित हुईं हैं, जिन्हें बैंक से 68,74,000 रुपये का ऋण दिलवाया गया है.

मोरारका फाउंडेशन दारा चलाई जा रही सबसे महत्वपूर्ण योजना स्वयं सहायता समूह है. इस योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर महिला जागरूकता मुहिम की शुरुआत की गई. जिसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने का काम किया गया और इसी समूह के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन संभव हो सके. स्वयं सहायता समूह 10 से 20 महिलाओं का समूह है. इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी कुछ महिलाएं शामिल होती हैं जो अपने फ़ैसले ख़ुद लेती हैं. हर माह एक निश्चत तारीख़ को बैठक होती है. जिसमें पहले से तयशुदा राशि जमा की जाती है. यह राशि ज़रूरतमंद महिलाओं को नियमानुसार क़र्ज के रूप में दी जाती है.

मोरारका फाउंडेशन का उद्देश्य है स्वयं सहायता समूह द्वारा समाज में फैली भ्रांति को दूर करके आपसी मेलजोल बढ़ाना. इसमें सभी महिलाएं एक जगह जमा होकर अपनी समस्याएं एक-दूसरे के सामने रखकर उन पर विचार-विमर्श करती हैं.

सोलर लैंप परियोजना

मोरारका फाउंडेशन ने इलाके के विकलांग और बेरोज़गार युवक-युवतियों को भी रोज़गार मुहैया करवाया है. इसके लिए फाउंडेशन ने उन्हें सोलर लैंप परियोजना का तोहफ़ा दिया है. इसके तहत फाउंडेशन ने गांव घोड़ीवारा कलां की नीलम कंवर को चुना और इसे एक सोलर पैनल और 25 लालटेन उपलब्ध कराए. नीलम विकलांग है और उस पर तीन बच्चों सहित पूरे परिवार के भरण पोषण की ज़िम्मेदारी है. ऐसे में इस योजना ने नीलम को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना दिया है. नीलम इन लालटेनों को किराये पर देकर अपनी रोज़ी-रोटी कमाती हैं. आज नीलम के चेहरे की ख़ुशी बताती है कि उसकी समस्याओं भरी जिन्दगी को मोरारका फाउंडेशन ने नई राह दी है.

कम्युनिटी किचन

कहते हैं महिलाओं का आधा जीवन खाना पकाने में ही बीत जाता है, जिसकी वजह से उन्हें किसी और काम के लिए वक़्त नहीं मिल पाता, लेकिन खाना पकाने में यदि नए तरीकों का इस्तेमाल किया जाए तो महिलाओं की कई मुश्किलें एक साथ हल हो जाती हैं. खाना पकाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल काफी महंगा पड़ता है, खाना बनाने में वक़्त भी ज़्यादा लगता है और परेशानी भी ज़्यादा होती है. महिलाओं की इन परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से मोरारका फाउंडेशन ने एक नई पहल की. सांझा गैस रसोई योजना के ज़रिए न केवल गैस ईंधन के इस्तेमाल के प्रति महिलाओं को जागरूक किया है, बल्कि रोज़गार के नए अवसर भी विकसित किए हैं. क्षेत्र के कई गांवों में फाउंडेशन ने यहां कम्युनिटी किचन के कई केंद्र खोले हैं. जिनके अलग-अलग नाम भी रखे गए हैं, मसलन स्नेह, कबीर और नारायण सामुदायिक रसोई केंद्र. इसमें छह परिवार की औरतें साथ मिलकर खाना बनाती हैं. फाउंडेशन दारा हर केंद्र में नि:शुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया गया है. समूह से जुड़े सबसे ग़रीब परिवार की महिला को कम्युनिटी किचन का इंचार्ज बनाया जाता है. बाक़ी महिलाएं रसोई में आकर एलपीजी चूल्हे का लाभ उठाती हैं और बदले में आपसी सहमति से तय की गई राशि इंचार्ज को देती हैं, इससे आर्थिक समस्या का निवारण भी होता है और समाज में सदभावना संदेश भी जाता है. फाउंडेशन की इस पहलकदमी से गांव की औरतें बेहद खुश हैं. नवलगढ़ के नारायण सांझा गैस रसोई की मुखिया शरबती देवी पहले चूल्हे पर खाना बनाती थीं, चूल्हे की गर्मी और लपटों से उठने वाले धुएं से परेशान थीं, लेकिन जब से वह एलपीजी चूल्हे पर खाना पकाने लगी हैं, जीवन के मायने बदल गए हैं. इसके अलावा इससे समय की बचत, कम लागत, कम परेशानी और कम मेहनत के साथ अच्छी कमाई भी हो जाती है. जिसका उपयोग वो स्वयं सहायता समूह में बचत के द्वारा भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए करती हैं. हर रोज़ खाना पकाने के दौरान हंसी-मज़ाक का जो माहौल बनता है, उससे इनके अंदर ज़िंदादिली आती जा रही है. एकसाथ खाना बनाने से सब परिवारों में आपस में मेल-मिलाप और अपनापन भी बढ़ा है.

सरकार ने सिक्किम को ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा दे दिया है. मोरारका फाउंडेशन ने इस क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं. लेकिन गांव-गांव तक ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर-तरीक़े और उसमें आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए ऐसे स्थानीय लोगों की ज़रूरत पड़ी, जिससे भाषा की मुश्किल को दूर किया जा सके. फाउंडेशन ने वीरबाला किसान कॉल सेंटर प्रोजेक्ट के ज़रिए स्थानीय गांव की लड़कियों को इससे जोड़ा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया. सिक्किम से महिलाओं का एक समूह इस प्रोजेक्ट की बारीकियों को समझने के लिए राजस्थान आया. यहां फाउंडेशन ने उन्हें किसान कॉलसेंटर चलाने के लिए प्रशिक्षित किया. अब ये महिलाएं सिक्किम जाकर वहां के किसानों को अपनी भाषा में जानकारियां उपलब्ध करा रही हैं. ये लड़कियां इस काम से जुड़कर आत्मनिर्भर हो रही हैं. फाउंडेशन की यह योजना अब देश के दूसरे राज्यों तक भी पहुंच रही है.

ऑर्गेनिक टिफिन सेंटर

मोरारका फाउंडेशन ने आर्गेनिक टिफिन सेंटर की भी शुरुआत की है. इस सेंटर में ज़रूरतमंद विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों के लिये घर पर ही टिफिन पहुंचाने का काम किया जाता है. ख़ास बात यह है कि फाउंडेशन यहां भी इनकी मदद करता है. टिफिन तैयार करने का काम तो महिलाएं करती हैं, लेकिन उन्हें घर-घर तक पहुंचाने का ज़िम्मा फाउंडेशन ख़ुद उठाता है. ऑर्गेनिक भोजन से लोगों की सेहत भी ठीक रहती है घर से दूर रहकर भी घर जैसा स्वादिष्ट खाना मिलता है. बेरी गांव की श्रीमती मूलसिंह ने अन्नपूर्णा शब्द को सार्थक किया है और इसीलिए वो अपनी बिटिया की प्रेरणा हैं. परिवार से ग़रीबी दूर करने का जो रास्ता उसकी मां ने अपनाया, रजनी उससे प्रभावित है. रजनी की मां और बड़ी मां ने ग़रीबी से बाहर आने के लिए ऑर्गेनिक टिफिन सेंटर की शुरुआत की. फाउंडेशन से मिली मदद के बाद आस-पड़ोस की औरतें मिलकर मूलसिंह देवी के साथ शुद्ध जैविक भोजन तैयार करती हैं और उसे टिफिन में पैक कर ज़रूरतमंदों तक पहुंचाती हैं. घर के लड़के-बच्चे उसे लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं.

किसान कॉल सेंटर, वीरबाला प्रोजेक्ट

राजस्थान की संस्कृति ही पर्देदारी की है, ऐसे में वहां की महिलाएं घर से बाहर निकलकर काम करें या आधुनिकता से वाक़िफ़ हों यह सोचना भी दुश्वार लगता है, लेकिन फाउंडेशन के वीरबाला प्रोजेक्ट की बदौलत आज यहां की महिलाओं की शख़्सियत ही बदल गई है. चेहरे पर घूंघट आज भी है लेकिन कॉलसेंटर में बैठकर वे बेधड़क किसानों को फोन और कम्प्यूटर के ज़रिए कृषि क्षेत्र में हो रहे नए प्रयोगों की जानकारी दे रही हैं. इस प्रोजेक्ट में शामिल महिलाओं को बाक़ायदा प्रशिक्षित किया जाता है. कॉलसेंटर में किसानों का डाटा बैंक तैयार किया जाता है, जिसमें किसानों से जुड़ी विस्तृत जानकारी होती हैं. खेतीबाड़ी से संबंधित किसानों की सभी परेशानियों का निवारण होता है. वीरबाला प्रोजेक्ट से जुड़ी तमाम महिलाओं ने बताया कि फाउंडेशन ने उन्हें जो मौक़ा दिया है, उससे उनके अंदर एक नई जागरूकता पैदा हुई है. कुदन गांव की सरोज कंवर को पढ़-लिखकर अनपढ़ होने का दुख सताता था, वह कहती हैं कि हमेशा से मन करता था कि बाहर की दुनिया देखें. मन में हमेशा कसक बनी रहती थी, कि पढ़-लिख कर भी हम अनपढ़ रह गए. न घर से बाहर की दुनिया देख पाए न जान पाए. राजपूत घरानों की महिलाओं को पर्दे में रहना होता है, इसलिए बाहर जाकर काम करने की इजाज़त नहीं मिली. मोरारका फाउंडेशन की तरफ से आए अख़बार के एक विज्ञापन में वीरबाला प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा, हमने घर पर मां से बात की, और मां ने पिता जी से बताया. पहले तो घरवालों को ऐतराज हुआ. पर जब पता चला कि इस काम को करने के लिए घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है तब घरवाले राजी हुए. वहीं गोठडा गांव की गोपाल कंवर को इस कॉलसेंटर ने आत्मनिर्भर बनाया है. पर इनके लिए ये राह भी आसान नहीं थी. वह कहती हैं कि पहले चाहकर भी कोई ऐसा काम नहीं कर पाती थी, जिससे ख़ुद की कोई पहचान बन सके. गांव के लोग शुरुआत में अपने घर की छोरियों को ये काम करने की इजाज़त नहीं देते थे, लेकिन इस काम को देखने के बाद अब मना नहीं करते हैं. काम देखने के बाद घर के पुरुषों में भी जागरूकता आई कि जो काम कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं और उन्हें करना ही चाहिए. अगर इसमें रुचि हो. इलाके के किसान भी फाउंडेशन के इस प्रयास से बहुत ख़ुश हैं और खेतीबाड़ी की नई विधियों से अवगत हो रहे हैं.

जैसलमेर प्रोजेक्ट

महिला कल्याण के लिये मोरारका फाउंडेशन ने जैसलमेर में एक क्रांतिकारी योजना की शुरुआत की है. फाउंडेशन ने सेक्स वर्कर्स के स्वास्थ्य से जुड़े मसलों पर एक बेहद कारगर योजना की शुरुआत की है. इसमें प्रोजेक्ट का मक़सद सेक्स वर्कर्स को स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां देकर उनको शारीरिक बीमारियों और एचआईवी एड्स से जागरूक करना है. इसमें सेक्स वर्कर्स को मुफ्त कंडोम मुहैया कराए जाते हैं. इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों ने उन सेक्स वर्कर्स से सम्पर्क करके उन्हें एचआईवी एड्स से सुरक्षा की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं. प्रोजेक्ट के निदेशक जे डी माथुर ने बताया कि समय-समय पर इन सेक्स वर्कर्स के एचआईवी टेस्ट कराए जाते हैं. अब तक इस प्रोजेक्ट से लगभग 750 सेक्स वर्कर्स जुड़ चुकी हैं.

कहते हैं अगर औरत शिक्षित हो तो पूरे परिवार को शिक्षित बनाती है, और अगर शक्तिशाली हो तो पूरे समाज को उससे ताक़त मिलती है. महिलाओं की ताक़त का सही नमूना देखना हो तो शेखावाटी की महिलाओं को देखना चाहिए, जिन्होंने न केवल ऑर्गेनिक खेती और विभिन्न प्रोजेक्टों के द्वारा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है, बल्कि समाज को भी नई राह दिखाई है. इन महिलाओं के चेहरों पर आत्मनिर्भरता और अपने पैरों पर खड़े होने का जो सुख दिखाई देता है वो बेमिसाल है.

editorurdu@chauthiduniya.com

अगर यों किसी रुपये वाले को धमका कर लूट लिया जाए या जिसकी जेब भारी है, उसकी जेब काट ली जाए, तो यह भी अपराध है.

अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों में जो उतार-चढ़ाव आता रहा है, उसके चलते भारत दक्षिण एशिया में ख़ुद को अमेरिका के निर्णायक सहयोगी के रूप में देखता है.

पर उपदेश कुशल बहुतेरे

महावीर प्रसाद आर मोरारका

अब अगर आपको यह निश्चय हो गया हो कि समान वित्त वितरण बहुत ही अच्छी चीज और उसका होना ज़रूरी है तो भी यदि आप धनिक हैं, समृद्ध हैं या उच्च वर्ग के मध्यवर्गीय हैं तो आप अपना धन जनता में बांट नहीं डालेंगे, यह तो पूरा भरोसा है. क्योंकि, अगर इसी तरह बातों से प्रभावित होकर आप अपना धन दे डालते तो आप धनिक या समृद्ध हो ही कैसे सकते थे? दिन भर में पचासों मौक़े ऐसे आते हैं, जहां आपकी भावुकता को विलोड़ित किया जाता है. अगर आप निर्धन हैं तो निश्चय ही आप चाहेंगे कि झटपट यह वितरण हो और हमें कुछ मिले. आप में से कुछ लोग आपस में यह भी कहेंगे कि भाई, लेखक ने इतना सब लिख डाला, समान वित्त वितरण का ज़ोरदार समर्थन कर दिया, पर सोचने की बात है, जब वे स्वयं इतनी संपत्ति के मालिक बने बैठे हैं तो फिर क्यों न अपने रुपये बांटकर यह शुरुआत करें. गोस्वामी जी की चौपाई कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो आचरहिं ते नर न घनेरे हमारे ऊपर फिट बैठा देंगे. सही है, समान वित्त वितरण की योजना आवश्यक है और आपने भी शायद समझ लिया होगा कि वर्तमान आर्थिक समस्या को संतोषप्रद बनाने का एकमात्र इलाज यही है, पर समस्या है कि यह कार्यान्वित कैसे हो? किसी व्यक्ति विशेष, कुछ आदमियों के या समस्त धनिक वर्ग के करने का कार्य नहीं है यह. वे लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि अपना धन दे दें. अगर वे दें तो यह दान होगा, जिसका मतलब भारतीय दृष्टिकोण से पुण्य कार्य होगा और जिसका फल, देने वाले के लिए वैकुंठ या स्वर्ग में सीट रिजर्व हो जाने की सुनिश्चितता है. नियम है कि देने वाले का दर्जा पाने वाले से ऊंचा रहता है. स्वाभाविक है कि यह भावना आ ही जाएगी कि देने वाले ने उपकार किया है. फिर बिना किसी काम या बदले के लेना तो नैतिक अपराध है. इस तरह के लेने को भिक्षा या भीख के सिवाय और कह ही क्या सकते हैं? जिस देश में दाताओं से भिखारियों की संख्या कई गुनी हो जाए, उस देश का उत्थान तो दूर रहा, उसकी किसी भी योजना पर विचार करना अत्यंत कठिन है.

भिक्षावृत्ति से काम चलाना मानव जाति का सबसे बड़ा पाप है. आज ही नहीं, बल्कि हजारों वर्ष पहले से इस संबंध में यहां के समाजशास्त्रियों ने कठिन नियम बना दिए थे, जिनके द्वारा यह घोषणा थी कि स्नातक ब्रह्मचारी या वीतराग संन्यासी के सिवाय अगर कोई भिक्षावृत्ति करता है तो वह चोर है और जिस राज्य में चौरवृत्ति होती है और वहां का राजा इस तरह के कारनामों को नहीं रोकता तो वह राजा चोर भक्त है, उसे राज्य करने का अधिकार नहीं:

येन भैक्ष्यचरा द्विजा.
चौर भक्त प्रदौ दि सः.

जिस देश में दाताओं से भिखारियों की संख्या कई गुनी हो जाए, उस देश का उत्थान तो दूर रहा, उसकी किसी भी योजना पर विचार करना अत्यंत कठिन है. भिक्षावृत्ति से काम चलाना मानव जाति का सबसे बड़ा पाप है. आज ही नहीं, बल्कि हज़ारों वर्ष पहले से इस संबंध में यहां के समाजशास्त्रियों ने कठिन नियम बना दिए थे, जिनके द्वारा यह घोषणा थी कि स्नातक ब्रह्मचारी या वीतराग संन्यासी के सिवाय अगर कोई भिक्षावृत्ति करता है तो वह चोर है और जिस राज्य में चौरवृत्ति होती है और वहां का राजा इस तरह के कारनामों को नहीं रोकता तो वह राजा चोर भक्त है.

इस शास्त्रीय वचन से सिद्ध होता है कि भिक्षा लेना या देना नैतिक अपराध है. अब भी है, हालांकि आजकल भिक्षा लेने के कई नए-नए तरीके चल पड़े हैं. क़ानून के फंदे में न फंसने पर भी तो यह नैतिक पतन तो है ही. तो फिर समान वित्त वितरण हो कैसे? अगर यों किसी रुपये वाले को धमका कर लूट लिया जाए या जिसकी जेब भारी है, उसकी जेब काट ली जाए, तो यह भी अपराध है. आप यह कर नहीं सकते. फ़ौरन पुलिस गिरफ़्तार करके हवालात में डाल देगी और समान वित्त वितरण की यह मीमांसा यों ही धरी रह जाएगी. इसका सिर्फ़ एक ही उपाय है. आपको अपनी पसंद द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा सैकड़ों नए-नए क़ानून बनवाने होंगे. साथ ही सैकड़ों पुराने चालू क़ानूनों को निरस्त या रद्द कराना होगा. यह प्रक्रिया कई महीनों या वर्षों तक चलेगी. हर एक क़ानून के अमल में आने के परिणामस्वरूप धनिकों की संपत्ति या आय में कुछ न्यूनता होगी और ग़रीबों या निर्धनों की संपत्ति या आय में वृद्धि होगी. हर क़ानून हर पहलू को ध्यान में रखते हुए कि संतुलन कहीं बिगड़ न जाए, आदर्श क़ानून पुंज बनेंगे, जिसके परिणामस्वरूप सबको समान वित्त वितरण का या कहें समान अवसर प्राप्त होता जाएगा.

सभ्यता का प्रथम अनिवार्य नियम यही है कि राष्ट्र का हर नागरिक क़ानूनपरस्त बने. जहां क़ानून का उल्लंघन होता है, हर व्यक्ति मनमानी करता है, वहां कितने ही आदर्श पुरुष क्यों न हों, पाशविकता छा जाएगी और मानवता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी. अगर कोई व्यक्ति आपके किसी प्रियजन का ख़ून कर डाले तो क़ानून के फंदे में उस ख़ूनी व्यक्ति को उस अपराध में मृत्युदंड प्राप्त होगा, पर आप यह नहीं कह सकते कि उसने हमारे प्रियजन को मार डाला है, सो हम उसे मार डालते हैं. ऐसा कर डालने में आपको उसी मुसीबत में पड़ना होगा, जिसमें वह ख़ूनी पड़ा है. कोई व्यक्ति अत्यंत आलसी है, कुछ भी काम नहीं करता, पड़ा-पड़ा खाता है, समाज के लिए यह कलंक है. निश्चय ही आपको क्रोध आएगा, पर अगर आवेश में आकर उसे आप भला-बुरा कहें या चांटा रसीद कर दें तो आपको कष्टप्रद परिणाम भुगतना ही पड़ेगा. तात्पर्य यही है कि समाज में कोई भी व्यक्ति कुछ ग़लती करे, अपराध करे, आपका बिगाड़ करे तो आप क़ानूनी कार्यवाही ही कर सकते हैं, क़ानून अपने हाथ में कदापि नहीं ले सकते. ऐसा करने से आप स्वयं अपराधी हो जाएंगे. सभ्यता की मूल भित्ति ही क़ायदे-क़ानून या अनुशासन का पालन है.

समाजवादी हो जाने या समाजवादी अर्थव्यवस्था का असर हो जाने से कोई ग़रीब या ग़रीबी दुनिया बदल जाने वाली है. आम क़ानूनों में या उनके प्रतिपालन में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ने वाला है. जो अपराध सामाजिक, नैतिक या वैयक्तिक आज हैं, वे वैसे ही रहेंगे. न्यायालय उसी तरह न्याय करते रहेंगे. समाजवाद हो जाने के बाद डॉक्टर या वकील को फीस नहीं देनी पड़ेगी, रेलवे की टिकट नहीं लगेगी, दुकानों में चीज़ें मुफ़्त मिलने लगेंगी, हर आदमी अपना-अपना उत्तरदायित्व समझ कर यों ही बिना शुल्क काम करेगा, समाजवादी मंत्री मोटर में नहीं बैठेंगे पैदल ही चलेंगे, समाजवादी मकान मालिक रहने वालों से मकानों का किराया नहीं लेंगे आदि-आदि सैकड़ों ग़लत धारणाएं लोगों ने समाजवाद के संबंध में बना रखी हैं. दुर्भाग्य है कि वे समाजवाद को ज़रा भी समझ नहीं पाए हैं. बल्कि मेरा तो मानना है कि ऐसा कहने वाले या मानने वाले किसी भी वाद को नहीं जानते. यहां तक कि सभ्यता या मानवता को भी नहीं समझ रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

यह सवाल नहीं, चिंगारी है

प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने वकील हैं. देश के कुछ वकील जिनका नाम सब लोग जानते हैं, उनमें प्रशांत भूषण भी हैं. उनके चेंबर में घुसकर चार युवकों ने मारपीट की. ये चारों लोग भारतीय जनता पार्टी के दफ़्तर में नियमित जाने वालों में से हैं और भाजपा की विचारधारा से जुड़े हुए किन्हीं अनाम से संगठन के सदस्य भी हैं. इनका कहना है कि प्रशांत भूषण ने कश्मीर पर एक वक्तव्य दिया, जिससे ये नाराज़ थे और इसीलिए इन्होंने प्रशांत भूषण के साथ मारपीट की. इन युवकों ने बाद में यह भी कहा कि प्रशांत भूषण को उनके घर में घुसकर फिर मारेंगे. यह घटना बताती है कि हम लोकतंत्र के सैचुरेशन प्वाइंट की तरफ बढ़ रहे हैं. हमने लोकतंत्र की अच्छाइयों को छोड़ दिया और उसके उस बुरे हिस्से को पकड़ने की कोशिश की, जिसके तहत हम अपने लिए सारी आज़ादी चाहते हैं, लेकिन दूसरों को कोई आज़ादी देना नहीं चाहते. जैसा हम सोचें, वैसा दूसरा बोले, जैसा हम चाहें, वैसा दूसरा करे. यह लोकतंत्र का बुरा हिस्सा है, जिसे इन युवकों ने अपनाया और शायद भारतीय जनता पार्टी आस्था के नाम पर इसी चीज को देश में फैलाने की कोशिश कर रही है. इन चारों लोगों में से कुछ ऐसे हैं, जो लगभग किसी भी आंदोलन में अगुवा पंक्ति में खड़े हो जाते हैं. ये सिर्फ़ चार होते हैं या दो, लेकिन ये उनमें शामिल हैं, जो अपना फोटो खिंचवा कर अपनी प्रासंगिकता कुछ विशिष्ट नेताओं के सामने रखते हैं और बताते हैं कि यह सब हमारी ही वजह से हुआ. हमारे पास बहुत सारी तस्वीरें ऐसी हैं भिन्न-भिन्न आंदोलनों की, जिनमें इनमें से कुछ चेहरे हर जगह आगे-आगे विभिन्न मुद्राओं में देखे जा सकते हैं.

अगर लोकतंत्र का यह हिस्सा हमारी जीवनशैली का अंग बन गया तो इससे एक बड़ा ख़तरा है और उसे भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ रही है. कांग्रेस भी शायद नहीं समझ रही है. बड़ा ख़तरा यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण दें तो वहां इस समय नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जो भाजपा की सहयोगी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह और अब लालकृष्ण आडवाणी, ये सभी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं. क्या भाजपा यह चाहेगी कि जब कभी लालकृष्ण आडवाणी गुजरात जाएं तो नरेंद्र मोदी के समर्थक उनके साथ मारपीट करें, क्योंकि वे नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री बने. या जब सुषमा स्वराज या अरुण जेटली उत्तर प्रदेश जाएं तो राजनाथ सिंह के समर्थक उनके साथ मारपीट करें. या राजनाथ सिंह जब मध्य प्रदेश जाएं तो उमा भारती के समर्थक उनके साथ मारपीट करें. जिस आधार पर किसी की बात पसंद न आने पर उसके साथ मारपीट का तर्क ये युवक देते हैं और इनकी विचारधारा के शीर्षस्थ लोग उसका खंडन नहीं करते, उनकी लानत-मलामत नहीं करते, उन्हें संगठन से निकालते नहीं हैं, बल्कि उन्हें साथ बैठाकर शाबासी देते हैं, उनके लिए वकीलों का इंतजाम करते हैं, ऐसे लोग इस ख़तरे से आज अनजान हैं, लेकिन यह ख़तरा उनके सिर पर आ रहा है. भारतीय समाज, भारतीय राजनीति और भारतीय लोकतंत्र में सहिष्णुता का प्रमुख स्थान है यानी दूसरे को उसकी बात कहने का हक़ देना, उसे सुनना, फिर यह कहना कि हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं और इसका फ़ैसला जनता के बीच करेंगे. सहिष्णुता और लोकतंत्र के इस मूल तत्व को अब कुछ लोगों ने ख़ारिज़ करना शुरू कर दिया है. क्या यह रास्ता लोकतंत्र को ख़ारिज़ करने की दिशा में जाएगा कि लोकतंत्र में वही होगा, जो हम चाहते हैं, जो हम लिखते हैं, जिसकी हमने कल्पना की है. जो लोग ऐसा सोचते हैं, वे जब भी फ़ैसले का वक़्त आता है, चुनाव में अल्पमत में आ जाते हैं.

बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ज़ोर-शोर से चुनाव लड़ा. लोगों ने उसकी सरकारों को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल में रिपीट नहीं किया. इसका मतलब देश का बहुमत इस पक्ष में नहीं है कि आप अपनी ही बात कहें और उसे समर्थन दे दें. किसी भी धर्म-जाति के लोग, जो वोट देते हैं, जो फ़ैसला करते हैं, उनका बहुमत किसी भी तरह के कठमुल्लेपन, इक्स्ट्रीमिज्म और परस्पर संघर्ष को पसंद नहीं करता. यह बात उन सभी लोगों को, चाहे वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हों या कांग्रेस से, समझनी चाहिए. इस देश के लोग बेबस हैं, लाचार हैं, अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते, लेकिन वे बेवकूफ नहीं हैं. वे जब भी फ़ैसला करते हैं, बहुत सोच-समझ कर करते हैं. मैं असहिष्णुता की एक और बात याद दिलाना चाहता हूं. अटल जी गुजरात गए थे, वहां उन्होंने राजधर्म की बातें कीं और जब वह लौट रहे थे हवाई अड्डे की तरफ, तो भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उनकी कार को रोका, उनके ख़िलाफ़ नारे लगाए. इतना ही नहीं, उनकी कार पर कूद-कूदकर वीभत्स नृत्य भी किया. वे कांग्रेस के लोग नहीं थे, वे किसी ऐसे दल के लोग भी नहीं थे, जो भाजपा को पसंद नहीं करता. वे भाजपा की विचारधारा के ही लोग थे. उस समय अगर उनमें कोई शैतान होता तो वह अटल जी के साथ मारपीट कर सकता था. उस घटना से जब भारतीय जनता पार्टी ने कोई सबक नहीं लिया तो यह स्थिति आनी ही थी और यह चीज नीचे सर्कुलेट होनी थी कि आप ऐसे लोगों को न बोलने दें, न चलने दें और न नारे लगाने दें, जिनकी बातों को आप पसंद नहीं करते.

शायद इसीलिए दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर उन लोगों के साथ मारपीट की गई, जो अन्ना हज़ारे के समर्थक थे. क्या विडंबना है कि एक तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत दावा करते हैं कि अन्ना हजारे के आंदोलन को संगठित करने, उसे चलाने, फैलाने के पीछे उन्हीं का हाथ है और दूसरी तरफ उनकी विचारधारा से जुड़े लोग अन्ना हज़ारे के लोगों को पीटते हैं. वे यह चाहते हैं कि अन्ना हज़ारे या उनके लोग सिर्फ़ वही बात करें, जिससे उन्हें फ़ायदा हो यानी सिर्फ़ भ्रष्टाचार की बात. बाकी चीजों को वे सुनना नहीं चाहते, चाहे वह किसानों की बात हो, मज़दूरों की बात हो, कश्मीर की बात हो. हम कश्मीर के मुद्दे पर प्रशांत भूषण से सहमत नहीं हैं. हम कश्मीर को भारत का टुकड़ा नहीं मानते. हम कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग इसलिए नहीं मानते, क्योंकि हमें कश्मीर पर क़ब्ज़ा करना है, बल्कि हम कश्मीर को भारत की धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक के रूप में मानते हैं. पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ के साथ एक बातचीत में चंद्रशेखर जी ने कहा था कि अगर आप कश्मीर को इस तर्क के आधार पर पाकिस्तान में मिलाने की बात करेंगे या कश्मीर के लोग इस तर्क के साथ पाकिस्तान में मिलाने की बात करेंगे कि वहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं तो यह तर्क हिंदुस्तान के 15 करोड़ मुसलमानों के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित होगा, क्योंकि यह हिंदुस्तान के गांवों में रहने वाले करोड़ों मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदुओं को एक तर्क दे देगा, गैर मुस्लिमों को एक तर्क दे देगा कि हम अपने गांव में इन्हें नहीं रखना चाहते. तब उन्हें वहां से निकाला जाएगा. अगर वहां से निकाला गया तो दूसरे गांव वाले उन्हें रखेंगे नहीं तो वे वहां से कहां जाएंगे. नतीजा एक संघर्ष के रूप में सामने आएगा और वह संघर्ष सांप्रदायिक होगा. हिंदुस्तान के गांव-गांव में सैकड़ों सालों से हिंदू और मुसलमान बहुत प्यार से, आराम से, एक-दूसरे की इज्जत करते हुए, सह अस्तित्व यानी तुम भी रहो, हम भी रहें के सिद्धांत के आधार पर जीते हैं, दु:ख-सुख में शरीक होते हैं, उस चीज को तोड़ने का काम जो तर्क करेगा, वह हिंदुस्तान की संप्रभुता और लोकतंत्र के ख़िलाफ़ होगा. हम अपनी मां को जब मां कहते हैं तो वह प्यार से हमारे सिर पर हाथ फेरती हैं, लेकिन मां कहना जितना सत्य है, उतना ही बड़ा सत्य है अपनी मां को अपने पिता की पत्नी के रूप में बताना. अगर हम अपनी मां से कहें कि हमारे फलाने पिता की पत्नी हमको ज़रा यह दो, तो मां दो झापड़ मारेगी. ठीक यही कश्मीर के साथ हो रहा है.

भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रशांत भूषण तीनों ही कश्मीर को साथ रखने के ग़लत तर्क दे रहे हैं. हमारा मानना यहळ है कि कश्मीर को धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक के तौर पर साथ रखने का तर्क सही है, पर इसके बावजूद हिंदुस्तान का लोकतंत्र यह कहता है कि भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कश्मीर को लेकर अपनी सारी बात निर्भीक ढंग से सामने रखे. वही तर्क प्रशांत भूषण को भी अपनी बात हिंदुस्तान के लोगों के सामने निर्भीक ढंग से रखने की इजाज़त देता है. यह नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी अपना तर्क रखे और प्रशांत भूषण न रखें. हमारा मानना है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र को उसके बुरे पहलुओं के जाल में मत फंसने दीजिए. हिंदुस्तान का लोकतंत्र सारी दुनिया में आदर्श लोकतंत्र है. यह ज़िम्मेदारी है स्वयं संघ प्रमुख मोहन भागवत, लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली एवं राजनाथ सिंह जैसे लोगों की. वे इस बात को खुलेआम कहें कि हिंदुस्तान में हरेक को अपनी बात कहने का उतना ही हक़ है, जितना हमें. जो कोई इस हक़ को मारने की बात करता है, वह हमारा साथी नहीं है, हमारा सदस्य नहीं है, वह लोकतंत्र का विरोधी है, पार्टी का विरोधी है, समाज का भी विरोधी है, क्योंकि वह समाज में टूट पैदा करना चाहता है. इस सवाल को टालिए मत, क्योंकि यह सवाल वैसा ही है, जैसे जंगल में छोटी सी चिंगारी से आग लगती है और अगर उसे बुझाया न जाए तो पूरा जंगल इतनी बुरी तरह धू-धू करके जलता है कि बस्तियों, इंसानों और जानवरों को अपनी चपेट में ले लेता है. हिंदुस्तान के सामाजिक ताने-बाने और लोकतंत्र को, जो लोग जलाने की कोशिश करना चाहते हैं, उनसे बचाने के लिए मोहन भागवत, लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली एवं राजनाथ सिंह को तत्काल आगे आना चाहिए और देश के सामने अपनी स्पष्ट राय रखनी चाहिए.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

कमल मोरारका का ब्लॉग
www.kamalmorarka.com

ग़रीबी और अमीरी के बीच की खाई बढ़ी है

आजकल 9 फ़ीसदी से कम विकास दर पर काफी चर्चा की जा रही है. हालांकि विकास दर महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि विकास का विषय क्या है. 1991 में हमसे यह वादा किया गया था कि आर्थिक सुधार से विकास दर में वृद्धि होगी और इससे समृद्धि आएगी. साथ ही ऊपर के स्तर पर हो रहे विकास के प्रभाव से ग़रीबी को कम किया जा सकेगा. बीस साल गुजर गए हैं, लेकिन न केवल अभी ग़रीबी बरक़रार है, बल्कि अमीर लोग और अधिक अमीर हुए हैं तथा ऊपर के स्तर पर आने वाली समृद्धि से ग़रीबी समाप्त होने की जो बात कही जा रही थी, वह धराशायी हो गई है. इस बात की काफी उम्मीद है कि विकास दर घटकर 7.2 फ़ीसदी तक पहुंच जाए. ठीक इसी समय योजना आयोग ने कहा कि जो भी व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपये से अधिक कमा रहा है, वह ग़रीब नहीं है.

आंकड़े अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि 32 रुपये किसी भी व्यक्ति के एक दिन के ख़र्च के लिए काफी कम हैं. इसकी जानकारी के लिए हमें किसी अर्थशास्त्री की आवश्यकता नहीं है. अभी आवश्यकता है अर्थव्यवस्था के नवीनीकरण की, जिसमें उन लोगों को भी शामिल किया जाए, जो अभी तक उपेक्षित रहे हैं. ग्रामीण इलाक़ों में एक छोर पर किसान हैं तो दूसरे छोर पर वे मज़दूर, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है. शहरी क्षेत्रों में एक तरफ़ पक्के मकानों में रहने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ़ गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग, जिन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. 1991 के बाद ग़रीब और अमीर के बीच की विषमता बढ़ी है, जबकि इससे पहले विकास दर तो कम रही, लेकिन आर्थिक विषमता इस स्तर की नहीं दिखाई देती थी. सरकार कुछ आंकड़ों को नहीं दिखाती है या कह सकते हैं कि दिखाने से डरती है. इनमें से एक है कृषि क्षेत्र, जहां निवेश में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो सकी है. अगर इस पर ग़ौर नहीं किया गया तो अगले दस सालों के भीतर खाद्य वस्तुओं का अभाव हो जाएगा.

अभी जितना उत्पादन होता है, वह सराहनीय है, लेकिन अगर इसे ही अधिकतम उत्पादन समझ लिया जाए तो बाद में समस्याएं उत्पन्न होना तय है, क्योंकि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है. हमें अपने पहले के उत्पादन से ख़ुश होकर चुपचाप बैठने की आवश्यकता नहीं है, इसे लगातार बढ़ाना होगा. आज उन लोगों में काफी नाराज़गी है, जो वर्तमान बाज़ार से दूर कर दिए गए हैं. वे लोग बाज़ार की उन वस्तुओं को नहीं ख़रीद सकते, जिनका प्रचार देखकर ख़रीदने की इच्छा उनके अंदर पैदा होती है. इसलिए अभी इस बात की ज़रूरत है कि सरकार रोज़गार पैदा करने पर विशेष ध्यान दे, ताकि शिक्षित युवा रोज़गार के अवसरों की कमी के कारण हतोत्साहित न हों. एक तरफ़ तो ग़रीबी बढ़ रही है और दूसरी ओर कंपनियां अपने मुनाफ़े में लगातार वृद्धि कर रही है. उनका टर्नओवर दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. यह दौर प्रतिस्पर्द्धा का है और मुनाफ़ा कमाने की दौड़ में कहीं पिछड़ न जाएं, इसलिए लोग कोई भी साधन-तरीक़ा अपनाने के लिए तैयार बैठे हैं. यही कॉरपोरेट सेक्टर में भ्रष्टाचार का मूल कारण है. 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाला इसका जीता-जागता उदाहरण है कि एक-दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए किस स्तर तक जाया जा सकता है. अगर अर्थव्यवस्था इसी तरह चलती रही तो ऐसे कारनामे दोहराए जाते रहेंगे.

अभी आवश्यकता है अर्थव्यवस्था के नवीनीकरण की, जिसमें उन लोगों को भी शामिल किया जाए, जो अभी तक उपेक्षित रहे हैं. ग्रामीण इलाक़ों में एक छोर पर किसान हैं तो दूसरे छोर पर वे मज़दूर, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है. शहरी क्षेत्रों में एक तरफ़ पक्के मकानों में रहने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ़ गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग, जिन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

feedback@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

सोच-समझ कर क़दम उठाने की ज़रूरत

जुड़वा लोग मित्र और शत्रु दोनों ही रूप में करीबी हो सकते हैं. जुड़वा एक ही तरह की सोच रखते हैं. वे एक-दूसरे के मन की बात जान सकते हैं. इसलिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने अपनी भारत यात्रा के समय कहा कि भारत उसका मित्र है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो जुड़वा देश हैं. उनका यह कथन किसी को चौंकाने के लिए काफी है. एक तरह से देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान बेशक जुड़वा देश हैं, क्योंकि विभाजन के पूर्व दोनों एक थे, लेकिन विभाजन की त्रासदी ने दोनों देशों के रिश्तों में खटास पैदा कर दी. विभाजन के समय लाखों लोगों की जानें गईं और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ. हालांकि पाकिस्तान भी ज़्यादा दिनों तक एक राष्ट्र नहीं रह पाया और उसका भी 1971 में विभाजन हो गया तथा बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का निर्माण हुआ. बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत की भूमिका के कारण पाकिस्तान के साथ उसके संबंध और भी असहज हो गए. भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए 2004 से ही काफी प्रयास किए.

विकीलीक्स ने भी हाल में इस बात का खुलासा किया है कि पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के मुद्दे पर भारतीय प्रधानमंत्री को अपने सहयोगियों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला. उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शर्म-अल-शेख में हुई बैठक में इसके लिए पहल भी की थी, लेकिन उनके इस रुख को सराहा नहीं गया. मनमोहन सिंह द्वारा उठाए गए कदम को आगे बढ़ाने का प्रयास न पाकिस्तान की ओर से किया गया और न भारत की ओर से. भारत ने अफगानिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाने का प्रयास किया है. इस प्रयास के पीछे कई कारण बताए जा सकते हैं. पहला तो यह कि अफगानिस्तान दो ओर से पाकिस्तान से घिरा हुआ है, ऐसे में भारत को उसका सहयोग मिलता है तो इससे पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सकता है. यह भी कहा जा सकता है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनने की आशा ही छोड़ दी है. साथ ही साथ इसे भारत की क्षेत्रीय महाशक्ति बनने की रणनीति के रूप में भी देखा जा सकता है. इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर क्षेत्रीय महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा हमेशा रही है. अमेरिका के साथ भारत का नाभिकीय समझौता एक तरह से चीन के विरुद्ध एक आत्मरक्षात्मक गठबंधन बनाना ही रहा है.

अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों में जो उतार-चढ़ाव आता रहा है, उसके चलते भारत दक्षिण एशिया में खुद को अमेरिका के निर्णायक सहयोगी के रूप में देखता है. इसके अलावा पाकिस्तान और चीन के बीच सैन्य गठबंधन बन रहा है. पाकिस्तान के बल्टिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में चीन द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य इसके उदाहरण हैं. एक प्रकार से वह पाकिस्तान को घेर रहा है. यह भारत के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि चीन-पाकिस्तान संबंध भारत केंद्रित ही रहे हैं. बेशक इसे सरकारी तौर पर अस्वीकार किया जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा. एशिया में पनप रही नई व्यवस्था निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के माहौल को गर्म करेगी, लेकिन मूल प्रश्न तो भारत का है. क्या भारत एशिया में होने वाले इस परिवर्तन के लिए तैयार है, क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान और चीन के विरुद्ध भारत का साथ देगा, जबकि अमेरिका भारत की तरफ रहेगा और क्या हम पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार हैं?

बहुत सारे प्रश्न एक साथ हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं. इन सभी पर विचार करने के बाद ही कोई कदम उठाया जाना चाहिए. माइक मुलेन ने अपनी सेवानिवृत्ति के समय कहा कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क को समर्थन दे रहा है. इससे तो यही लगता है कि पाकिस्तान की रणनीति अफगानिस्तान में फिर से तालिबान शासन बहाल करने की है. साथ ही वह उसका उपयोग भारत के खिलाफ करने की रणनीति पर भी काम कर रहा है. भारत की रणनीति भी पाकिस्तान को घेरने की है. अफगानिस्तान से संबंध बढ़ाने की कोशिश उसी रणनीति का परिणाम है. इसलिए पाकिस्तान भी अफगानिस्तान में तालिबान शासन स्थापित करने के लिए अपना प्रयास तेज करेगा, चाहे अमेरिका उसके इस कार्य को पसंद करे अथवा नहीं. सबसे बड़ी बात यह है कि जबसे अमेरिका और ब्रिटेन ने अगले दो वर्षों में अफगानिस्तान से अपने सैनिक वापस बुलाने की घोषणा की है, तबसे ऐसा लग रहा है कि 2014-15 में अफगानिस्तान में कुछ नए विवाद उठ सकते हैं.

यह सही है कि भारत की विदेश नीति का निर्धारण यहां की लोकतांत्रिक सरकार ही करती है और विदेश मंत्रालय एवं प्रधानमंत्री कार्यालय के पास तेज दिमागों की कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध आगे बढ़ रहे हैं, उससे कई तरह के विवादों का जन्म होगा. अगर भारत पहले से ही उन पर विचार कर चुका है तो उसे एक स्पष्ट योजना बनानी चाहिए. ऐसा न हो कि परिणाम भारत के पक्ष में न हो, क्योंकि यह तय है कि जब भारत अफगानिस्तान के साथ नजदीकी बढ़ाएगा तो पाकिस्तान इस बात को गंभीरता से लेगा. वह भारत में आतंकी हमलों को अंजाम दे सकता है. पाकिस्तान के इस कदम का असर अरुणाचल प्रदेश पर भी पड़ेगा, क्योंकि इसका संबंध चीन से है. चीन के जिन क्षेत्रों में इस्लामिक आंदोलन चल रहे हैं, वे अफगानिस्तान से ज़्यादा दूर नहीं है और पाकिस्तान का वहां अच्छा-खासा प्रभाव है. इसलिए भारत को तैयार रहना होगा, अन्यथा परिणाम अपेक्षा के विपरीत भी हो सकता है.

अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों में जो उतार-चढ़ाव आता रहा है, उसके चलते भारत दक्षिण एशिया में ख़ुद को अमेरिका के निर्णायक सहयोगी के रूप में देखता है. इसके अलावा पाकिस्तान और चीन के बीच सैन्य गठबंधन बन रहा है. पाकिस्तान के बल्टिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में चीन द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य इसके उदाहरण हैं. एक प्रकार से वह पाकिस्तान को घेर रहा है. यह भारत के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि चीन-पाकिस्तान संबंध भारत केंद्रित ही रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

शिक्षा का व्यवसायीकरण

चौथी दुनिया में प्रकाशित आलेख-शिक्षा का माफ़िया राज पढ़ा. लगभग पंद्रह वर्ष पूर्व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मनीषा जैन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में यह ऐतिहासिक फ़ैसला दिया गया था कि शिक्षा को व्यवसाय बनाया जाना संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विपरीत है और नीति निर्देशक सिद्धांत केवल पवित्र घोषणा मात्र नहीं हैं, बल्कि सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर सकती, जो नीति निर्देशक सिद्धांतों और संविधान के विपरीत हो. इस फ़ैसले से कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के कई राजनेताओं की गद्दी चली गई, लेकिन मनीषा जैन को मेडिकल कॉलेज में दाख़िला नहीं मिल सका. अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के दौर में शिक्षा का निजीकरण भी हुआ, लेकिन इससे शिक्षा के व्यवसायीकरण की गति तेज़ हुई. आज शिक्षा के क्षेत्र में माफ़ियाओं का बोलबाला है.

-अनिल गुप्ता, *मेरठ, उत्तर प्रदेश.*

बजट की कमी

वर्ष 1994 में वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना स्थापित होने के बाद भी बाघों की घटती संख्या से स्पष्ट है कि उनके रखरखाव के लिए बजट की कमी है. इसके साथ ही एक ठोस नीति की भी ज़रूरत है. कुछ समय पहले शिकारियों ने एक दुर्लभ प्रजाति के गैंडे को गोली मार दी थी, जिसकी सूचना 10-12 दिनों बाद मिली. बाघों के साथ-साथ गिद्धों के भी संरक्षण की जरूरत है.

-चंद्रशेखर चौधरी, *मुंगेर, बिहार.*

बाढ़ की विभीषिका

देश में हर साल बाढ़ से भारी तबाही होती है. पहले तो प्रशासन कहता है कि बाढ़ से निपटने के व्यापक प्रबंध हैं, लेकिन बाद में वह अपने हाथ खड़े कर लेता है. जर्जर तटबंधों की अनदेखी हर साल बर्बादी का कारण बनती है. सरकार राहत की घोषणा करके अपनी जिम्मेदारी की खानापूर्ति कर लेती है. बाढ़ से निपटने के लिए एक ठोस रणनीति बनाई जानी चाहिए.

-चंद्रकांत यादव, *चंदौली, उत्तर प्रदेश.*

सर्वश्रेष्ठ पत्र

आंकड़ों का भ्रष्टाचार

अस्सी हज़ार वेतन मांगने वाले जनता के सेवकों का पेट निश्चित रूप से इस धनराशि से भी नहीं भरेगा, लेकिन देश की ग़रीब जनता ख़ून-पसीना बहाकर बेहाल होने के बाद भी सिर्फ 32 रुपये पाकर अमीरों की जमात में खड़ी हो गई है. ठीक ही कहा गया है, जाके पांव न फटे बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई. प्रति माह लाखों रुपये की नि:शुल्क सुख-सुविधाएं भोगने के बाद भी 80 हज़ार रुपये वेतन पाने वाले जनप्रतिनिधि आटा-दाल का भाव कैसे जान सकते हैं? अब तो यही प्रतीक्षा है कि अमीर होने का पैमाना 32 रुपये से नीचे गिरकर एक रुपये पर कब आता है. सच कहा जाए तो यह आंकड़ों का भ्रष्टाचार है. ऐसे में जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीद की जाए.

-जलालुद्दीन ख़ां, *देवरिया, उत्तर प्रदेश.*

विज्ञापनों की भरमार

यहां जो दिखता है, वही बिकता है यानी जब तक किसी उत्पाद का विज्ञापन न किया जाए, वह बिकने वाला नहीं है. यूरोप और अमेरिका में तो विज्ञापन को अर्थव्यवस्था का पहिया कहा जाता है. भारत में भी हर तरफ़ विज्ञापन ही विज्ञापन नज़र आते हैं, भले ही वह सरकारी बस ही क्यों न हो. ज़रूरी सूचनाओं के बोर्डों पर विज्ञापन के पोस्टर चिपके होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

-रुचिन भाटिया, *करनाल, हरियाणा.*

घोटाले दर घोटाले

भारत में कोई भी काम बिना घपले के होना लगभग असंभव है. नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट इसी की भेंट चढ़ गया. सबसे पहली अनियमितता तो यह है कि गोपा सब्बरवाल की ग़ैर क़ानूनी ढंग से नियुक्ति की गई. देश में हर तरफ भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला है.

-अरुण सरोहा, *मालवीय नगर, नई दिल्ली.*

राजकमल प्रकाशन समूह
राजकमल प्रकाशन राधाकृष्ण लोकभारती प्रकाशन

चौथी दुनिया में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को राजकमल प्रकाशन की ओर से 700 रुपए की किताबें दी जाएंगी.

राजकमल प्रकाशन की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें. हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

शोध में नार्वे, एस्टोनिया, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस और स्पेन के उन लोगों को शामिल किया गया, जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है.

दिल्ली, 24 अक्टूबर–30 अक्टूबर 2011 चौथी दुनिया

सूचना का अधिकार जानने का अधिकार जीने का अधिकार चौथी दुनिया की पहल

आरटीआई, मनरेगा और जॉब कार्ड

ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार पैदा करने के लिए सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा को सफल बनाने के लिए हज़ारों करोड़ रुपये ख़र्च करने की योजना बनाई. यह योजना गांवों तक पहुंची भी, लेकिन हर योजना की तरह मनरेगा भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गई. देश भर में मनरेगा से जुड़ी धांधलियों की ख़बरें मीडिया में लगातार आती रहती हैं. जैसे, कहीं किसी ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत फ़र्ज़ी जॉब कार्ड बनाकर मज़दूरी का धन हड़प लेना या फिर प्रधान और पंचायत सचिव मिलकर विद्यालय के प्रबंधक, ठेकेदार और व्यापारियों तक के नाम जॉब कार्ड जारी कर देते हैं. इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारियों की मिलीभगत से मज़दूरों का भुगतान महीनों तक न होने की शिकायतें मिलती हैं. धांधली सामने आने पर जांच के आदेश दे दिए जाते हैं और कभी-कभार कार्रवाई भी हो जाती है. दरअसल, मनरेगा में मनमानी करने का खेल ज़िला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक जारी है. धन की बंदरबांट के लिए चहेतों के नाम जॉब कार्ड बनाकर धन निकाल लिया जाता है. सरकार भी मानती है कि मनरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा है. सरकार के पास भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत कामगारों को जॉब कार्ड प्रदान नहीं किए जाने के बारे में शिकायतें आती हैं. हमने पहले भी इस कॉलम में मनरेगा के बारे में जानकारी दी है. इस अंक में एक बार फिर हम अपने पाठकों और उनके ज़रिए गांव-देहात के लोगों तक मनरेगा और जॉब कार्ड बनवाने से संबंधित जानकारी पहुंचा रहे हैं. हम पाठकों से अपेक्षा करते हैं कि वे गांव-देहात में रहने वाले लोगों को भी इस कॉलम के बारे में बताएंगे और दिए गए आवेदन के प्रारूप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे. सरकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार से लड़ने की चौथी दुनिया की मुहिम में आपका साथ भी मायने रखता है. यहां हम मनरेगा योजना से जुड़े कुछ सवाल आवेदन के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं. आप इस आवेदन के माध्यम से मनरेगा के तहत बने जॉब कार्ड, मस्टररोल, भुगतान, काम एवं ठेकेदार के बारे में सूचनाएं मांग सकते हैं, ताकि ज़रूरतमंदों तक इस सरकारी योजना का लाभ पहुंच सके. इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना में हुए विकास कार्यों की जांच के लिए सोशल ऑडिट किया जाना भी ज़रूरी होता है. इससे इस योजना में पारदर्शिता लाई जा सकती है. इसके लिए पंचायत स्तर पर ग्राम सभा के सदस्यों को भी अपनी तरफ़ से कोशिश करनी चाहिए. दरअसल, मनरेगा के तहत होने वाले काम का चयन भी अगर ग्राम सभा की खुली बैठकों में होगा तो फिर भ्रष्टाचार पर कुछ हद तक लगाम लगाई जा सकती है. अगर इस सबके बारे में सभी लोगों के सामने खुली बैठक हो तो फिर प्रधान भी बेईमानी करने से डरेगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

मनरेगा व जॉब कार्ड

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

दिनांक :

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 केतहत आवेदन.

महोदय,
.....ब्लॉक केग्राम.....केसंबंध में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं:

1. उपरोक्त गांव से एन.आर.ई.जी.ए.(नरेगा) केतहत जॉब कार्ड बनाने के लिए अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? इसकी सूची निम्नलिखित विवरणों केसाथ उपलब्ध कराएं:
क. आवेदक का नाम व पता
ख. आवेदन संख्या
ग. आवेदन की तारीख़
घ. आवेदन पर की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण (जॉब कार्ड बना/जॉब कार्ड नहीं बना/विचाराधीन)
ड. यदि जॉब कार्ड नहीं बना तो उसका कारण बताएं
च. यदि बना तो किस तारीख़ को

2. जिन लोगों को जॉब कार्ड दिया गया है, उनमें से कितने लोगों ने काम देने का आवेदन किया है? उसकी सूची निम्नलिखित सूचनाओं केसाथ उपलब्ध कराएं:
क. आवेदक का नाम व पता
ख. आवेदन करने की तारीख़
ग. दिए गए कार्य का नाम
घ कार्य दिए जाने की तारीख़
ड. कार्य के लिए भुगतान की गई राशि व भुगतान की तारीख़
च. रिकॉर्ड रजिस्टर के उस भाग की प्रमाणित प्रति जहां इनके भुगतान से संबंधित विवरण दर्ज हैं.
छ. यदि काम नहीं दिया गया है तो क्यों?
ज. क्या उन्हें बेरोज़गारी भत्ता दिया जा रहा है?

3. उपरोक्त गांव से एन.आर.ई.जी.ए. केतहत रोज़गार के लिए आवेदन करने वाले जिन आवेदकों को बेरोज़गारी भत्ता दिया गया या दिया जा रहा है, उनकी सूची निम्नलिखित सूचनाओं के साथ उपलब्ध कराएं:
क. आवेदक का नाम व पता
ख. आवेदन करने की तारीख़
ग. बेरोज़गारी भत्ता दिए जाने की तारीख़
ड. बेरोज़गारी भत्ता केलिए भुगतान की गई राशि व भुगतान की तारीख़
च. रिकॉर्ड रजिस्टर के उस भाग की प्रमाणित प्रति जहां इनके भुगतान से संबंधित विवरण दर्ज हैं.

मैं आवेदन शुल्क के रूप में ... रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

भवदीय

नाम:
पता:
हस्ताक्षर

राशिफल

मेष 21 मार्च से 20 अप्रैल

इस सप्ताह परेशानियों से घबराने की ज़रूरत नहीं है. बाधाओं और विरोधियों का सामना करना फ़िलहाल आपकी पहली प्राथमिकता है. आर्थिक तंगी के चलते पारिवारिक ज़रूरतें पूरी करने में विफल रहेंगे. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के योग बन रहे हैं.

वृष 21 अप्रैल से 20

इस सप्ताह घर से निकलने के बाद आपको किसी अवांछित तरीक़े की खोज में नहीं निकलना चाहिए. अगर आप सही बिंदु पर केंद्रित रहेंगे तो सप्ताहांत तक कोई अच्छा परिणाम आपको मिल सकता है. युवाओं को नौकरी में बदलाव के अवसर मिलेंगे.

मिथुन 21 मई से 20 जून

इस सप्ताह लंबे समय से पड़ा हुआ आपका वांछित लाभ फ़िलहाल कहीं पर अटका हुआ है, लेकिन सप्ताहांत में यह आपके हाथ में आ ही जाएगा. घर परिवार व सामाजिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लेने की ज़रूरत है.

कर्क 21 जून से 20 जुलाई

इस सप्ताह आपके शुभ काम में विरोधी और शत्रु कोई अड़ंगा नहीं डाल पाएंगे. आजीविका और कारोबार में सप्ताह के अंत में धन लाभ होगा. घर-परिवार के लोग भी आपकी सफलता से प्रसन्न रहेंगे.

सिंह 21 जुलाई से 20 अगस्त

इस सप्ताह अपने नए काम को शुरू करने के बारे में बार-बार दूसरों की सलाह लेना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है. अगर कोई पारिवारिक व्यक्ति आपको नेक सलाह दे रहा है तो उस पर सप्ताहांत तक अमल अवश्य करें.

कन्या 21 अगस्त से 20 सितंबर

जो काम आपने अभी अधूरे छोड़ रखे हैं इस सप्ताह उनको आगे बढ़ाएं, प्रयास सार्थक होंगे. परिवार के सदस्य कई दिनों के बाद आपको अच्छे मूड में देखकर कोई फ़रमाइश भी कर सकते हैं. आप जल्दबाज़ी के चक्कर में कोई ग़लती कर सकते हैं.

तुला 21 सितंबर से 20 अक्टूबर

इस सप्ताह अचानक कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है. किसी वजह से आपका मन चिंताग्रस्त रहेगा और किसी ज़रूरी काम के टल जाने या बिगड़ जाने का अफ़सोस भी रहेगा. दूसरों के मामलों में पड़ने से अपमान हो सकता है.

वृश्चिक 21 अक्टूबर से 20 नवंबर

इस सप्ताह आप कार्यक्षेत्र में आपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे. आपके कार्य सिद्ध होंगे, जो आपके लिए आश्चर्य और सुखद घटनाओं का प्रतीक बनेंगे. सप्ताह के अंत में आपके सहयोगी और सहकर्मी आपके लिए कुछ नई योजनाएं भी ला सकते हैं.

धनु 21 नवंबर से 20 दिसंबर

इस सप्ताह भविष्य के लिए लाभदायी योजना की शुरुआत होगी. आपको अचानक लंबी यात्रा पर जाना भी पड़ सकता है. सप्ताह के अंत में अच्छा यही होगा कि आप अपनी सूझबूझ और धैर्य से परिस्थितियों को टालने में सक्रिय रहें.

मकर 21 दिसंबर से 20 जनवरी

इस सप्ताह तेज़ी से बदलती परिस्थिति में ख़ुद को बदलना आपके हित में होगा. अगर यात्रा करनी है तो सुरक्षित स्थानों की ही यात्रा करें. सप्ताहांत में रास्ते में रुकावट आने से आपका समय बेकार जा सकता है. आय के नए स्त्रोत बनेंगे.

कुंभ 21 जनवरी से 20 फरवरी

इस सप्ताह अधिकारी आपके कामकाज से प्रसन्न रहेंगे. कुछ लोग आपकी प्रतिष्ठा व बढ़ते वर्चस्व से ईर्ष्या करेंगे. साझेदारी में दरार पड़ सकती है. धैर्य से काम लें. बुज़ुर्गों के स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो सकती है. आप कुछ नया करना चाहेंगे, लेकिन समय आपके अनुकूल नहीं है.

मीन 21 फरवरी से 20 मार्च

इस सप्ताह आप परिवार की ख़ुशियों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे. कोई महत्वपूर्ण योजना बीच में छोड़नी पड़ सकती है. कार्यक्षेत्र में दूसरों के सुझावों को सहज भाव से स्वीकार करने से लोग मदद को तैयार रहेंगे.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

सिर दर्द का इलाज महंगा पड़ेगा

एक यूरोपीय शोध के मुताबिक़, दर्द से निजात पाने के लिए एस्प्रिन नहीं लेने वाले लोगों के मुक़ाबले रोज़ाना एस्प्रिन लेने वाले बुज़ुर्गों को ऐसी बीमारी होने का ख़तरा दोगुना हो जाता है, जिसमें आंख की रोशनी चली जाती है. अक्सर दर्द निवारक दवा एस्प्रिन का इस्तेमाल करने वाले बुज़ुर्गों को आंख से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं. एक शोध में पता चला है कि इससे आंख की रोशनी जाने का ख़तरा रहता है. यह बीमारी बढ़ती उम्र से जुड़ी है. शोध के तथ्य इलाज की नई तकनीकों से जुड़ी पत्रिका ऑप्थलमोलॉजी में छपे हैं. आंकड़ें यह नहीं बताते कि एस्प्रिन की वजह से आंख की रोशनी जाती है, लेकिन यह चिंता की बात है कि एस्प्रिन की वजह से आंख में होने वाली गड़बड़ी बढ़ती है. हृदय रोग की बीमारी से जूझ रहे बहुत से बुज़ुर्ग एस्प्रिन का इस्तेमाल करते हैं. बॉस्टन के महिला अस्पताल के डॉक्टर विलियम क्रिश्टेन के मुताबिक़, जिन लोगों को बढ़ती उम्र के साथ दृष्टि से जुड़ी मैकुलर डीजेनरेशन की समस्या है, उन लोगों को शायद एस्प्रिन लेने की सिफ़ारिश नहीं करना बुद्धिमानी है. नीदरलैंड के न्यूरोसाइंस इंस्टीट्यूट और अकेडमी मेडिकल सेंटर ने क़रीब 4700 लोगों से स्वास्थ्य और जीवन शैली से जुड़ी जानकारी जमा की. शोध में नार्वे, एस्टोनिया, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस और स्पेन के उन लोगों को शामिल किया गया, जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है. रोज़ाना एस्प्रिन लेने वाले 839 लोगों में से 36 लोगों में वेट मैकुलर डीजेनरेशन बीमारी पाई गई. वहीं अकसर कम एस्प्रिन लेने वाले 100 लोगों में से दो लोगों को ऐसी बीमारी है. आंखों में ख़ून की नसें लीक होने के कारण वेट फॉर्म जैसे हालात बनते हैं जिससे आंख की रोशनी जाने का ख़तरा होता है. ड्राई फॉर्म ज़्यादा आम है और कम गंभीर है. शोधकर्ताओं ने पाया कि एस्प्रिन का इस्तेमाल न तो ड्राई फॉर्म से जुड़ा हुआ है और न ही बीमारी के शुरुआती चरणों से.

जेम्स बॉन्ड की रियल कार

कारों में महारत हासिल करने वाली जर्मन कंपनी बीएमडब्ल्यू इस दिशा में काम कर रही है कि कारें ख़ुद ब ख़ुद चलें. म्यूनिख में प्रोजेक्ट लीडर निको केम्पशन का कहना है कि भविष्य में सभी कारें ऑटो पायलट पर चला करेंगी. रडार, लेजर और कैमरों की मदद से कारें अपना रास्ता ख़ुद ही ढूंढ लेंगी. हालांकि इसके लिए इंतज़ार करना होगा. फ़िलहाल निको केम्पशन ऑप्टिमाइजिंग असिस्टेंस सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जो कार चलाने में कई तरह से मददगार साबित हो सकता है. मौजूदा आधुनिक कारों में पार्किंग असिस्टेंट की सुविधा आम हो गई है, जिनमें आगे और पीछे सेंसर लगे होते हैं. केवल एक बटन दबाने से कार पार्किंग के लिए तैयार हो जाती है और अपने लिए जगह खोज लेती है. ड्राइवर को केवल एक्सलरेटर और ब्रेक का ध्यान रखना होता है, और छोटी से छोटी जगह में इसकी मदद से कार पार्क करना संभव हो पाता है. इस पार्क असिस्ट की क़ीमत तीस से साठ हज़ार रुपये के बीच है.

जर्मनी की तकनीकी परीक्षण संस्था कुएस के हांस गेओर्ग मार्मिट की सलाह है कि इस तरह की तकनीक में और निवेश करना चाहिए. कार पार्क करते वक़्त गाड़ी को अगर ज़रा सी भी टक्कर लग जाए तो आपको अपनी कार की मरम्मत का भी ख़र्च उठाना पड़ता है और जिसके साथ टक्कर हुई है उसका भी. बीएमडब्ल्यू और वोल्क्सवागेन कंपनियों में इस बात पर शोध चल रहा है कि ड्राइवर के कार में बैठे बिना ही उसे किस तरह पार्क किया जा सके. इस तरह के सिस्टम से कार को ऐसी तंग जगह पर पार्क करने में मदद मिलेगी, जहां पार्क करने के बाद ड्राइवर कार से बाहर नहीं निकल सकता. कार को पार्किंग से निकालने के लिए आपको बस रिमोट कंट्रोल का बटन दबाना है, कार का इंजन अपने आप शुरू हो जाएगा और कार ख़ुद ही बाहर निकल आएगी. हालांकि दोनों ही कंपनियां अभी भी यह बताते हुए हिचकिचा रही हैं कि इस तरह का सिस्टम बाज़ार में कब उपलब्ध होगा. लोगों के लिए ऐसे सिस्टम बेहद रोमांचक तो हैं, लेकिन साथ ही इस बात का डर भी है कि इससे कार पर उनका कोई नियंत्रण नहीं रहेगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

पहली बात तो यह है कि जिस कश्मीर में चीनी सैनिक होने की बात जनरल ने कही, उसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है.

चीन की सरकार डर गई है

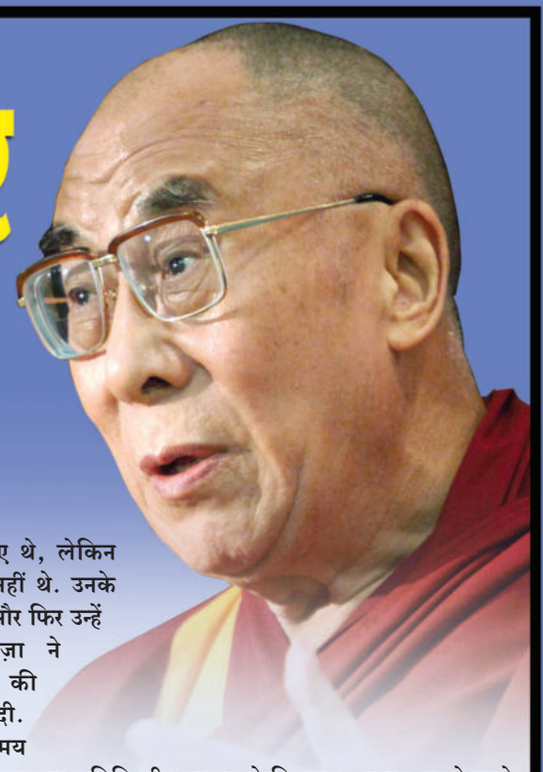

राजीव रंजन तिवारी

वर्ष 2010–11 दुनिया के विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली की समृद्धि के लिए हुई क्रांतियों का गवाह रहा है. इस दरम्यान न सिर्फ आंदोलनकारी चर्चा में रहे, बल्कि कथित तानाशाह शासक भी. चीन में भी लोकतंत्र की बहाली के लिए जमीन तैयार की जा रही है. इसके लिए रणनीति मुख्य रूप से तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा एवं चीनी मानवाधिकार कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं, जिन्हें अमेरिका एवं भारत जैसे कुछ देशों का परोक्ष समर्थन भी प्राप्त है. लू श्याबाओ समर्थक मानवाधिकार कार्यकर्ता और दलाई लामा लोकतंत्र की स्थापना के लिए चीन के विरुद्ध न केवल बाहर, बल्कि देश के अंदर भी जनमत तैयार करने में लगे हुए हैं. यही वजह है कि चीन सरकार द्वारा उन्हें रोकने के लिए की जा रही तमाम कोशिशों के बावजूद उनका काम है. हाल में दलाई लामा ने अफ्रीका में वीडियो लिंक के जरिए चीन के खिलाफ जमकर आग उगली.

दरअसल, दलाई लामा नोबेल पुरस्कार विजेता आर्चबिशप डेसमंड टूटू का जन्मदिन मनाने दक्षिण अफ्रीका जाने वाले थे, लेकिन बाद में उन्हें अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका सरकार ने समय रहते उन्हें वीज़ा नहीं दिया. उसने ऐसा चीन के दबाव में किया. हालांकि दक्षिण अफ्रीका कहता है कि उस पर चीन का कोई दबाव नहीं था. दोनों नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बीच यूनिवर्सिटी ऑफ़ द वेस्टर्न केप में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई. दलाई लामा यहीं पर डेसमंड टुटू के 80वें जन्मदिवस पर भाषण देने वाले थे. जब दलाई लामा को वीजा नहीं दिया गया तो आर्चबिशप ने दक्षिण अफ्रीका सरकार की तीखी आलोचना की. उन्होंने कहा कि वीज़ा न देना रंगभेद से भी खराब है. दक्षिण अफ्रीकी संसद के बाहर भी विरोध प्रदर्शन हुए. पिछले दो वर्षों में यह दूसरी बार है, जब दक्षिण अफ्रीका में दलाई लामा का दौरा रद्द हुआ. चीन दलाई लामा को एक ख़तरनाक पृथकतावादी मानता है, जो तिब्बत को चीन से अलग करना चाहता है. जबकि दलाई लामा बार–बार कहते हैं कि उनका मकसद तिब्बत को स्वायत्तता दिलाना है, आज़ादी नहीं. नोबेल पुरस्कार विजेता डेसमंड टूटू से चर्चा में लामा ने कहा कि सच बोलकर उन्होंने चीन को असहज महसूस कराया है. कुछ चीनी अधिकारी मुझे दैत्य कहते हैं. ज़ाहिर है, कुछ लोग इस दैत्य से डरते हैं. जो लोग सच बोलते हैं, उनसे चीन असहज महसूस करता है. लामा के वक्तव्य से चीन के हालात के प्रमाण मिल रहे हैं. इसके अलावा शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा समेत कई नेताओं ने चीन से लू श्याबाओ की रिहाई की अपील की. लू श्याबाओ को पिछले वर्ष शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. नोबेल शांति पुरस्कार समिति ने कुछ दिनों पहले ही इस वर्ष के विजेताओं के नामों की भी घोषणा कर दी, पर लू श्याबाओ के जीवन में कुछ नहीं बदला. अक्टूबर 2010 से वह जेल में हैं और सत्ता को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में 11 वर्ष की सज़ा काट रहे हैं. श्याबाओ को नोबेल पुरस्कार देते समय सोचा गया होगा कि इससे इस मानवाधिकार कार्यकर्ता के जीवन में कुछ बदलाव आएगा, उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा अथवा उनकी सजा कम कर दी जाएगी, लेकिन हुआ इसके विपरीत. उन पर और भी कड़ी नजर रखी जाने लगी. उनकी पत्नी लूशिया को घर में ही नज़रबंद करके रखा गया है. कई चीनी सामाजिक कार्यकर्ता सरकार के निशाने पर हैं. ऐसा भी नहीं है कि चीन में मानवाधिकारों पर बहस ख़त्म हो गई हो. लू श्याबाओ समर्थक मानवाधिकार कार्यकर्ता देश में लोकतंत्र के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए अभियान छेड़े हुए हैं. लू श्याबाओ को वर्ष 2009 में क्रिसमस के दिन सज़ा सुनाई गई थी. उनका जुर्म था राजनीतिक बदलाव की पैरवी करने वाले एक घोषणापत्र को लिखने में सहायता देना. वह 20 वर्षों से इन मुद्दों पर आवाज़ उठाते आए थे, लेकिन उस वक्त वह चर्चित नहीं थे. उनके द्वारा लिखे घोषणापत्र और फिर उन्हें सुनाई गई कड़ी सज़ा ने अचानक उन्हें दुनिया की नज़रों में जगह दे दी. संयोगवश यह उस समय हुआ, जब नोबेल शांति पुरस्कार समिति चीन सरकार के ख़िलाफ आवाज़ उठाने वाले कार्यकर्ता की तलाश कर रही थी. समिति के स्थायी सचिव गीर लुंडेस्टैड ने कुछ दिनों पहले कहा था कि अपने अनुभवों से हम जानते थे कि चीन में सत्ता विरोधी स्वर बंटे हुए हैं. एक तरीके से चीन सरकार ने हमारे लिए फैसला आसान कर दिया. पुरस्कार की घोषणा होने तक लू श्याबाओ की पत्नी लूशिया नियमित रूप से उनसे जेल में मिलने जाती थीं, लेकिन फिर सब बदल गया. लूशिया अचानक ग़ायब हो गईं. बीजिंग में उनके घर के बाहर कड़ा पहरा हो गया. मनमानी नज़रबंदी पर संयुक्त राष्ट्र के वर्किंग ग्रुप ने पिछले वर्ष जब सवाल उठाए तो चीन सरकार ने कहा कि लूशिया पर कोई क़ानूनी रोक–टोक नहीं है, लेकिन चीन सरकार के इस कथन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि लू श्याबाओ को पुरस्कार दिए जाने की घोषणा के बाद से उनकी पत्नी लूशिया सार्वजनिक स्थानों पर नहीं दिखाई देतीं. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों और इंटरनेट के माध्यम से अपना विरोध प्रकट करने वालों के लिए ज़िंदगी काफी कठिन हो गई है.

मध्य–पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में हो रहे राजनीतिक परिवर्तनों ने चीनी नेताओं को भी डरा दिया है. उन्हें इस बात का डर है कि कहीं चीन में भी ऐसा कोई आंदोलन शुरू न हो जाए. चीन में पहले भी लोकतंत्र की बहाली के लिए आंदोलन हुए, लेकिन सरकार ने उन्हें बेरहमी से कुचल दिया. चीन सरकार को फिर से वही आशंका है. इसलिए हर विरोधी स्वर दबाया जा रहा है. लोगों को डराया–धमकाया जा रहा है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है. चाइनीज ह्यूमन राइट डिफेंडर के मुताबिक, एक चीनी नागरिक को पहली बार शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने से देश में मानवाधिकारों की स्थिति बदलेगी. हाल की घटनाओं से यही लगता है कि चीन सरकार डर गई है, उसे अब दलाई लामा से पहले से अधिक डर लगने लगा है. इसलिए वह दलाई लामा को भी भारत में ही कैद कर देना चाहता है. दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा उन्हें वीजा उपलब्ध न कराना इसका ताजा उदाहरण है.

feedback@chauthiduniya.com

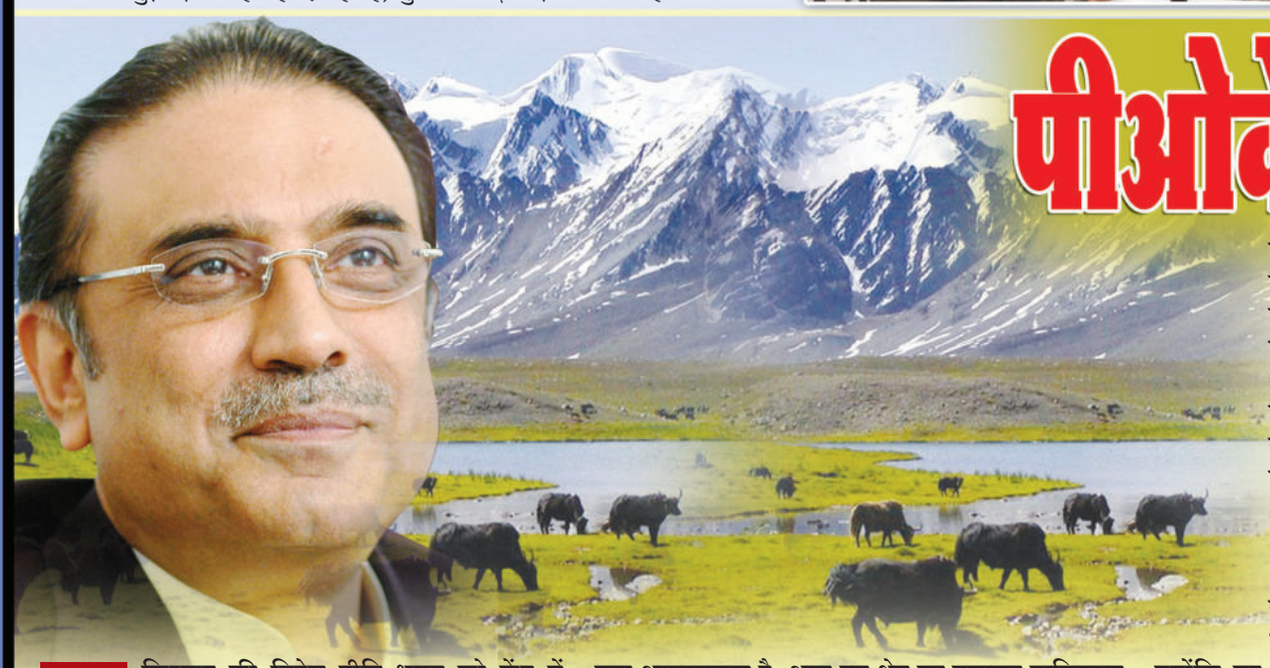

पीओके, पाकिस्तान और चीन

पाकिस्तान की विदेश नीति भारत को केंद्र में रखकर बनाई जाती है. उसने यह सोच रखा है कि जो भारत के हित में हो, वह उसका विरोध करेगा, चाहे उसके हित में हो अथवा नहीं. लेकिन उसे अभी तक यह समझ में नहीं आ रहा है कि केवल भारत को कमज़ोर करने के लिए वह जो कर रहा है, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान उसी को हो सकता है. अभी कुछ दिनों पहले भारत के थलसेना अध्यक्ष जनरल वी के सिंह ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर में 4000 चीनी मौजूद हैं, जिनमें सैनिक भी हैं. हालांकि जनरल सिंह के इस बयान का पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने खंडन किया. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता तहमीना जंजुआ ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि आजाद कश्मीर में जो काम हो रहा है, वह केवल विकास के लिए है और उसमें चीन के आम शहरी भाग ले रहे हैं, न कि सैनिक. तहमीना ने यह भी कहा कि उन्होंने जनरल सिंह का बयान नहीं सुना. जनरल सिंह ने यह भी कहा था कि पाक अधिकृत कश्मीर में निर्माण कार्यों में जो चीनी इंजीनियर लगे हुए हैं, उनका संबंध सेना से है और ऐसा भारतीय सेना में भी होता है कि इंजीनियरों के पास लड़ाकू क्षमता होती है. ऐसे में यह कहा जा सकता है कि पाक अधिकृत कश्मीर में काम करने वाले इंजीनियर चीनी सेना से जुड़े हुए हैं. भारतीय सेनाध्यक्ष के बयान पर अविश्वास करने की कोई वजह नहीं दिखाई देता, लेकिन पाकिस्तान इंकार करता है कि इस इलाके में चीनी सैनिक नहीं हैं, यह सोचने की बात है. आखिर पाकिस्तान ने ऐसा क्यों कहा, क्या उसे जनरल सिंह के बयानों का खंडन करने की आवश्यकता थी.

पहली बात तो यह है कि जिस कश्मीर में चीनी सैनिक होने की बात जनरल ने कही, उसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है. अगर वह आजाद है तो फिर उसकी तरफ से पाकिस्तान ने ऐसा क्यों कहा कि वहां चीनी सेना नहीं है. आजाद कश्मीर के प्रतिनिधियों की तरफ से अगर यह कहा जाता तो बात कुछ और थी. इस बयान से पाकिस्तान ने यह साबित किया है कि कश्मीर का वह हिस्सा आजाद नहीं है, बल्कि उस पर उसका कब्जा है. भारतीय कश्मीर में रहने वाले पृथकतावादी लोग जो आजाद कश्मीर की बात करते हैं, उन्हें भी पाकिस्तान के इस बयान पर ध्यान देना चाहिए. दूसरी बात यह है कि अगर चीनी सैनिक पाक अधिकृत कश्मीर में हैं तो पाकिस्तान को इस बयान के खंडन की क्या आवश्यकता है. अगर उस क्षेत्र का प्रशासन पाकिस्तान संभालता है और वहां के निर्माण कार्यों में चीन सहयोग कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है. अगर चीन अपने इंजीनियरों या अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए अपने कुछ सैनिक वहां रखता भी है तो इसमें ग़लत क्या है. पाकिस्तान अगर कहता कि चीनी सैनिक अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए हैं, तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं थी. चीनी सैनिक कोई आतंकवादी तो हैं नहीं, जिनकी उपस्थिति की बात से हंगामा हो जाएगा. पाकिस्तान एक संप्रभु देश है और उसे अपनी सीमा के भीतर किसी भी देश के सैनिकों को रखने की पूरी आजादी है, बशर्ते वह कश्मीर के इस क्षेत्र का अपना भाग स्वीकार कर ले.

अब प्रश्न यह है कि पाकिस्तान में चीनी सैनिकों की उपस्थिति से नुकसान किसे है. भारत को इससे चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह तय है कि अगर भविष्य में कभी भी भारत विरोधी गतिविधियों के लिए चीन को पाकिस्तान की आवश्यकता होगी तो पाकिस्तान चीन के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि चीन को अपने यहां प्रश्रय देना उसके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है. चीन के जिनजियांग प्रांत में विद्रोह हो रहा है. कुछ दिनों पहले जब इस प्रांत में तुर्कीस्तान इस्लामिक मूवमेंट के लोगों ने आतंकवादी कार्रवाई की थी तो चीन ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, जिसके बाद पाक के नेताओं के होश उड़ गए थे. अगर चीन के इस प्रांत में पृथकतावादी ताकतें ज्यादा बढ़ जाती हैं और पाकिस्तान के कट्टरपंथी उन्हें समर्थन देते हैं तो ऐसी स्थिति में चीन के प्रकोप का सामना पाकिस्तान को करना पड़ेगा और उस समय पाकिस्तान स्थित चीनी सेना और उसके द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी पाकिस्तान को महंगी पड़ेगी. अंतरराष्ट्रीय राजनीति कब, किस ओर करवट ले लेगी, कहा नहीं जा सकता. पाकिस्तान को भी इस पर ग़ौर करना चाहिए और भारत केंद्रित अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए, वरना इसका खामियाजा उसे ही भुगतना पड़ेगा.

राजीव कुमार
feedback@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी
हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक
दो टूक–संतोष भारतीय के साथ
ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
स्पेशल रिपोर्ट
नायाब हैं हम–उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
साई की महिमा

एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा–201301 www.chauthiduniya.tv

गोपाल राव गुंड ने शिरडी में साई बाबा के भक्तों के सामने अपने विचार रखे, ताकि उनकी सहमति मिल सके. सबने इसका समर्थन किया. बाबा से अनुमति और आशीर्वाद मांगा गया जो उन्होंने दे दिया.

त्योहारों का समन्वय

साई बाबा का उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सद्भाव और समन्वय स्थापित करना जान पड़ता है. यही कारण रहा होगा कि वह रहते तो थे मस्जिद में, पर उसका नाम उन्होंने द्वारका माई रखा था. वह एक ओर तो संस्कृत के ज्ञाता थे और विशुद्ध रीति से वेद पाठ करते थे तो दूसरी ओर वह क़ुरआन की आयतें भी पढ़ते थे. वह पंढरपुर के विट्ठल भगवान के भक्त थे और राम, कृष्ण, श्री हरि के मानने वाले थे तो साथ ही उनके मुंह से हमेशा यही निकलता था कि अल्लाह मालिक है. साई बाबा जाति-पाति और धर्म के विवादों से ऊपर समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाले अवतार थे.

पूजा और त्योहार

साई बाबा अत्यंत उदार थे. उन्होंने अपने भक्तों को अपनी पूजा-अर्चना करने की पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी. वह तो भक्त वत्सल थे. उनके निवास स्थान को मस्जिद या मंदिर के बजाय आश्रम कहना ही अधिक उचित होगा. शिरडी ही क्या, दूर-दूर तक के लोग उनके जीवनकाल में ही उन्हें भगवान मानते थे. भक्तजन जल के अर्घ्य से उनका पद प्रक्षालन करते थे. मस्जिद या साई बाबा के आश्रम में चौबीसों घंटे धूनी जलती रहती थी. वहां शंख, झालर और घंटे बजाए जाते थे. भजन होता था और नाम सप्ताह का आयोजन किया जाता था, जिसमें अखंड राम धुन होती थी. भक्तजन साई बाबा को प्रातःकाल मंगल आरती, मध्याह्न की आरती और शाम को संध्या आरती करते थे. साधक, साधु, संत और संन्यासी भी मोक्ष की अभिलाषा से उनके पास आते थे. श्रेष्ठ अग्निहोत्री ब्राह्मण भी साई बाबा के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे. साई बाबा वर्ष में चार त्योहार मनाते थे. वे हैं- राम नवमी, जन्माष्टमी, संदल और ईद. इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में त्योहारों का समन्वय किया था. ईद पर वह नमाज़ पढ़ते और राम नवमी के दिन वेदपाठ करते थे. राम नवमी में नाम सप्ताह का और जन्माष्टमी में गोपाल काला का आयोजन किया जाता था.

राम नवमी और उर्स

पहले उर्स का आयोजन किया गया और उसके बाद राम नवमी का. कोपरगांव में गोपाल राव गुंड नाम का एक सर्किल इंस्पेक्टर साई बाबा का भक्त था. उसका कोई पुत्र नहीं था. साई बाबा के आशीर्वाद से उसका एक लड़का हुआ. इसी ख़ुशी में गोपाल राव गुंड के मन में शिरडी में उर्स और उर्स का मेला लगाने का विचार आया. यह बात 1897 की है. गोपाल राव गुंड ने शिरडी में साई बाबा के भक्तों के सामने अपने विचार रखे, ताकि उनकी सहमति मिल सके. सबने इसका समर्थन किया. बाबा से अनुमति और आशीर्वाद मांगा गया जो उन्होंने दे दिया. साई बाबा ने उर्स के लिए राम नवमी का दिन तय किया. ऐसा जान पड़ता है कि इसमें साई बाबा का रहस्य छिपा था. वह तो त्रिकालदर्शी और सर्वज्ञ थे. उनका उद्देश्य राम नवमी में उर्स का समावेश कर हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना था. शिरडी गांव था. वहां केवल दो कुंए थे, जिनमें से एक सूख गया था और दूसरे का पानी खारा था. उर्स और मेले में पीने के पानी की कठिनाई हो सकती थी जिसे पहले से ही दूर करना आवश्यक था. साई बाबा ने खारे पानी वाले कुंए में कुछ फूल डाले और उसका पानी मीठा हो गया. तात्या पाटिल ने काफ़ी दूर स्थित एक कुंए से भी पानी लाने की व्यवस्था की.

संदल का जुलूस

साई बाबा का एक भक्त था अमीर शक्कर दलाल. उर्स के साथ संदल के जुलूस को जोड़ देने का विचार उसके मन में आया. संदल का जुलूस मुसलमान संतों के सम्मान में निकाला जाता है. इसमें चंदन घिसकर थाली में रखते हैं. उस थाली को अगरबत्ती की सुगंध के साथ बैंड बाजा बजाते हुए जुलूस के रूप में गांव में घुमाते हैं. मस्जिद वापस आने पर उस घिसे हुए चंदन को नीम-वृक्ष के चबूतरे और द्वारका माई मस्जिद की दीवारों पर छिड़क देते हैं. साई बाबा ने संदल का जुलूस निकालने की अनुमति भी दे दी. शिरडी में उर्स और राम नवमी का जुलूस एक साथ निकालने की तैयारी शुरू हो गई. गोपाल राव गुंड का अहमद नगर में दामू अण्णा कसार नाम का एक मित्र था. उसने दो ब्याह किए थे, पर उसका भी कोई पुत्र नहीं था. साई बाबा के आशीर्वाद से उसके भी पुत्र हुए. गोपाल राव गुंड ने दामू अण्णा को एक सादा बड़ा झंडा बनवाकर देने को कहा, जो उसने दिया और नाना साहब निमोणकर से एक ज़री की किनारी वाला झंडा लिया गया.

उर्स मेले का प्रबंध

मेले के दिन वातावरण एकदम साफ़ था. शिरडी के छोटे-बड़े और अमीर-ग़रीब सभी मेले का प्रबंध करने में लगे थे. बाहरी प्रबंध का ज़िम्मा तात्या कोते पाटिल के पास था. भीतरी प्रबंध राधा कृष्णा माई नाम की बाबा की एक भक्त कर रही थी. राधा कृष्णा माई का घर मेहमानों से भरा हुआ था. वह सबके लिए मिठाइयां और भोजन बना रही थी. एक और काम राधा कृष्णा माई ने स्वेच्छा से अपने हाथ में ले लिया था. वह काम था मस्जिद की साफ़-सफ़ाई और दीवारों की पुताई करना. साई बाबा जिस दिन सोने के लिए चावड़ी चले जाते थे उस दिन वह मस्जिद की सफ़ाई करती थी. ग़रीबों को भोजन कराना भी कार्यक्रम में शामिल था. यह काम साई बाबा को अत्यंत ही प्रिय था. मेला निर्विघ्न संपन्न हुआ.

उर्स का राम नवमी में समावेश

उर्स और मेले का कार्यक्रम वर्ष प्रतिवर्ष चल रहा था. लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी. प्रारंभ से ही पांच हज़ार से लेकर सात हज़ार तक लोग एकत्र होते थे. यह संख्या कुछ ही वर्षों में बढ़कर पचहत्तर हज़ार हो गई. वर्ष 1912 में अमरावती के दादा साहब खापर्डे के साथ साई सगुणोपासना के रचयिता कृष्ण राव जागेश्वर भीष्म मेले में आए. वह दीक्षित बाड़ा में ठहरे. जब वह बरामदे में लेटे हुए थे और लक्ष्मण राव उर्फ़ काका महाजनी पूजा की सामग्री लेकर मस्जिद में जा रहे थे तब कृष्ण राव भीष्म के मन में एक विचार आया. उन्होंने काका महाजनी को बताया कि इस तथ्य में कोई ईश्वरीय व्यवस्था अवश्य ही है कि उर्स का मेला राम नवमी के दिन लगता है. भगवान राम का जन्मदिन राम नवमी सभी हिंदुओं को अत्यंत ही प्रिय है. तब राम नवमी का त्योहार क्यों न मनाया जाए. काका महाजनी को भीष्म का यह विचार बहुत पसंद आया और उन्होंने इसके लिए साई बाबा से अनुमति लेने की इच्छा व्यक्त की. राम नवमी का उत्सव मनाने के लिए कीर्तन करने वाला हरिदास प्राप्त करने की समस्या थी जिसका हल कृष्ण राव भीष्म ने स्वयं निकाल लिया. वह बोले कि राम जन्म पर मेरी रचना रामाख्यम पूरी हो चुकी है. मैं स्वयं कीर्तन करूंगा. काका महाजनी हारमोनियम बजाने के लिए राज़ी कर लिए गए. राधा कृष्णा माई से प्रसाद बनवाना तय किया गया. इसके बाद साई बाबा से अनुमति लेने के लिए मस्जिद गए. अंतर्यामी साई बाबा तो सब कुछ जानते थे. उन्होंने काका महाजनी से पूछा कि बाड़े में क्या बात चल रही थी? काका महाजनी चुप हो गए. तब बाबा ने भीष्म से पूछा कि तुम क्या चाहते हो? भीष्म ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोग राम नवमी उत्सव मनाना चाहते हैं. इसके लिए आपकी आज्ञा चाहिए. साई बाबा ने बड़ी प्रसन्नता से अनुमति दे दी. इससे लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई.

मां-बेटे की भक्ति

बायजा बाई और उसके बेटे तात्या कोते पाटिल का उल्लेख पहले भी कई बार आ चुका है. दोनों मां-बेटे के मन में साई बाबा के प्रथम दर्शन करने के साथ ही उनके प्रति अगाध श्रद्धा, अटूट प्रेम और अनन्य भक्ति थी. यह कहना अनुचित नहीं होगा कि शिरडी में साई बाबा के जितने भक्त थे, उन सबमें बायजा बाई और उसके बेटे तात्या कोते पाटिल का सर्वप्रथम स्थान था. परिणाम यह हुआ कि साई बाबा की उन दोनों पर सबसे अधिक कृपा थी. अंतर्यामी साई बाबा तो स्वयं भगवान थे और भगवान कभी पक्षपात नहीं करते. उनकी कृपा तो सब पर समान रूप से बरसती है. वर्षा का जल तो समान रूप से बरसता है, पर जिसका पात्र जितना बड़ा होता है उसे उतना ही अधिक जल मिलता है. इसमें वर्षा का कोई पक्षपात नहीं. इसी तरह जिसकी जितनी अधिक भक्ति होती है वह प्रभु का उतना ही अधिक कृपा-पात्र हो जाता है. तात्या कोते हमेशा साई बाबा के साथ रहता था और बायजा मां प्रतिदिन मस्जिद में जाकर साई को भोजन कराती थी.

बायजा के परिवार की स्थिति

बायजा बाई और तात्या कोते पाटिल की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी. उनके जीविकोपार्जन का कोई विशेष साधन नहीं था. तात्या कोते वन से लकड़ी बटोर कर ले आता और गट्ठा बनाकर बेच देता था. बस यही उनकी थोड़ी सी आमदनी थी जिससे वे कठिनाई से जीवन-निर्वाह कर रहे थे. अब साई बाबा की कृपा से उनकी दशा सुधरती जा रही थी. उनके जीवन में एक आश्चर्य हो रहा था. जब से साई बाबा शिरडी आए थे तब से तात्या कोते की लकड़ियों का गट्ठा रास्ते में ही बिक जाता था. रास्ते में कोई न कोई ग्राहक अवश्य ही मिल जाता और पूछता, ओ लकड़ी वाले, लकड़ी कितने की है? तात्या कहता, भाई जो मर्ज़ी हो दे दो, साई तेरा भला करे. वह ग्राहक एक रुपया देकर लकड़ियां ख़रीद लेता, जबकि लकड़ी चार आने की ही होती थी. एक दिन तात्या लकड़ी लाने के लिए जंगल में गया. वह लकड़ी इकट्ठी कर ही रहा था कि आकाश में काले बादल छा गए और गर्जना होने लगी. तात्या कोते चिंतित हो गया कि अब क्या होगा! उसने थोड़ी ही लकड़ी इकट्ठी की, उसे गट्ठे में बांधा और गांव की ओर चल पड़ा. गांव की सीमा पर पहुंचते ही तात्या को आवाज़ सुनाई दी, ऐ लकड़ी वाले. वह रुक गया, ख़रीददार की आवाज़ थी. वह बोला, लकड़ी चाहिए. तात्या ने गट्ठर उसकी ओर बढ़ा दिया. उस ग्राहक ने बिना कुछ कहे उसके हाथ पर एक रुपया रख दिया. तात्या के मुंह से आश्चर्य के साथ निकाल गया, एक रुपया! कम है तो और लो भाई कहकर ग्राहक ने एक रुपया और उसकी हथेली पर रख दिया. कम लकड़ी के लिए दो रुपये देने वाला उदार दाता कौन है - यह देखने के लिए तात्या ने आंखें ऊपर कीं तो वहां कोई नहीं था - न लकड़ी, न ग्राहक. दो रुपये लेकर वह घर आ गया और मां बायजा बाई के हाथ में रुपये देकर उसे पूरा क़िस्सा सुना दिया. मां-बेटे की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे. वह सब कुछ समझ गई और बोली, बेटा यह सब साई बाबा की करामात मालूम होती है. साई तो भगवान के अवतार और अंतर्यामी हैं. तात्या बोला, मुझे भी ऐसा ही लगता है मां. इस बारे में मैं साई बाबा से ज़रूर पूछूंगा. तात्या कोते पाटिल उत्सुकता लिए साई बाबा के निवास स्थान द्वारका माई मस्जिद की ओर चला. वहां पहुंचकर उसने साई बाबा को दंडवत प्रणाम किया और इसके पहले कि वह कुछ कहता, अंतर्यामी सर्वज्ञ साई बाबा बोल उठे, तात्या, तुझे तो तेरी मेहनत की कमाई मिलती है. फिर शंका क्यों? तेरे भाग्य में जो कुछ है वही तुझे मिलता है. तू तो मेरा भाई है. बायजा मां मेरी मां है. यह कहकर साई बाबा ने तात्या को अपने हृदय से लगा लिया.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

तक़रीबन साढ़े तीन महीने बाद एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे याद दिलाया कि हमें स्टैंप पेपर का कुछ रिफंड मिलना है. मैं अगले ही साप्ताहिक अवकाश में एडीएम कार्यालय पहुंचा.

अनंत विजय

अन्ना को समर्थन की वजह

पिछले दिनों जब दिल्ली में अन्ना हजारे का अनशन हुआ तो रामलीला मैदान में उमड़ी भीड़ देखकर अचंभा हुआ था. दिल्ली में लाखों लोग एक जगह किसी ख़ास मक़सद को लेकर जमा हो जाएं, यह लगभग अविश्वसनीय था. लेकिन ऐसा हुआ और लोग ख़ुद अन्ना के आंदोलन को समर्थन देने चले आए. अन्ना के समर्थन में रामलीला मैदान में सिर्फ़ दिल्ली की जनता ही नहीं पहुंची थी, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग वहां जमा हुए थे. वहां जाकर मैंने यह समझने की कोशिश की कि ऐसी कौन सी वजह है, जो लोगों को खींचकर ला रही है. लोगों से बातचीत करके कुछ समझ में आया, लेकिन जिस निष्ठा और कनविक्शन के साथ लोग वहां पहुंच रहे थे, उसे समझ नहीं पा रहा था.

कई लोगों से बात की. एक मित्र ने बताया कि एक दिन उनकी पत्नी घर से उनके दफ्तर पहुंचीं और रिसेप्शन पर कार की चाबी के साथ एक चिट छोड़ी, जिसमें लिखा था, मैं अन्ना हजारे के आंदोलन में शरीक होने के लिए रामलीला मैदान जा रही हूं. अगर तुमको वक़्त मिले तो मुझे लेने आ जाना, वरना मैं मेट्रो से घर आ जाऊंगी. मैं उन दोनों (पति-पत्नी) को कई वर्षों से जानता हूं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करने के बारे में भाभी सोच भी सकती हैं, यह मेरी समझ से परे था. मेरे मित्र ने बाद में बताया कि वह अन्ना इफेक्ट था. इस तरह के कई वाकए मेरे सामने आए तो मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा और प्रबल हो गई कि अन्ना में ऐसा क्या जादू है, जिससे लोग खिंचे चले जाते हैं. कई लोगों से बात की, काफी लेख पढ़े, फिर भी वजह का पता नहीं चल पाया. लेकिन अचानक मेरे ज्ञानचक्षु खुल गए. वाकया बेहद मजेदार है, आप भी सुनिए.

तक़रीबन चार महीने पहले किसी काम की वजह से स्टैंप पेपर ख़रीदना पड़ा था. ग़लत गणित की वजह से तक़रीबन दस हज़ार रुपये के स्टैंप पेपरों की ज़्यादा ख़रीद हो गई. हमें लगा कि पैसे बर्बाद हो गए, लेकिन हमारे वकील ने बताया कि स्टैंप पेपर वापस लौटाने का भी प्रावधान है. उसके लिए एडीएम कार्यालय जाना पड़ेगा. वकील साहब ने आनन-फानन इस बाबत एक आवेदनपत्र तैयार कर दिया और कहा कि इसे एडीएम कार्यालय में जमा करा दीजिए. मैं रजिस्ट्रार कार्यालय से एडीएम कार्यालय पहुंचा. वहां संबंधित बाबू से मिला तो उन्होंने बताया कि जिस वेंडर से स्टैंप पेपर ख़रीदा गया है, उससे प्रमाणित कराकर लाना होगा कि उक्त स्टैंप पेपर उसने ही बेचा है. मैंने उन्हें यह बताने की कोशिश की कि स्टैंप पेपर के पीछे बेचने वाले वेंडर की मुहर लगी है और उसका पूरा पता भी अंकित है, लिहाज़ा फिर से प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन बाबू तो ठहरे बाबू, लकीर के फकीर, टस से मस नहीं हुए और फिर अपनी बात दोहरा दी. मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, सो घर लौट आया.

तक़रीबन चार महीने पहले किसी काम की वजह से स्टैंप पेपर ख़रीदना पड़ा था. ग़लत गणित की वजह से तक़रीबन दस हज़ार रुपये के स्टैंप पेपरों की ज़्यादा ख़रीद हो गई. हमें लगा कि पैसे बर्बाद हो गए, लेकिन हमारे वकील ने बताया कि स्टैंप पेपर वापस लौटाने का भी प्रावधान है.

हफ्ते भर बाद जब दफ्तर से साप्ताहिक अवकाश मिला तो सुबह तक़रीबन ग्यारह बजे रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचा. वहां स्टैंप विक्रेता से मिला तो उसने कहा कि दो बजे आइए. मेरे पास इंतज़ार करने के अलावा कोई चारा नहीं था. तपती दोपहरी में कचहरी परिसर में इंतज़ार करता रहा. ठीक दो बजे उसके पास पहुंचा तो उसने वादे के मुताबिक़ स्टैंप पेपर पर लिखकर दे दिया. अब मैं विजेता के भाव से कचहरी परिसर से निकला और तीन-चार किलोमीटर की दूरी पर स्थित एडीएम कार्यालय पहुंचा और वहां बाबू की मेज पर उसी विजयी भाव से स्टैंप पेपर रखा और कहा कि चलिए इसे लौटाने की कार्रवाई शुरू करिए. मेरे उत्साह पर चंद पलों में पानी फेरते हुए उन्होंने कहा कि आप पोस्ट ऑफिस से एक रजिस्ट्री का लिफाफा ख़रीद कर और उस पर अपना पता लिखकर दे दीजिए.

मैं भागकर नीचे पोस्ट ऑफिस पहुंचा, तब तक पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका था. मैं हारे हुए योद्धा की तरह बाबू के पास पहुंचा और उनसे बताया कि पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका है. बाबू साहब जल्दी में लग रहे थे. उन्होंने बेहद अनौपचारिक अंदाज़ में कहा कि कोई बात नहीं, कल दे जाना. मेरे बहुत अनुरोध करने पर वह इस बात के लिए राजी हो गए कि मैं किसी और से लिफाफा भिजवा दूंगा. मैंने अपने एक मित्र से अनुरोध किया और उनसे वह लिफाफा भिजवा दिया. मेरे मित्र को साहब बहादुर ने बताया कि अब तीन महीने बाद आकर रिफंड ले जाएं. मुझे संतोष हुआ कि चलो तीन महीने बाद पैसे मिल जाएंगे. तब तक कचहरी और एडीएम कार्यालय के चार चक्कर लग चुके थे.

तक़रीबन साढ़े तीन महीने बाद एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे याद दिलाया कि हमें स्टैंप पेपर का कुछ रिफंड मिलना है. मैं अगले ही साप्ताहिक अवकाश में एडीएम कार्यालय पहुंचा. बाबू साहब अपनी सीट पर मौजूद थे. मैंने नमस्कार कर अपना नाम बताया. बेहद ही तत्परता से उन्होंने फाइल निकाली और कहा कि मैं अपने किसी परिचय पत्र की फोटो कॉपी उन्हें दूं. मैं मूर्ख-अज्ञानी बग़ैर फोटो कॉपी लिए वहां चला गया था. ख़ैर पास की एक दुकान से फोटो कॉपी कराकर उन्हें सौंप दी. उन्होंने भी मुझे स्टैंप पेपर के पीछे लिखकर दे दिया और कहा कि नीचे की मंजिल पर कोषागार कार्यालय है, वहां जाकर इसे जमा करा दूं. जब मैं उठने को हुआ तो बाबू साहब ने मुझे रजिस्ट्री वाला लिफाफा पकड़ा दिया और कहा कि रख लो, तुम्हारे काम आएगा. मैं हैरान कि अगर वापस ही करना था तो फिर मंगवाया क्यों, लेकिन यह बात पूछने का साहस नहीं था, सो लिफाफा लेकर नीचे उतर आया.

नीचे आकर मैं कोषागार के काउंटर पर पहुंचा और वहां मौजूद साहब को स्टैंप पेपर देकर कहा कि मेरा रिफंड दे दीजिए. उन्होंने मेरी तरफ़ ऐसे देखा, जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया हो. उन्होंने कहा कि आपके रिफंड का चेक बनेगा और उसके लिए आपको बैंक से अपना दस्तख़त प्रमाणित कराकर लाना पड़ेगा.

मैं झल्ला कर बोला कि अगर आप अकाउंट पेयी चेक बना रहे हैं तो दस्तखत प्रमाणित कराने की क्या ज़रूरत है. बाबू बहस करने के मूड में नहीं था. उसने मुझे सहायक कोषाधिकारी के पास भेज दिया. वहां पहुंचा तो सफारी सूट में एक बुजुर्ग शख्स बैठे थे. मैंने उनसे अपनी व्यथा सुनाई और अनुरोध किया कि रिफंड का चेक बनवा दें. उन्होंने बड़े रौब से और एहसान जताने वाले अंदाज़ में कहा कि बैंक से प्रमाणित कराकर ला दीजिए तो दो-एक दिन में चेक बनवा दूंगा. अब तक मेरा धैर्य साथ छोड़ने लगा था. मैंने सहायक कोषाधिकारी से पूछा कि वह किस नियम के तहत ऐसा कर रहे हैं, मुझे नियम दिखाएं. मेरे इतना पूछते ही वह भड़क गए, बोले, पंद्रह साल पहले का शासनादेश है, मैं कहां से लाऊं. बहस होते-होते गर्मागर्मी हो गई. मैंने कहा कि मैं आठ चक्कर लगा चुका हूं, लेकिन अभी तक रिफंड नहीं मिला. लिफाफे की बात भी उन्हें बताई. उनका तर्क था कि मैं उनके विभाग में तो पहली बार आया हूं, इसलिए मेरी नाराज़गी जायज़ नहीं है. वह सरकारी नियमों का हवाला देकर बैंक से दस्तखत प्रमाणित कराकर जमा कराने पर अड़े रहे. इसी बहस के दौरान मैंने उनसे कहा कि आप जैसे लोगों की वजह से ही अन्ना हजारे को अनशन करना पड़ता है. इतना सुनते ही वह ऐसे भड़के, जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखा दिया गया हो. अन्ना के नाम पर ही वह अड़ गए. उनकी इच्छा थी कि मैं अन्ना वाली बात वापस लूं, लेकिन मैं उस पर क़ायम रहा. लाख बहस करने के बाद भी वह नहीं माने. मुझे दो चक्कर और लगाने पड़े, तब जाकर रिफंड का चेक मिला. मेरे घर से कोषागार कार्यालय की दूरी बारह किलोमीटर है. मैं इस चक्कर में बुरी तरह खिन्न हो चुका था, लेकिन इस बात की ख़ुशी थी कि मुझे मेरे प्रश्न का जवाब मिल चुका था कि अन्ना हजारे को समर्थन क्यों मिला और हर तबके के लोग उनके साथ क्यों जुड़े. अन्ना का विरोध करने वालों को न यह वजह समझ में आएगी और न जनता का मिज़ाज.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

सर्वश्रेष्ठ पुस्तक समीक्षा

सिनेमा से कभी गुज़रो तो कुछ किरदार मिलते हैं

प्रकाम्य भदौरिया

धारावाहिक रामायण में राम का रोल निभाने वाले अरुण गोविल और अभिनेता संजीव कुमार में सहज ही कोई समानता नहीं दिखेगी, लेकिन दोनों के करियर का विश्लेषण करें, तब उनमें छवि की समानता नज़र आती है. एक तरफ़ गोविल हैं, जो राम की छवि के कुछ यूं शिकार हुए कि फिर कभी उससे बाहर नहीं निकल पाए और दूसरी तरफ़ संजीव कभी किसी छवि के मोहताज नहीं रहे. इस कूव्वत के साथ अभिनय किया कि समकालीन अभिनेत्री जया बच्चन के पिता, ससुर और पति के किरदार में बड़ी ख़ूबसूरती के साथ पेश आए. अभिनेताओं की इन्हीं छवियों से गुजर कर संजय दत्त की मुन्ना भाई छवि का गांधीगिरी तक पहुंचना ही प्रहलाद अग्रवाल की पुस्तक जुग-जुग जिए मुन्ना भाई: छवियों का मायाजाल का सार है. यह किताब असल में हिंदी फिल्मों के अभिनेताओं के उन किरदारों का फ्लैश बैक है जो हमारे दिलोदिमाग़ में आज भी चमक रहे हैं. यह सिनेमा के शुरुआती इतिहास के ज़रिए दादा साहेब फाल्के, भारत भूषण, के एल सहगल, दिलीप कुमार, राजकुमार, देव आनंद, राजेश खन्ना, राजकपूर, बलराज साहनी, अमिताभ, अक्षय, शाहरुख, सलमान और संजय दत्त जैसे अभिनेताओं की समीक्षा करती है. इससे इन अभिनेताओं के करियर की जमा पूंजी का पता चलता है और इस बात की तस्दीक होती है कि लोकप्रियता और छवि दोनों अलग-अलग चीजें हैं. प्रहलाद कुछ अभिनेताओं मसलन राजकुमार और राजेंद्र कुमार को कमतर अभिनेता बताते हुए अपने मूल कथानाक मुन्ना भाई यानी संजय दत्त पर आ जाते हैं कि किस तरह सालों से अभिनय करता यह बुजुर्ग अभिनेता मात्र एक किरदार की बदौलत न सिर्फ़ जवां हो गया है, बल्कि विख्यात हो गया है. किताब में एक जगह मेरा नाम जोकर के एक दृश्य का जिक्र है, जिसमें स्कूल टीचर माउथ ऑर्गन बजाते नन्हें जोकर से पूछती है कि वह कोई दूसरी धुन सीखना चाहता है तो जवाब में राजकपूर के बाल चरित्र में ऋषि कपूर कहते हैं कि एक ज़िंदगी के लिए एक ही धुन काफी है. यही मंत्र संजय पर भी खरा उतरता है. एक कलाकार के तौर पर संजय को इस किरदार ने यूं इज़्ज़त बख्शी, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो. इससे पहले प्रहलाद संजय की पारिवारिक पृष्ठभूमि को पूरे विवरण के साथ पेश करते हैं, फिर उनके अभिनय के कुछ पड़ावों से होते हुए खलनायक (1993) तक पहुंच जाते हैं. इस फिल्म की रिलीज के समय संजय की छवि कुछ यूं बदली कि लोग भूल गए कि रियल और रील लाइफ में फ़र्क़ होता है. ख़ैर, शाहरुख की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन संजय को जब लंबे और उबाऊ अभिनय के आईसीयू से बाहर लाया तो संजय मॉडर्न गांधी बन गए. ग़ौरतलब है कि यह रोल संजय से पहले हिरानी ने शाहरुख को ऑफर किया था. मुन्ना भाई एमबीबीएस और लगे रहो मुन्ना भाई के चरित्र रूपांतर भी दिलचस्प हैं. किताब में मुन्ना के किरदार पर इतनी गहराई से चर्चा है कि एकबारगी लगता है कि हिरानी ने भी इसके इतने पहलुओं पर ग़ौर नहीं किया होगा. यही लेखक की विशेषता होती है. प्रहलाद इससे पहले भी सिनेमा पर कई पुस्तकों का लेखन और संपादन कर चुके हैं, इसलिए हिंदी सिनेमा के इतिहास और वर्तमान पर उनकी मज़बूत पकड़ है, लेकिन वह कहीं-कहीं मुन्ना की छवि के मायाजाल में उलझ जाते हैं, जैसे देव आनंद का यह कहना कि पच्चीस साल बाद इसकी चमक बताएगी कि यह सितारा है या गुब्बारा. जो सितारे थे, चमकते ही रहे और जो गुब्बारे थे, वे आख़िर में गिर गए. यह बात तो सभी कलाकारों पर लागू होती है. संजय के अलावा कई और भी अभिनेता हैं, जिन्होंने कई महान छवियों का मायाजाल रचा है. गुलजार के शब्दों में कहें तो सिनेमा से कभी गुज़रो तो बहुत किरदार मिलते हैं, जिन पर रोशनी डाली जा सकती है. किताब में अभिनेत्रियों के कुछ किरदारों पर चर्चा न होना अखरता है. फिर भी सिनेप्रेमियों और खासकर साहित्यिक सिनेप्रेमियों के लिए यह किताब पढ़ने लायक़ है.

समीक्ष्य कृति : जुग-जुग जिए मुन्ना भाई : छवियों का मायाजाल
लेखक : प्रहलाद अग्रवाल
प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
मूल्य : 250 रुपये

feedback@chauthiduniya.com

किताब मिली

पुस्तक का नाम
पच्चीस बरस पच्चीस कहानियां
संपादन
राजेन्द्र यादव
प्रकाशक
राजकमल प्रकाशन
मूल्य
450 रुपये

यह किताब हंस में प्रकाशित पच्चीस कहानियों का संग्रह है.

सभी के लिए उपयोगी पुस्तकें

21st Century A DICTIONARY OF COMMON ERRORS ₹ 99
CROSS STITCH Manual Part - 1 ₹ 60
Cross-Stitch Manual Part - II ₹ 70
21st Century DICT ENGLISH - HINDI ₹ 75
21 Century DICT. English-English-Hindi ₹ 125
वज़न कम करने के सरल उपाय ₹ 50
इंगलिश सीखिए और बोलिए ₹ 199
Stop Worrying Start Living ₹ 50
Successful Techniques to Improve Your Personality ₹ 99
★ VASTU SHASTRA ₹ 70
WORD POWER ₹ 20
WORD POWER MADE EASY ₹ 80
★ Love Letters ₹ 30
Think Positive Act Positive ₹ 70
Treasury of Idiom & Phrases ₹ 75
How to be an Entrepreneur ₹ 50
Unique Letter Writing ₹ 45
Guide to Good Health ₹ 40
Handbook of Synonyms, Antonyms & Homonyms ₹ 75
Homoeopathic Remedies ₹ 40
How to Lose Weight ₹ 50
Nature Cure ₹ 35
A Modern Approach to Personality Development ₹ 45
★ Yogic Cure ₹ 40
★ Healing with Reiki ₹ 60
★ हिन्दी संस्करण भी उपलब्ध है।

ब्राईट पब्लिकेशंस
भारत में सर्वाधिक बिकने वाली प्रतियोगिता पुस्तकों के प्रकाशक
2767, कूचा चैलान, दरियागंज, दिल्ली-110002 (भारत) (स्थापित : 1968)
फोन : 011-64632226, 23282226, 23283226 — फैक्स : 011-23269227
ई-मेल: sales@brightpublications.com | वैब साइट: http://www.brightpublications.com

टैंगो टीआरएक्स को आप चाहें तो स्पीकर फोन की तरह प्रयोग कर सकते हैं. ज़्यादातर म्यूज़िक लवर न्यूट्रल साउंड क्वालिटी पसंद करते हैं.

टेक्नो का 4 सिम मोबाइल फोन

लगता है कि अब ड्यूल सिम फोन के दिन लदने वाले हैं. जब बाज़ार में 4 सिम के साथ आपको लक्जरी फोन मिलेगा तो ड्यूल सिम फोन को कौन पूछेगा. टेक्नो टेलीकॉम कंपनी जल्द ही 4 सिम के साथ एक नया फोन लांच करने वाली है, जिसमें यूजर बिना किसी सिम को बंद किए या फिर चेंज किए चार अलग-अलग नेटवर्क से कनेक्ट रह सकता है. कंपनी के अनुसार, वह लोगों को कम क़ीमत में अच्छी क्वालिटी के मोबाइल हैंडसेट उपलब्ध कराना चाहती है और उसका नया हैंडसेट टी-4 जल्द ही बाज़ार में आ जाएगा. ऐसे में मोबाइल बाज़ार की दिग्गज कंपनियों नोकिया और सैमसंग पर भी दबाव पड़ सकता है. फ़िलहाल भारतीय बाज़ार में किसी भी बड़ी कंपनी का 4 सिम मोबाइल फोन उपलब्ध नहीं है. कंपनियों के बीच आगे निकलने की होड़ मची हुई है, जिसके चलते उनके टैरिफ प्लान में कोई ख़ास अंतर नहीं है. इस वजह से लोग एक से ज़्यादा नेटवर्क की सर्विस का प्रयोग करना चाहते हैं. दो सिम वाले हैंडसेटों में सिम बदलने या फिर एक नेटवर्क के दौरान दूसरे नेटवर्क के काम न करने जैसी परेशानियां हैं, मगर टेक्नो के नए टी-4 में हर समय चारों नेटवर्क काम करते रहेंगे. यूजर चाहे तो टी-4 में एक फोन कॉल रिसीव करने के साथ ही दूसरे नेटवर्क की कॉल भी रिसीव कर सकता है. हाल में टेक्नो ने अपने 4 सिम वाले मोबाइल को केन्या के बाज़ार में लांच किया. इस हैंडसेट की शुरुआती क़ीमत 15,000 रुपये है. कंपनी भारत में भी टी-4 को इसी क़ीमत में लांच करेगी.

रोबोट सुनाएगा म्यूज़िक

म्यूज़िक गैजेट के क्षेत्र में जानी-मानी कंपनी ओलोजिक ने एंड्रॉयड बेस्ड नया रोबोटिक म्यूज़िक प्लेयर लांच किया है, जिसमें ऑटोमेटेड म्यूज़िक पर्सनालिटी तकनीक का प्रयोग किया गया है. ओलोजिक के रोबोटिक म्यूज़िक प्लेयर में दो हाथों के साथ-साथ बैलेंसिंग के लिए दो पैर भी दिए गए हैं, जिससे यह चारों ओर चहलकदमी कर सकता है. प्लेयर में म्यूज़िक को शेयर करने के लिए ब्ल्यूटूथ की सुविधा है. ओलोजिक अपने इस अनोखे म्यूज़िक प्लेयर को मार्केटिंग के हिसाब से बाज़ार में पेश करेगा. अगर आप इस रोबोटिक म्यूज़िक प्लेयर को ख़रीदना चाहते हैं तो यह यूएस के बाज़ार में 400 डॉलरों में ऑनलाइन उपलब्ध है. रोबोटिक प्लेयर के सीने में म्यूज़िक कंट्रोल के लिए कई बटन हैं, जिनसे आप प्लेयर को एक्सेस कर सकते हैं. इसके अलावा ओलोजिक रोबोटिक प्लेयर के ऊपरी भाग को निकालने के बाद आप इसमें आईपैड या आईफोन अटैच कर सकते हैं. कंज्यूमर उत्पाद बनाने वाली कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक भी यूएस में रोबोकिंग नामक एक होमबोट रोबो पेश कर चुकी है. होमबोट में आईफोन और एंड्रॉयड एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करने की सुविधा है. रोबोट में लगा कैमरा अपने आसपास होने वाली सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता रहता है. ख़ास बात यह है कि इसमें दिया गया वैक्यूम क्लीनर आपके पूरे घर की साफ-सफाई बड़े आराम से करता है. इसकी क़ीमत 35,000 से लेकर 50,000 रुपये तक है.

थ्री डी हुआ लैपटॉप

सोनी अपने हाई क्वालिटी उत्पादों और नए डिज़ाइन प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है. कंपनी शीघ्र ही अपनी वॉयो एस सीरीज के तहत एक नया 3-डी लैपटॉप बाज़ार में पेश करेगी. इस लैपटॉप में आप सिर्फ़ एक क्लिक से सिस्टम की स्क्रीन को 2-डी से 3-डी व्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं. वॉयो एस में हाई डेफिनेशन वेब कैम इनबिल्ड है, जो यूजर को वीडियो चैटिंग के दौरान क्रिस्टल क्लीयर पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करता है. यह वेब कैम यूजर की आंखों की हलचल के हिसाब से 3-डी पिक्चर प्रोवाइड करता है. इस लैपटॉप में इंटेल का कोर आई 7 प्रोसेसर है, जो अब तक का सबसे उन्नत प्रोसेसर है. इसमें 32 बिट का विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है. 3-डी लैपटॉप है तो ज़ाहिर सी बात है कि इसका स्क्रीन साइज भी अच्छा होना चाहिए. वॉयो एस में 1920/1080 के हाई रेज्योलूशन सपोर्ट के साथ 16.4 इंच की बड़ी स्क्रीन है, जो यूजर को मूवी और वीडियो देखने की सुविधा देगी. अगर आप वॉयो एस की मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए लैपटॉप में माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट की सुविधा मौजूद है. इसके अलावा ब्ल्यूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ब्लूरे डिस्क भी है, जो साधारण डिस्क के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है. पैनड्राइव या एक्सटर्नल स्पीकर अटैच करने के लिए इसमें 2.0 और 3.0 वर्जन के यूएसबी पोर्ट ऑप्शन मौजूद हैं. 3.2 किलोग्राम भार वाले वॉयो एस में लीथियम ऑयन बैट्री दी गई है, जो अच्छा बैकअप प्रोवाइड करेगी. इस समय अन्य ब्रांडों में 3-डी लैपटॉप की कीमत काफी ज़्यादा है, मगर जानकारों के का कहना है कि कंपनी अपना 3-डी वॉयो एस लैपटॉप 40,000 रुपये की अनुमानित क़ीमत में लांच करेगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

टैंगो स्पीकर

म्यूज़िक डिवाइस बनाने वाली एक्ट्रीम मैक्स ने आईपॉड और आईफोन के लिए टैंगो नामक नए स्पीकर बाज़ार में पेश किए हैं. इनमें ब्ल्यूटूथ, सांग नेवीगेशन एवं वॉल्यूम कंट्रोल के अलावा बास कंट्रोल जैसे शानदार फीचर्स हैं. टैंगो टीआरएक्स को आप चाहें तो स्पीकर फोन की तरह प्रयोग कर सकते हैं. ज़्यादातर म्यूज़िक लवर न्यूट्रल साउंड क्वालिटी पसंद करते हैं. टैंगो में यूजर को ध्यान रखते हुए साउंड इक्यूलाइज का ऑप्शन है. अगर आपके पास आईफोन है तो ब्ल्यूटूथ द्वारा आप आईफोन से स्पीकरों में म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं. धुन बदलने के लिए 5 बैंड इक्यूलाइज का ऑप्शन दिया गया है. कुल मिलाकर टैंगो स्पीकर सिस्टम एक कंप्लीट म्यूज़िक किट है. बाज़ार में यह 12,000 रुपये में उपलब्ध है.

यह हेडफोन ख़ास है

हेडफोन से म्यूज़िक सुनने में कुछ अलग ही आनंद मिलता है, मगर जब एक से ज़्यादा लोग म्यूज़िक सुनना चाहते हों तो क्या करना चाहिए? जूमरिड ने इस समस्या का हल हाईब्रिड हेडफोन के रूप में खोज निकाला है. हाईब्रिड हेडफोन में इंटरनल स्पीकरों के साथ एक्सटर्नल स्पीकर भी हैं, जिनसे न केवल आप, बल्कि आसपास मौजूद लोग भी म्यूज़िक सुन सकेंगे. स्पीकरों में लेफ्ट और राइट दोनों तरफ़ स्पीकर दिए गए हैं. म्यूज़िक प्ले करते समय आप स्पीकरों के मोड को बदल भी सकते हैं. हेडफोन की डिज़ाइन देखने में कूल है, इसकी बॉडी प्लास्टिक से बनी है, जो इसे अतिरिक्त मज़बूती देती है. हेडफोन को अटैच करना काफी आसान है. इसके लिए हेडफोन में दी गई केबल स्पीकर से अटैच करनी पड़ती है. हेडफोन के साइड में दिए गए शॉर्ट बटन से आप स्पीकर और हेडफोन के मोड को अपनी सुविधानुसार बदल सकते हैं. स्पीकर एक बार पूरी तरह रिचार्ज हो जाने के बाद 4 घंटे का बैट्री बैकअप देते हैं. यह बैट्री बैकअप केवल एक्सटर्नल स्पीकरों के लिए है, इंटरनल स्पीकरों में कोई भी बैट्री बैकअप नहीं दिया गया है. बाजार में जूमरिड हाईब्रिड स्पीकर लाल, काले और सफेद रंगों में उपलब्ध हैं. जूमरिड एक्स-2 हाईब्रिड स्पीकर सभी बड़े ऑडियो स्टोर्स में 8000 रुपये में उपलब्ध हैं.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

बंगलुरु को सबसे बड़ा झटका तब लगा, जब तूफ़ानी बल्लेबाज़ क्रिस गेल हरभजन सिंह की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए. दिलशान और गेल के जाने से मुंबई इंडियंस के गेंदबाज़ों के हौसले काफ़ी बढ़ गए.

मुंबई इंडियंस

चैंपियंस के चैंपियन

राजेश एस कुमार

अभी हाल ही चेन्नई में ट्वेंटी–20 चैंपियंस लीग में मुंबई इंडियंस ने अपनी बादशाहत कायम कर ली. यह पहला मौक़ा था, जब मुंबई इंडियंस ने ट्वेंटी–20 का फाइनल जीतकर खिताब पर क़ब्ज़ा किया. नया विजेता बनकर जब मुंबई इंडियंस चेन्नई में चैंपियंस लीग के फ़ाइनल मुक़ाबले में अपनी जीत के क़रीब पहुंच रहा था, तब उस वक़्त उसके पास अपना सबसे बड़ा स्टार यानी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी नहीं था. इसके बावजूद हारी हुई बाजी को मुंबई इंडियंस ने जिस तरह जीत में बदला, वह काबिले तारीफ़ था. मुंबई इंडियंस ने जब रॉयल चैलेंजर बंगलुरु को 31 रनों से हराकर ट्रॉफ़ी अपने नाम की, तब जाकर यक़ीन आया कि वही असली विजेता है. वरना किसने सोचा था कि जिस खिलाड़ी को अभी–अभी टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, वह इस कदर जीत का जज़्बा दिखाते हुए चयनकर्ताओं को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर देगा. इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि जब यह लीग मुक़ाबला शुरू हुआ था, तब सभी ने मुंबई इंडियंस के प्रदर्शन को लेकर कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की थीं. सभी का यही कहना था कि टीम में न तो सचिन हैं और न रोहित शर्मा और मुनाफ़ पटेल.

कोई भी टीम अपने किसी एक खिलाड़ी के आउट ऑफ फॉर्म होने पर चिंता में पड़ जाती है. अगर तीन–तीन खिलाड़ी बाहर हों तो टीम के बाक़ी सदस्यों के मनोबल पर क्या फ़र्क़ पड़ता होगा, इसका सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसे वक़्त में जिस तरह टर्मिनेटर हरभजन की कप्तानी में युवा खिलाड़ियों ने फ़ाइनल तक का सफ़र तय किया, वह काफी कुछ सकारात्मक संदेश दे जाता है. साथ ही इस बात की भी तस्दीक करता है कि अगर टीम में जीत की भूख हो तो फिर किसी भी हाल में जीत आपके दामन में आकर ही रहेगी. मुंबई इंडियंस की जीत के बाद जब नीता अंबानी से बात की गई तो उनकी जीत की ख़ुशी में युवाओं के जोरदार प्रदर्शन का दम बोल रहा था. हालांकि वह इस बात से इंकार नहीं कर रही थीं कि सचिन की ग़ैर मौजूदगी से मनोबल में थोड़ी कमी आई थी. उन्होंने कहा कि सचिन भले ही मैदान में नहीं थे, पर उनकी मौजूदगी दुआ और टीम के खिलाड़ियों को सलाह के रूप में हर वक़्त हमारे साथ थी. वह इस जीत के लिए हरभजन की तारीफ़ करती हैं कि उन्होंने जिस तरह मुश्किल वक्त में अपनी नेतृत्व क्षमता का दम दिखाया, उसका कोई जवाब नहीं.

अगर मैच की बात करें तो कप्तान हरभजन सिंह और युजवेंद्र चहल की बेहतरीन गेंदबाज़ी के आगे बंगलुरु का कोई भी बल्लेबाज़ कहीं नहीं टिक सका. पहले बल्लेबाज़ी करते हुए मुंबई की टीम केवल 139 रनों का स्कोर ही खड़ा कर पाई थी. बंगलुरु की शुरुआत अच्छी नहीं रही. क्रिस गेल 5 रनों पर आउट हुए, जबकि तिलकरत्ने दिलशान ने 27 रन बनाए. गेल का विकेट कप्तान हरभजन सिंह ने लिया, वहीं दिलशान को मलिंगा ने आउट किया. हरभजन ने ही बंगलुरु के कप्तान डेनियल विटोरी को एक रन के निजी स्कोर पर 17वें ओवर में पवेलियन भेज दिया. विराट कोहली को भी 11 रनों के बाद खेलने का मौक़ा नहीं दिया. इसके तुरंत बाद किरोन पोलार्ड ने मोहम्मद कैफ को 3 रनों पर आउट किया. यहीं से मैच पूरी तरह मुंबई के पाले में आ चुका था.

बंगलुरु को सबसे बड़ा झटका तब लगा, जब तूफ़ानी बल्लेबाज़ क्रिस गेल हरभजन सिंह की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए. दिलशान और गेल के जाने से मुंबई इंडियंस के गेंदबाज़ों के हौसले काफ़ी बढ़ गए. मयंक अग्रवाल भी 14 रनों पर सस्ते में ही निपट गए. उस समय बंगलुरु का स्कोर था चार विकेट पर 73 रन. मुंबई को नियमित समय पर विकेट मिलते गए, जबकि बंगलुरु के लिए रन रेट बढ़ता गया. अरुण कार्तिक खाता भी नहीं खोल पाए तो कैफ़ ने मात्र तीन रन जोड़े. विटोरी को हरभजन ने एक रन पर आउट कर दिया. अंतिम ओवरों में रन रेट करीब 15 प्रति ओवर पहुंच गया था. 18वें ओवर में अबू अहमद की गेंद पर सौरभ तिवारी के आउट होने के बाद तो बंगलुरु की उम्मीदें ख़त्म हो गईं. बंगलुरु की पूरी टीम 19.2 ओवरों में 108 रन बनाकर आउट हो गई. हरभजन सिंह ने तीन विकेट लिए तो मलिंगा और अबू अहमद की झोली में दो विकेट गए. मुंबई इंडियंस के कप्तान हरभजन सिंह को मैन ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया और लसिथ मलिंगा को मैन ऑफ़ द सीरीज. सबसे ज़्यादा विकेट लेने का ख़िताब भी मलिंगा को ही दिया गया. खराब फॉर्म के कारण टीम इंडिया से बाहर चल रहे हरभजन सिंह ने चैंपियंस लीग टी–20 मैच में वह एक अहम विकेट लिया, जिसके बाद टीम की जीत लगभग तय हो गई.

क्रिकेट के जानकारों की मानें तो मुंबई इंडियंस ने चेन्नई में खेले गए दूसरे सेमी फाइनल में सोमरसेट को हराकर ट्वेंटी–20 चैंपियंस लीग के फाइनल में जगह बना ली और उसके बाद उसकी जीत के आसार बढ़ गए थे. वह मैच मुंबई इंडियंस ने 10 रनों से जीता था. कुल मिलाकर मुंबई इंडियंस की जीत काफी कुछ कह जाती है. यह उन टीमों के लिए एक सबक है, जो अपनी हार का ठीकरा खिलाड़ियों की कमी, उनकी चोटों और उनके फॉर्म में न होने पर फोड़ती हैं. इस जीत के साथ अगर किसी के हौसले सबसे ज़्यादा बुलंद हुए तो वह हैं हरभजन सिंह. अब वह टीम में वापसी के लिए एक बार फिर से फॉर्म में आ जाएंगे.

rajeshy@chauthiduniya.com

दाग़ नहीं मिट रहे

भारतीय एथलेटिक्स से डोपिंग का साया हटने का नाम नहीं ले रहा है. कोलकाता में पिछले महीने नेशनल ओपन चैंपियनशिप के दौरान कराए गए टेस्ट में तीन और एथलीट स्टेरॉयड के सेवन के दोषी पाए गए. नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने 10 से 13 सितंबर तक हुई चैंपियनशिप के दौरान 93 नमूनों की जांच की थी, जिनमें से तीन में स्टेरॉयड और मेथिलहेसनीमाइन पाया गया. नाडा के डायरेक्टर जनरल राहुल भटनागर ने कहा कि कोलकाता में 51वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान ट्रैक और फील्ड में 93 नमूने लिए गए थे, जिनमें से 91 के नतीजे मिल चुके हैं और तीन पॉजिटिव पाए गए. इन्हें पहले नोटिस भेजे जा चुके हैं. तीन महीने पहले ही आठ एथलीट डोपिंग के दोषी पाए गए थे, जिनमें एशियन गेम्स की डबल गोल्ड मेडलिस्ट अश्विनी अकुंजी शामिल हैं. इसके अलावा एशियन गेम्स की चार गुणा 400 मीटर रिले दौड़ की गोल्ड मेडलिस्ट टीम की सदस्य मनदीप कौर, सिनि जोस के साथ धाविका जौना मुर्मू, प्रियंका पंवार, टियाना मेरी थामस, शॉटपुट खिलाड़ी सोनिया और लंबी कूद के खिलाड़ी हरिकृष्ण मुरलीधरन भी दोषी पाए गए थे.

गर्दिश में सितारे

भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ताजा डब्ल्यूटीए रैंकिंग में सात पायदान लुढ़क कर 88वें स्थान पर आ गई हैं, जबकि सोमदेव देववर्मन को चार पायदान का नुक़सान हुआ है. सानिया पिछली रैंकिंग में 81वें स्थान पर थीं. डबल्स रैंकिंग में वह अभी भी 10वें स्थान पर बनी हुई हैं. भारत के नंबर वन सिंगल्स खिलाड़ी सोमदेव देववर्मन एटीपी रैंकिंग में चार पायदान खिसक कर 69वें स्थान पर आ गए. डबल्स रैंकिंग में महेश भूपति छठे, लिएंडर पेस आठवें और रोहन बोपन्ना 14वें स्थान पर बने हुए हैं. सिंगल्स रैंकिंग में प्रथम तीन स्थानों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. महिला श्रेणी में डेनमार्क की कैरोलीन वोज्नियाकी, रूस की मारिया शारापोवा और बेलारूस की विक्टोरिया पहले तीन स्थानों पर हैं. पुरुष श्रेणी में अमेरिकी ओपन विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच, उपविजेता रफेल नडाल और स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर पहले तीन स्थानों पर हैं.

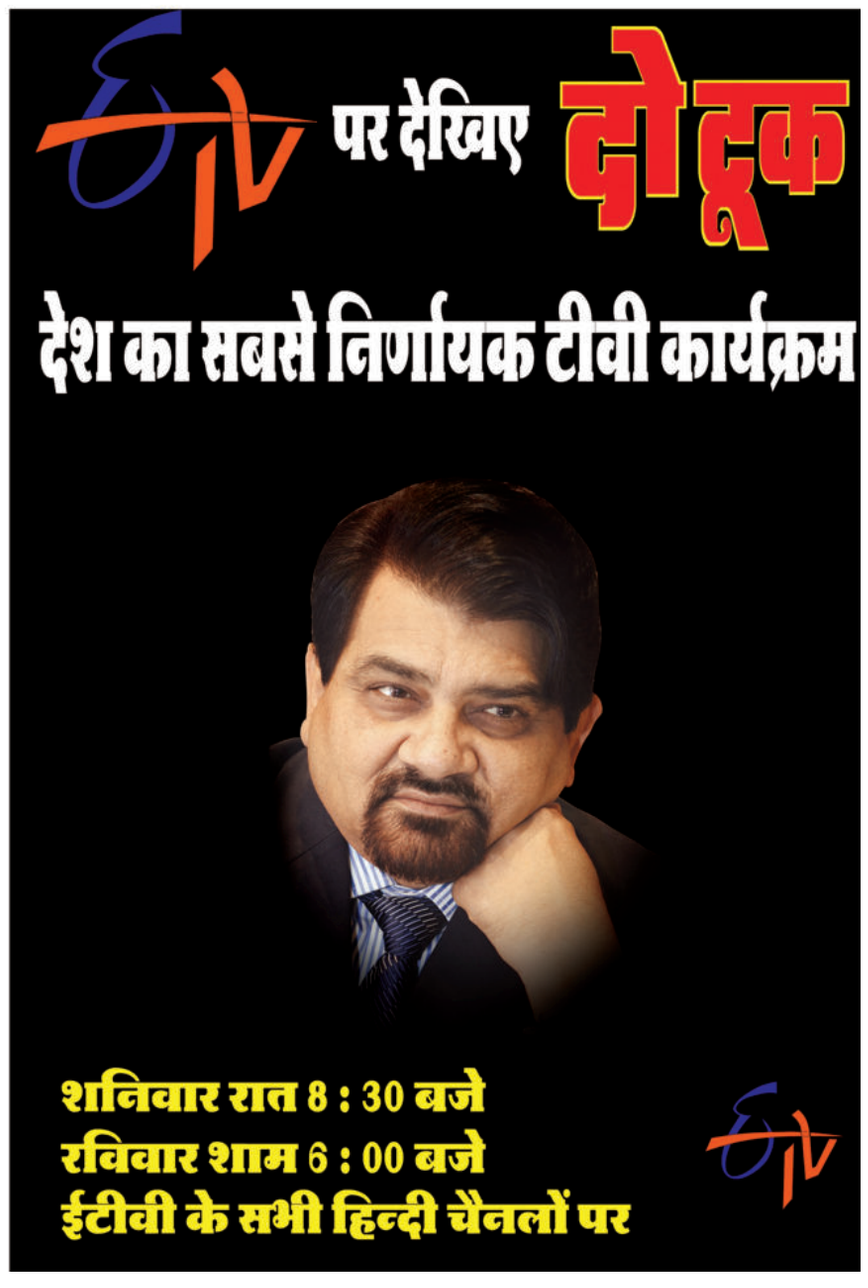

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

असिन ने अपनी फिल्म अम्मा नन्ना ओ तमिल अम्मई का चरित्र इस रीमेक फिल्म में भी निभाया, लेकिन यहां उन्हें तमिल लड़की की जगह मलयाली लड़की के रूप में चित्रित किया गया.

हॉलीवुड से...

ज़िद पर अड़ी हैं निकोल

एक ट्रांसजेंडर पेंटर पर आधारित निकोल किडमेन की फिल्म के निर्माण में आने वाली मुश्किलें बढ़ गई हैं. द डैनिश गर्ल नामक इस फिल्म में वह खुद आर्टिस्ट लिली एल्बे के ट्रांसजिशन के पहले और बाद के व्यक्तित्व का किरदार निभाने वाली हैं. यह फिल्म निकोल की प्रोडक्शन कंपनी द ब्लोसम फिल्म्स का एक महत्वाकांक्षी प्रोजक्ट है. यह फिल्म निर्माण से पहले ही विवादों में है और अब तक तीन बड़ी अभिनेत्रियों को एल्बे की पत्नी के रोल से हटाया जा चुका है. गायनथ पेल्ट्रा और चार्लीज थेरॉन का नाम भी सामने आया, लेकिन उनके पास समय की कमी के चलते बात नहीं बन सकी. रैशल वाइज को पिछले साल साइन किया गया था, लेकिन वह भी पीछे हट गईं. निकोल आज भी फिल्म बनाने के मूड में हैं. एल्बे वह पहली हस्ती हैं, जिन्होंने इस साल सर्जरी के जरिए लिंग परिवर्तन कराया था. एल्बे लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम से ग्रसित थीं. निर्देशन की कमान टॉमस एजफ्रेडसन को सौंपी गई है.

अभिनय का अर्जुन

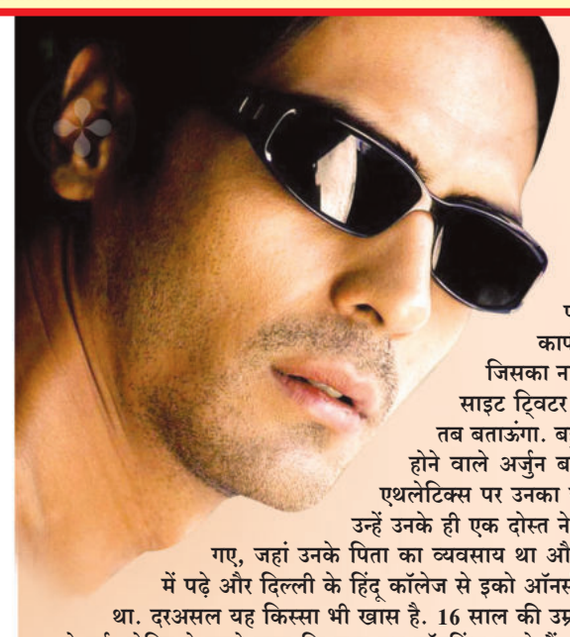

फैशन मॉडल से अभिनय की तरफ रुख करने वाले अर्जुन रामपाल काफी खुश हैं. इस खुशी का कारण उनकी नई फिल्म है, जिसमें वह एक नए लुक में नज़र आएंगे. यह दीपावली उनके लिए दो मायनों में खास है, पहला तो यह कि दीपावली उनका पसंदीदा पर्व है और दूसरा यह कि मोस्ट अवेटेड फिल्म रा-वन इसी दिन रिलीज होगी. पिछले काफी समय से अर्जुन इस फिल्म के प्रोमोशन में लगे हैं. इसमें उन्होंने विलेन की भूमिका निभाई है जिसका नाम रावण है. इसके अलावा और भी कारण हैं अर्जुन के खुश होने के. अर्जुन ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर लिखा है कि मैं स्टार वर्ल्ड पर एक शो करने जा रहा हूं. शो का नाम जब तय हो जाएगा, तब बताऊंगा. बहुत जल्द इसका प्रोमो लिंक भेजने वाला हूं. बच्चों की फिल्म में नजर आनेवाले बच्चों से उत्साहित होने वाले अर्जुन बचपन में काफी शरारती थे. दसवीं तक उनका ध्यान पढ़ाई पर नहीं था. उस वक़्त टेनिस एवं एथलेटिक्स पर उनका ज़्यादा ध्यान था. पढ़ाई से बचने के लिए खेल एक बहाना बन गया था. इस बात का एहसास उन्हें उनके ही एक दोस्त ने दिलाया. जबलपुर में उनके जन्म के बाद उनके माता-पिता नासिक के पास देवलाली में बस गए, जहां उनके पिता का व्यवसाय था और मां टीचर थीं. यहीं पर उनका बचपन बीता. उसके बाद वह कोडाईकनाल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े और दिल्ली के हिंदू कॉलेज से इको ऑनर्स किया. मॉडलिंग की शुरुआत में रोहित बल जैसे डिजायनर से टकराना एक खूबसूरत इत्तेफाक था. दरअसल यह किस्सा भी खास है. 16 साल की उम्र में जब वह मुंबई आए तो पहली बार एक डिस्कोथेक में गए, जहां उनकी मुलाकात रोहित बल से हुई. रोहित ने उनसे पूछा कि क्या वह मॉडलिंग करते हैं, लेकिन दिलचस्पी न होने की वजह से उन्होंने मना कर दिया. उनका मानना था कि मॉडलिंग लड़कियों के लिए ही ठीक है. उसके बाद जब वह हिंदू कॉलेज में मॉडलिंग करने लगे तब एक बार फिर डिस्कोथेक में उनकी मुलाक़ात रोहित बल से हुई, लेकिन मॉडलिंग में उनकी दिलचस्पी न होने की वजह से वह उब गए थे, पर रोहित ने अर्जुन को उनके नाम से पहचानते हुए अगले दिन शूटिंग पर आने का न्योता दे दिया. दरअसल वह कैमरे के पीछे रहना चाहते थे और फिल्म मेकिंग जैसी चीजों पर ध्यान देना चाहते थे. इसके लिए वह न्यूयॉर्क फ़िल्म स्कूल में भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन मॉडलिंग का सीधा रास्ता उन्हें बॉलीवुड की तरफ ले गया, जहां उन्होंने कई हिट और कई फ्लॉप जैसे उतार-चढ़ाव देखे. 2001 में फ़िल्म मोक्ष प्रदर्शित हुई, जिसे अशोक मेहता ने निर्देशित किया था. यह उनकी दूसरी फ़िल्म प्यार, इश्क़ और मोहब्बत के बाद रिलीज हुई. इसमें उन्होंने सुनील शेट्टी और आफ़ताब शिवदासानी के साथ काम किया था. हालांकि दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, पर आलोचकों ने दोनों ही फ़िल्मों में उनके अभिनय की सराहना की. 2002 में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय भारतीय फ़िल्म अकादमी से फ़ेस ऑफ़ द इयर पुरस्कार जीता. उन्होंने आंखें (2002), दिल है तुम्हारा (2002), और एक अजनबी (2005) जैसी फ़िल्मों में काम किया. अधिकांश फ़िल्मों में वह सहायक भूमिकाओं में नज़र आए. उन्होंने शाहरुख़ ख़ान, रानी मुखर्जी, सैफ़ अली ख़ान, प्रीति ज़िंटा और प्रियंका चोपड़ा जैसे सितारों के साथ मिलकर टेंपटेशन 2004 में भाग लिया. 2006 में उन्होंने मल्टी स्टारर फ़िल्म कभी अलविदा ना कहना में अतिथि भूमिका और 1978 में अमिताभ बच्चन अभिनीत फ़िल्म डॉन के रीमेक डॉन-द चेस बिगिन्स अगेन में एक सहायक की भूमिका निभाई. अर्जुन ने स्वयं के प्रोडक्शन हाउस चेसिंग गणेशा फ़िल्म्स के ज़रिए इसका निर्माण किया. उनकी पत्नी मेहर जेसिया सहनिर्माता थीं. इसके बाद फ़राह ख़ान की फिल्म ओम शांति ओम (2007) में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए उन्हें समीक्षकों ने काफी सराहा. यह बॉलीवुड के इतिहास में सबसे बड़ी हिट फ़िल्मों में से एक थी. 2007 में अर्जुन ने ऋतुपर्णो घोष कृत कलात्मक फ़िल्म द लास्ट लियर में अमिताभ बच्चन एवं प्रीति ज़िंटा के साथ अभिनय किया. 2008 में रामपाल ने रॉक ऑन में अभिनय किया. अर्जुन ने पूर्व मिस इंडिया मेहर जेसिया से शादी की. उनकी दो बेटियां हैं, माहिका और माइरा.

शीला की कहानी

राखी को रीयल किस देकर चर्चा में छाने वाले मीका अपनी आने वाली फिल्म में शीला की ड्रेस पहने एक लड़की को किस करते नज़र आएंगे. मीका ने बिना हिचक स्वीकार भी कर लिया कि वह शीला के नाम को भुनाना चाहते हैं. अब शीला यानी कैटरीना कैफ इस बात का क्या मतलब निकालती हैं, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल उनके पास इन सब बातों के समय नहीं है. यशराज फिल्म्स की इस फिल्म का नाम है एक था टाइगर, जो अगले साल एक जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब 2012 में ही ईद के दिन रिलीज होगी. चूंकि आमिर खान अगले साल एक जून को अपनी फिल्म, जो रीमा कागती द्वारा निर्देशित है, को रिलीज करना चाहते हैं. इसलिए उन्होंने सलमान खान और आदित्य चोपड़ा से अनुरोध किया कि वे एक था टाइगर की रिलीज डेट बदल दें. करीबी रिश्ते और आपसी सम्मान के चलते बात बन गई. कबीर खान द्वारा निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा प्रोड्यूस इस फिल्म में कैटरीना कैफ और सलमान खान लीड रोल में हैं. फिल्म आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखी कहानी पर आधारित है, पटकथा- संवाद लेखन कबीर खान एवं नीलेश मिश्रा का और संगीत दिया है सोहेल सेन ने.

भाग्यशाली अजय

अजय देवगन की गिनती बॉलीवुड के उन सितारों में होती है जो कम पैसा लेते हैं और सुपरहिट फिल्म देते हैं. अजय ने पिछले कुछ वर्षों में कई हिट फिल्में दी हैं. हाल में आईं उनकी फिल्म गोलमाल-3 और सिंघम ने 100 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का व्यवसाय किया, लेकिन अजय ने अपनी कीमत नहीं बढ़ाई, लेकिन इसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब समय आ गया है प्राइस बढ़ाने का. जब कम हिट फिल्म देने वाले हीरो दोगुनी कीमत वसूल रहे हैं तो अजय भला क्यों पीछे रहें. ख़बर है कि अजय ने वासु भगनानी की अगली फिल्म करने के बदले में 18 करोड़ रुपये वसूले हैं. यह फिल्म सुपरहिट फिल्म हिम्मतवाला (1983) का रीमेक है. हिम्मतवाला ने श्रीदेवी को स्टार बना दिया था और जितेंद्र के करियर को मजबूती दी थी. वासु को लगता है कि आज के दौर में हिम्मतवाला का रीमेक काम कर सकता है. जितेंद्र का रोल निभाने के लिए उन्होंने अजय को चुना. अजय ने बढ़ी हुई प्राइस बताई, वासु तुरंत तैयार हो गए. अजय के पास कई टीवी शो के भी ऑफर आ रहे हैं. अजय का मानना है कि कठिन परिश्रम के साथ-साथ आपकी तकदीर भी आपके साथ होनी चाहिए. मुझे तकदीर ने बहुत साथ दिया, बॉलीवुड में काम करने का ऑफर मिला. बीस वर्ष हो गए, लेकिन प्रशंसक मुझसे कभी निराश नहीं हुए.

तुम जियो हजारों साल

असिन

अभिनेत्री असिन को कौन नहीं जानता. आमिर खान के साथ फिल्म गजनी करने के बाद वह पूरे देश में प्रसिद्ध हो गईं. इससे पहले वह दक्षिण फिल्मों की अभिनेत्री थीं. असिन थोट्टूमकल का जन्म केरल के कोची में 26 अक्टूबर, 1985 को हुआ था, संयोगवश इस साल इसी दिन दीवाली है. उनके जन्मदिन पर आपको बताते हैं कि वह बॉलीवुड से पहले क्या कर रही थीं. असिन थोट्टूमकल ने 2001 में सथ्यन अंथिक्कड़ी की मलयालम फिल्म नरेंद्र मकान जयकंथान वाका में सहायक अभिनेत्री की भूमिका करके अभिनय के क्षेत्र में प्रवेश किया, तब उनकी उम्र 15 साल की थी. एक साल तक फिल्म जगत से बाहर रहने केबाद असिन एक अभिनेत्री के रूप में फिल्म अम्मा नन्ना ओ तमिल अम्मई में रवि तेजा के साथ वापस आईं. तेलुगु भाषा में यह उनकी पहली फिल्म थी, जिसमें उन्होंने एक तमिल लड़की का चरित्र निभाया, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का तेलुगु फ़िल्म फेयर अवॉर्ड दिलाया. उसी साल उन्होंने अपनी दूसरी तेलुगु फिल्म शिवमणि में नागार्जुन के साथ अच्छे प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का संतोषम पुरस्कार जीता. इसके बाद आईं दो तेलुगु फिल्में, लक्ष्मी नरसिम्हा और घर्षण. दोनों में उन्होंने पुलिस अधिकारी की प्रेमिका की भूमिका निभाई और तेलुगु फिल्म उद्योग में एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में उनका स्थान मजबूत होता चला गया

असिन को पहली व्यवसायिक सफलता 2003 में अम्मा नन्ना ओ तमिल अम्मई नामक फिल्म से मिली. कई फ़िल्में प्रदर्शित होने के बाद तमिल फिल्म गजनी (2005) में अपने प्रदर्शन केलिए उन्हें दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दक्षिण फ़िल्म फयर पुरस्कार मिला. उन्होंने कई सफल फिल्में कीं. रोमांचक फिल्म गजनी (2005) और एक्शन कॉमेडी फिल्म वारालारू (2006) में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई. हाल में असिन ने फिल्म गजनी से बॉलीवुड में प्रवेश किया, जो उनकी इसी नाम की तमिल फिल्म की रीमेक है और इसके लिए उन्होंने प्रथम फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनय का फ़िल्म फेयर पुरस्कार भी जीता.

असिन की पहली तमिल फिल्म एम कुमारन सन ऑफ महालक्ष्मी थी, जिसमें उन्होंने जयम रवि के साथ अभिनय किया. असिन ने अपनी फिल्म अम्मा नन्ना ओ तमिल अम्मई का चरित्र इस रीमेक फिल्म में भी निभाया, लेकिन यहां उन्हें तमिल लड़की की जगह मलयाली लड़की के रूप में चित्रित किया गया. यह फिल्म 2004 के दौरान तमिल सिनेमा की सबसे सफल फ़िल्मों में से एक बन गई. एक संक्षिप्त अंतराल में तेलुगु फिल्म चक्रम करने के लिए लौटने के बाद वह उल्लम केटुकुमाए में भी दिखाई दीं. यह फिल्म 2002 में असिन को एक अभिनेत्री के रूप में स्थापित करने के लिए शुरू की गई थी, जिसमें उनके साथ नए कलाकार आर्य और पूजा उमा शंकर भी थे. जीवा द्वारा निर्देशित यह फिल्म प्रेम कहानी पर आधारित थी और काफी समय बाद पूरी हो पाई, लेकिन अंत में बॉक्स ऑफिस पर सफल उपक्रम बन गई.

बहन भरोसे शमिता

शिल्पा ने बॉलीवुड में जो मुकाम हासिल किया है, वहां तक पहुंचना शमिता के लिए लगभग नामुमकिन है. यशराज कृत मोहब्बतें जैसी फिल्म मिलने के बावजूद शमिता कोई कमाल नहीं दिखा पाईं. अनुभव सिन्हा की फिल्म दस में शमिता को रोल मिल पाया तो केवल शिल्पा शेट्टी की वजह से. जब शिल्पा शेट्टी यूके के रियलिटी शो बिग बॉस से लौटीं तो यहां के शो बिग बॉस में शमिता शेट्टी को भी एंट्री मिल गई. जब-जब शिल्पा शेट्टी हाईलाइट हुईं, तब-तब शमिता शेट्टी भी फ्रेम में नज़र आईं. चाहे वह आईपीएल मैच हो या शिल्पा की शादी. लगता है, बहन को कामयाब बनाने के लिए शिल्पा को फिल्म भी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी.

प्रतिभा के बूते सफलता संभव

फिल्म ख्वाजा मेरे ख्वाजा से एंट्री कर रही वसुंधरा को पूरा भरोसा है कि सिर्फ अपनी प्रतिभा के बूते वो बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाने में कामयाब हैं. हलांकि मायानगरी में ये आसान नहीं वह भी तब जब वह फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कलाकारों के परिवारों के से नहीं आती बल्कि उत्तर प्रदेश से हैं. वसुंधरा आगरा में फिल्म ख्वाजा मेरे ख्वाजा की शूटिंग में व्यस्त हैं. मासूमियत और सौम्यता वसुंधरा विरासत में मिली है. हालांकि फिल्म ख्वाजा मेरे ख्वाजा उनकी पहली हिंदी फिल्म है. इससे पहले वह हॉलीवुड फिल्म नेवर से कांट टेल में काम कर चुकी है. अभिनय और गायन से उनका पुराना नाता है. बचपन से उन्हें गाने का शौक था. कई नाटकों में प्ले किया. वह मुंबई में सिर्फ़ अपनी प्रतिभा और लगन के बल पर टिकी हुई हैं. वसुंधरा उत्साह से लबरेज हैं और मानती हैं कि यदि आपमें प्रतिभा हो आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है.

फिल्म प्रीव्यू

रा-वन

फिल्म की कहानी शेखर सुबह्मण्यम (शाहरुख खान) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक गेम डिजाइनर है, लेकिन अभी तक वह एक भी सफल वीडियो गेम नहीं बना पाया है. शेखर एक मस्तमौला आदमी है, लेकिन इसके बावजूद वह अपना ज़्यादातर समय गेम डिजाइन लैब में बिताता है, ताकि वह एक सफल वीडियो गेम बना सके. हां, उसकी एक आदत है खाना. वह खाने का बहुत शौकीन है जिससे सभी परेशान हैं. शेखर की बीवी का नाम है सोनिया (करीना कपूर), जो पंजाबी है. पंजाबी महिलाओं की तरह वह जिंदगी को भरपूर तरीके से जीने में विश्वास करती है. शेखर जो खुद दक्षिण भारतीय है, उसके साथ पंजाबी कुड़ी की जोड़ी बहुत दिलचस्प लगती है, लेकिन सोनिया का व्यवहार और आदतें शेखर से बिल्कुल उलट हैं. सोनिया किसी भी तरह की समस्या से निपट सकती है, सिवाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी के. इसके साथ ही सोनिया एक ऐसी किताब भी लिखना चाहती है जिसमें गालियां पुरुषों के ऊपर बनी हों. शेखर और सोनिया का एक बेटा है प्रतीक सुबह्मण्यम (मास्टर अमन वर्मा). प्रतीक को वीडियो गेम का बहुत शौक है. वह पूरे दिन वीडियो गेम ही खेलना पसंद करता है, लेकिन इसके साथ वह अन्य खेलों में भी रुचि रखता है, पर उसका पहला प्यार तो वीडियो गेम ही रहते हैं. प्रतीक की अपने मम्मी-पापा से नहीं पटती है. वह चाहता है कि उसके मां-बाप भी उसकी तरह रहें और जिएं. उसे अपनी लाउड पंजाबी मां पर शर्म आती है, जबकि पिता को वह बिल्कुल पसंद नहीं करता. वह चाहता है कि उसके पिता कूल दिखें, लेकिन उसके पिता शेखर (शाहरुख खान) अपने बेटे को खुश करने की सारी कोशिशें करते हैं. इसी बीच शेखर का डिजाइन किया एक गेम सफल हो जाता है. पूरा परिवार इस गेम को देखने के लिए इकट्ठा है. बीच गेम में हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाती है और तूफान आता है सुब्रह्मण्यम परिवार पर. गेम में जो भी कुछ होता है, वह इस परिवार के साथ असल में होने लगता है. यहां फिल्म कुछ-कुछ अजय देवगन की टूनपुर का सुपर हीरो की तरह लगती है. फिल्म में जी. वन (द गुड वन) नामक सुपर हीरो भी है. जी. वन बिजली से बना हुआ है और उसके अंदर रक्षा करने का प्रोग्राम फीड है. वह उड़ सकता है, कई भाषाएं बोल सकता है और कई चीजों को एक साथ नियंत्रित कर सकता है. सुब्रह्मण्यम फैमिली और जी. वन में क्या संबंध है, यह जी. वन कौन है? इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए आपको शाहरुख खान की यह बेमिसाल फिल्म देखनी होगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

महाराष्ट्र

दिल्ली, 24 अक्टूबर-30 अक्टूबर 2011 | www.chauthiduniya.com | दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

कुपोषण का दुष्चक्र

योजनाओं में लूट मची

प्रवीण महाजन

महाराष्ट्र में कुपोषण के ख़ात्मे के लिए हर साल राज्य सरकार भारी-भरकम बजट का आवंटन करती है. एक तरफ विविध योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपये कुपोषण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में खर्च किए जाने का दावा किया जाता है. वहीं दूसरी तरफ कुपोषित बच्चों को पौष्टिक आहार देने, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की बात हमेशा कही जाती है, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया जाता. नतीजतन हालात दिन-ब-दिन और खराब हो रहे हैं. राज्य में कुपोषण की वजह से शिशुओं के मरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है. प्रदेश के मेलघाट और गढ़चिरोली जैसे इलाकों में कुपोषण की वजह से बालमृत्यु की दर में कोई कमी नहीं आई है. पिछले दिनों इसका खुलासा विदर्भ वैधानिक विकास बोर्ड द्वारा राज्यपाल के. शंकर नारायणन को सौंपी गई रिपार्ट में किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में कुपोषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है. हालांकि इस रिपोर्ट को राज्यपाल ने इसकी अहमियत समझते हुए इसकी चर्चा राज्य सरकार से करने का आश्वासन बोर्ड के सदस्यों को दिया है. इस समस्या से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र अमरावती ज़िले के आदिवासी बहुल मेलघाट में लाख रुपये वेतन देने पर भी कोई चिकित्सक वहां जाने को तैयार नहीं है. ग़ौरतलब है कि इस तथ्य का खुलासा मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष किया गया है. सबसे अहम बात यह है कि सरकार इस समस्या के प्रति कितनी गंभीर है उसकी गंभीरता उसी से दिखती है कि कुपोषण के नाम पर होने वाले करोड़ों रुपये से बच्चों का भला तो नहीं हो रहा, लेकिन इससे जुड़े अधिकारी और कर्मचारी अपनी सेहत ज़रूर सुधार रहे हैं.

महाराष्ट्र में कुपोषण का दुष्चक्र जारी है. दरअसल यह राज्य सरकार और प्रशासन की घोर लापरवाही का नतीजा है. कुपोषण के सबसे अधिक शिकार आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे हो रहे हैं.जहां शिक्षा का अभाव, जागरूकता का अभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, रोजगार का अभाव जैसी समस्याएं बरकरार हैं. बावजूद इसके शासन-प्रशासन इन समस्याओं के प्रति उदासीन है. प्रदेश में तमाम योजनाएं कागजों पर ही लागू की जाती हैं. लिहाजा समस्याएं जस का तस मौजूद रहती हैं. एक ओर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण दावा करते हैं कि राज्य में कुपोषण 27 फीसदी कम हुआ है. हालांकि उनकी यह दलील उन ग़लत दस्तावेज़ों के आधार पर है, जो भ्रष्ट अधिकारियों ने अपनी खाल बचाने के लिए तैयार किया है. दूसरी ओर सरकार द्वारा गठित विदर्भ वैधानिक विकास महामंडल की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के दावे की पोल खोलने के लिए काफी है.महामंडल की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में हर वर्ष 22 हज़ार से अधिक आदिवासी बच्चे कुपोषण व मौसमी बीमारियों की वजह से मरते हैं. इसके अलावा तक़रीबन 11 लाख बच्चों में से 20 प्रतिशत कुपोषण से पीड़ित हैं. ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री के दावे पर कौन यकीन करेगा. इस समस्या से निपटने का जो तरीका शासन-प्रशासन द्वारा अपनाया जाता है वह पूरी तरह नाकाफ़ी साबित हो रहा है. एक आंकड़े के मुताबिक़ राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्र मेलघाट में 14,500 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं. यह आंकड़ा सरकार ने ही मुंबई उच्च न्यायालय के सामने रखी है. न्यायालय को सरकार ने बताया है कि वह इस समस्या से निपटने के लिए गंभीर कदम उठा रही है. इसका मतलब यह हुआ कि पिछले दस-पंद्रह वर्षों में सरकार ने जो योजनाएं लागू की हैं वह पूरी तरह फ्लॉप साबित हो रहा है. सरकार से यह पूछा जाना बेहद ज़रूरी है कि मेलघाट में कुपोषण के नाम पर किए गए करोड़ों रुपये कहां गए. यदि राज्य सरकार अपनी योजनाओं की विफलताओं की समीक्षा करे तो उसमें अरबों रुपये का घोटाला सामने आएगा, लेकिन क्या सरकार ऐसा करेगी यह बड़ा सवाल है. राज्यपाल के. शंकर नारायणन को विदर्भ वैधानिक विकास महामंडल द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे प्रदेश में आदिवासियों की कुल आबादी 84 लाख 86 हज़ार 156 है. उल्लेखनीय है कि लगभग 32 फ़ीसदी आदिवासी विदर्भ में निवास करते हैं. लगभग दो लाख 25 हज़ार आदिवासी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं. आदिवासी इलाकों के करीब 50 फ़ीसदी लोग 16 से 60 साल आयु वर्ग के हैं जिनमें से 50 प्रतिशत लोग कुपोषण के शिकार हैं. इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले महान ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. आशीष सातव का कहना है कि राज्य के सभी आदिवासी इलाक़ों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की सबसे अधिक गरज है, क्योंकि वर्तमान में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वे निम्न स्तर की हैं. ख़ास बात यह है कि आदिवासियों के जीवनस्तर को सुधारने के सरकारी दावों के विपरीत इस रिपोर्ट में 75 प्रतिशत आदिवासियों को ग़रीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते बताया गया है, लेकिन दूसरी ओर सरकार ज़मीनी हक़ीक़त पर सरकारी दस्तावेज़ों में दर्ज़ आंकड़ों का हवाला देकर पर्दा डालने की कोशिश करती है. वह उन दस्तावेज़ों में दर्ज़ आंकड़ों की वास्तविकता कभी जांचने या परीक्षण कराने का प्रयास नहीं करती है. इसलिए कागज़ी आंकड़ों के आधार पर सरकार कुपोषण के कम होने की घोषणा कर हक़ीक़त से मुंह चुराती दिखती है, जबकि सच्चाई यह है कि यहां कुपोषण काफी तेज़ी से फैल रहा है. विदर्भ के गोंदिया ज़िले में पिछले छह माह के दौरान 125 बालकों की मौत कुपोषण की वजह से हुई है. इसके अलावा क़रीब 500 नवजात शिशु भी असमय मौत के शिकार हो गए. मेलघाट में भी पिछले चार माह में क़रीबन 120 बच्चों की मौत कुपोषण से हुई है. उसी तरह नासिक ज़िले में पिछले चार माह में 619 बच्चों को कुपोषण ने निगल लिया. ये तमाम आंकड़े सरकारी हैं, जो मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के इस दावों को ग़लत साबित करने के लिए काफी हैं. ग़ौरतलब है कि आदिवासी इलाकों में कार्यरत स्वास्थ्य अधिकारी इन आंकड़ों में कमी दर्ज़ कर इस समस्या पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं. सरकार ने कुपोषण पर अंकुश लगाने के लिए माता-बाल स्वास्थ्य व पोषण मिशन के तहत कई योजनाएं चला रही हैं, लेकिन उसका कोई असर कहीं दिखाई नहीं देता. वहीं 15 ज़िलों में चलाई जा रही नव संजीवन योजना भी पूरी तरह विफल साबित हुई हैं. नव संजीवन योजना के तहत विदर्भ के अमरावती, यवतमाल, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चरोली और वाशिम ज़िलों को शामिल किया गया है, लेकिन इन ज़िलों में कुपोषण से होने वाली मौत का सिलसिला जारी है. सरकार की मानें तो बारिश के मौसम से पूर्व ही उसने प्रदेश भर में मातृत्व अनुदान योजना , मानसेवी डॉक्टर योजना और दाई योजना लागू करने पर विचार किया गया था, लेकिन व्यवस्थागत कमियों के कारण ये सभी योजनाएं लागू नहीं हो सकीं. ख़ास बात यह है कि कुपोषित बच्चों के सर्वेक्षण पश्चात उन्हें पोषण आहार आपूर्ति करने साथ ही गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण जैसी योजनाएं भी हवा-हवाई साबित हुई हैं. इस पूरे मामले में सरकारी तंत्र अंधेरे में हाथ-पांव मारता दिखाई देता है. लापरवाही का आलम यह है कि नव संजीवन योजना को लागू करने वाले स्वास्थ्य विभाग में तक़रीबन आठ सौ कर्मचारियों के पद खाली हैं. इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों में कोई डॉक्टर अपनी सेवाएं देने को तैयार नहीं हैं. अब तक सरकार इन क्षेत्रों में पूर्णकालिक बालरोग विशेषज्ञ, पोषण आहार विशेषज्ञ की नियुक्ति करने में भी नाकाम रही है. हालत यह है कि यहां कार्यरत मोबाइल स्वास्थ्य पथकों के पास वाहन तो है, लेकिन उसे चलाने के लिए डीजल नहीं है. वहीं पोषाहार आपूर्ति करने वाली पूरी व्यवस्था भी यहां अधर में लटकी हुई है. ऐसे में यह सवाल लाज़िमी है कि इन हालात में कुपोषण की समस्या से कैसे निजात मिलेगी.

मौजूदा समय में हालत यह है कि कुषोणग्रस्त आदिवासी क्षेत्रों में कोई अधिकारी वहां जाकर काम करने को तैयार नहीं है. इसकी एक बानगी मेलघाट में देखने को मिली. दरअसल सरकार ने मेलघाट में आदिवासी प्रकल्प अधिकारी पद सृजित करने का फैसला वर्ष 1993 में लिया था. शुरुआत के चार वर्षों को छोड़कर यह पद अतिरिक्त प्रभार के रूप में अन्य अधिकारियों के पास ही रहा है. कई वर्षों के बाद पिछले 1 सितंबर को आईएएस अधिकारी प्रशांत नारनवरे की नियुक्ति मेलघाट आदिवासी प्रकल्प अधिकारी के रूप में की गई, लेकिन दूसरे ही दिन उन्होंने अपना तबादला कहीं और करा लिया. इससे साफ है कि राज्य सरकार और उनके प्रशासनिक अधिकारी कुपोषण की समस्या के प्रति कितने गंभीर हैं.

आदिवासी इलाके में डॉक्टर जाने को तैयार नहीं

कुपोषणग्रस्त मेलघाट में डॉक्टर 1 लाख रुपये के वेतन पर भी जाने को तैयार नहीं हैं. इस तथ्य का खुलासा किया है नोडल अधिकारी प्रदीप.पी. ने. मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर मेलघाट आदिवासी विभाग के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी ने 15 सितंबर को इस तथ्य का खुलासा मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह और न्यायाधीश रोशन दलवी की खंडपीठ के समक्ष किया. उन्होंने न्यायालय में बताया कि मेलघाट में काम करने वाले डॉक्टरों को सरकार एक लाख रुपये वेतन देने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन वहां कोई भी डॉक्टर जाने को तैयार नहीं है. याचिकाकर्ता पूर्णिमा उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा था कि मेलघाट में कुपोषण एक बड़ी समस्या है और वहां के लोगों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है. इस मामले में उन्होंने न्यायालय से उचित कार्रवाई करने की मांग की थी.

feedback@chauthiduniya.com

मेडिकल कॉलेजों को आदिवासी इलाकों से जोड़ें

विदर्भ वैधानिक विकास महामंडल ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को सुझाव दिया है कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों को आदिवासी इलाकों में स्थित अस्पतालों से जोड़ा जाए. इससे आदिवासी क्षेत्र के अस्पतालों में डाक्टरों की कमी होने की समस्या से निपटा जा सकता है. मिसाल के रूप में सेवाग्राम (वर्धा) का उदाहरण दिया गया है. सेवाग्राम के महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को कर्मग्राम के आदिवासी अस्पताल से जोड़ा गया है, जिसके काफी अच्छे नतीजे सामने आए हैं. इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों को आदिवासी इलाकों के अस्पताल से जोड़े जाने से विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को भी दूर किया जा सकेगा.

मिजोरम से सबक सीखें

वैधानिक विकास महामंडल की रिपोर्ट में महाराष्ट्र सरकार को यह भी सुझाव दिया गया है कि वह कुपोषण से निपटने के मामले में मिजोरम जैसे छोटे से राज्य से सबक ले सकती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र जैसा प्रगतिशील राज्य अपने जीडीपी का 0.5 प्रतिशत जनता के स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है. वहीं देश का छोटा सा राज्य मिजोरम महाराष्ट्र की अपेक्षा 12 गुना अधिक अपने राज्य की जनता के स्वास्थ्य पर खर्च करता है. इसलिए महाराष्ट्र सरकार को मिजोरम से सबक लेते हुए अपने जीडीपी का 10 प्रतिशत राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने पर खर्च करना चाहिए. ताकि राज्य में तेजी से पैर पसार रही कुपोषण की समस्या पर रोक लगाई जा सके.

ये क्या हो रहा है...

सियासत के हथकंडे

महाराष्ट्र की राजनीति के अपने अज़ब-गज़ब तरीके हैं. राज्य के राजनीतिक दल कब कहां सवार हो जाएं इसकी भविष्यवाणी करना काफी कठिन है. यही वजह है कि प्रदेश के सियासी दल नित्य नए गुल खिलाते रहते हैं. सयाने यूनियन लीडर शरद राव को सूझा कि क्यों न कुछ नया किया जाए. लिहाज़ा वे ऑटो रिक्शा चालकों को सरकारी कर्मचारी का दर्ज़ा देने की वकालत करने लगे. हालांकि, उनका यह ख्याल महाराष्ट्र के अन्य नेताओं को हज़म नहीं हो रहा है. यही वजह है कि शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना(मनसे) ने उनके खिलाफ़ मोर्चा खोल दिया है. हद तो तब हो गई जब शिवसेना और मनसे के नेताओं ने खुले तौर पर मुंबई के ऑटो चालकों को सबक सिखाने का ऐलान कर दिया. उनके तेवर से ऐसा लग रहा था कि मानों समूचे मुंबई में उनकी समानांतर सरकार चल रही हो. मनसे कार्यकर्ताओं ने मुंबई के कुछ इलाकों में ऑटो रिक्शा चालकों के साथ मारपीट की और कुछ सवारियों के साथ बदतमीजी भी. हद तब हो गई जब इस मारपीट की घटना की जिम्मेदारी लेने के लिए शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में होड़ शुरू हो गई. दोनों पार्टियों के नेताओं ने दावा किया कि इस शर्मनाक घटना को उनके कार्यकर्ताओं ने अंजाम दिया. इस प्रकरण के बाद पुलिस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया. मनसे के शीर्ष नेताओं का कहना है कि यूनियन लीडर शरद राव की इस मांग से मराठी रिक्शा चालकों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है. लिहाज़ा यह मांग पूरी तरह बकबास है. पिछले दिनों एक छानबीन से पता चला कि 97 फ़ीसदी ऑटो रिक्शा के मीटरों में छेड़छाड़ की गई और सवारियों से अधिक किराया वसूल किया गया. सबसे अहम बात यह है कि मुंबई में लगभग 95 फ़ीसदी रिक्शा चालक उत्तर भारतीय हैं. मनसे नेताओं का आरोप है कि यूनियन लीडर शरद राव इन रिक्शा चालकों द्वारा सवारियों के साथ मुंहजोरी पर कुछ नहीं बोलते. मनसे का कहना है कि मुंबई में ऐसे ऑटो चालकों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो सवारियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं.

वहीं शिवसेना की ओर से मोर्चा संभाल रहे सांसद संजय राउत ने यूनियन लीडर शरद राव को घमंडी क़रार देते हुए बताते हुए ऐलान किया है कि यदि उन्होंने अपनी मांग वापस नहीं ली तो अंजाम काफी बुरा होगा. वहीं दूसरी तरफ मुंबई ग्राहक पंचायत के अध्यक्ष एड. गिरीष देशपांडे ने शरद राव को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे मुंबई में ऑटो चालकों की हड़ताल करके बताएं. मनसे, शिवसेना और मुंबई ग्राहक पंचायत के नेताओं के रवैये से साफ है कि वे यूनियन लीडर शरद राव के बयान को तूल देना चाहते हैं. ख़ास बात यह है कि मुंबई में ऑटो रिक्शा चालक प्रकरण की गूंज प्रदेश की सत्तारूढ़ गठबंधन तक भी पहुंच गई है. गठबंधन के सहयोगी आपस में ही एक-दूसरे पर निशाना साधने लगे हैं. उपमुख्यमंत्री के खेमे से भी जुबानी जंग शुरू हो चुकी है. ऐसे में सवाल यह है कि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के शासन में आखिर ये क्या हो रहा है? एक तरफ उपमुख्यमंत्री का खेमा कह रहा है कि परिवहन विभाग आपके पास है, लेकिन आप इस समस्या को सुलझाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं. आपकी वजह से ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को राजनीति करने का मौका मिल गया है. मतलब यह हुआ कि आज कल राजनीति ऑटो पर सवार है. एक ओर शरद राव ऑटो रिक्शा हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं तो दूसरी ओर मनसे-शिवसेना उत्तर भारतीय ऑटो चालकों को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं. वहीं तीसरे कोण से राकांपा नेता मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं. यहां रोचक तथ्य यह है कि जिन सवारियों और प्रवासियों के चलते हज़ारों ऑटो रिक्शा चालकों का परिवार पलता है उसकी फ़िक्र किसी भी दलों के नेताओं को नहीं है. एक जमाने में लोग तांगे की सवारी करते थे. यही वजह है कि हिंदी के कई फिल्मों में तांगे-रिक्शे पर फिल्माए गए हैं. ऑटो रिक्शा का भी वॉलीवुड में अहम किरदार है. हालांकि, राज ठाकरे की यह बात कुछ हद तक सही है कि ऑटो चालकों का सवारियों-प्रवासियों के प्रति व्यवहार बेहद खराब है. ऐसे में यूनियन लीडर शरद शरद राव की मांग मानना महाराष्ट्र सरकार के लिए आसान नहीं है, क्योंकि सरकार को इससे काफी परेशानी हो सकती है. मुंबई में ऑटो चालकों के सामने कई समस्याएं हैं जिसका समाधान करना शासन-प्रशासन का काम है. ऑटो चालकों के मुद्दे पर गंदी राजनीति करना प्रदेश के सियासी नेताओं को शोभा नहीं देता. हैरत इस बात की है कि शिवसेना और मनसे खुलेआम मुंबई में उत्तर भारतीय ऑटो चालकों पर जुल्म कर रहे हैं, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री रोमन सम्राट नीरो की भूमिका में हैं.

सयाने यूनियन लीडर शरद राव को सूझा कि क्यों न कुछ नया किया जाए. लिहाज़ा वह ऑटो रिक्शा चालकों को सरकारी कर्मचारी का दर्ज़ा देने की वकालत करने लगे. हालांकि, उनका यह ख्याल महाराष्ट्र के अन्य नेताओं को हजम नहीं हो रहा है. यही वजह है कि शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने उनके खिलाफ़ मोर्चा खोल दिया है. हद तो तब हो गई जब शिवसेना और मनसे के नेताओं ने खुले तौर पर मुंबई के ऑटो चालकों को सबक सिखाने का ऐलान कर दिया.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

कृषि बीमा

फ़ायदा से ज़्यादा नुक़सान

निशा वर्मा

प्रकृति की मार झेल रहे किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने कृषि बीमा योजना शुरू की थी. इस योजना के लागू होने से ऐसा लगा था कि अतिवृष्टि या सूखे पड़ने पर फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई आसानी से की जा सकेगी, लेकिन इस योजना से किसानों को फायदा कम और नुकसान अधिक होता दिखाई देता है. जिन छोटे किसानों को इस योजना की सबसे अधिक गरज है, उन्हें योजना संबंधी जानकारी न होने की वजह से फसल बीमा के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है. इस लिहाज से देखा जाए तो कृषि बीमा योजना का लाभ समुचित रूप से किसानों को नहीं मिल पा रहा है. इससे योजना की विफलता ही साबित होती है. बीमा प्रीमियम भरने के बाद भी किसानों को फसल खराब होने पर अनुदान नहीं मिल रहा. ग़ौरतलब है कि सरकार द्वारा सर्कल निहाय पर कृषि बीमा योजना लागू की गई थी. इस योजना से नागपुर जिले के किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है. कृषि बीमा योजना के तहत बीमित फसल की प्रीमियम भरने के बाद भी हुए नुकसान की भरपाई बीमा कंपनियों द्वारा नहीं की जा रही है. इससे किसानों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. पिछले चार सालों के आंकड़ों का अवलोकन किया जाए तो मात्र 3646 किसानों को ही इस योजना का फायदा मिला है, बाकी किसान इसके लाभ से वंचित ही रहे. इसके उलट बीमा कंपनियां इन योजनाओं से लाखों-करोड़ों का मुनाफा कमा कर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं. हालांकि इस योजना में परिवर्तन करने का आश्वासन सरकार ने ही दिया था, ताकि योजना को अधिक से अधिक कृषि हित में किया जा सके, लेकिन अब तक सारा आश्वासन कोरा ही साबित हुआ है. ध्यान रहे कि पिछले साल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने सर्कल निहाय बीमा योजना की जगह निजी बीमा करने की बात की थी, लेकिन एक साल गुजर जाने पर भी अभी तक सर्कल निहाय के आधार पर ही फसलों का बीमा किया जा रहा है. सर्कल निहाय योजना के अंतर्गत एक सर्कल में आने वाले 10 से 12 गांवों में कृषि को हुए नुकसान का अनुमान लगा कर फसल बीमा योजना या फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाती है. इससे अधिकांश छोटे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. वर्ष 2007 से 2010 के दरम्यान चार वर्ष में जिले के 31,101 किसानों ने 1 करोड़ 74 लाख 78 हजार रुपये की बीमा राशि भरी, लेकिन इन चार सालों में महज 3646 किसानों को 1 करोड़ 31 लाख 16 हजार रुपये के नुकसान भरपाई की गई. इस तरह मात्र चार सालों में ही कृषि बीमा करके बीमा कंपनी 43 लाख 62 हजार रुपये का मुनाफा कमा लिया और कृषक की आर्थिक हालत क्षतिपूर्ति न मिलने से और खराब हो गई. दरअसल बीमा कंपनियों द्वारा योजना के तहत कुल उत्पादन का अनुमान लगाने के बाद हुए नुकसान को देखकर योजना का लाभ किसानों को देती हैं. इस लिहाज से अधिक गांवों में फसलों को नुकसान होने पर कृषि बीमा योजना का लाभ किसानों को मिलता है. इस लिहाज से कृषि बीमा योजना का लाभ विदर्भ की तुलना में राज्य के अन्य हिस्सों के किसानों को अधिक मिला है. विदर्भ को छोड़कर राज्य के अन्य हिस्सों के किसानों को उनकी फसलों को हुए नुकसान की पूरी भारपाई मिली है. विदर्भ में जितने किसानों को नुकसान हुआ है, उससे कम नुकसान कागजातों में दर्शाया गया है. हालत यह है कि दस वर्ष में हुए नुकसान में से मात्र तीन वर्ष के ही आंकड़े निकाले गए. इससे विदर्भ के हजारों किसान कृषि बीमा योजना से मिलने वाले लाभ से वंचित हैं. मतलब यह है कि विदर्भ के किसानों को कृषि बीमा योजना की रकम भरने के बाद भी अपेक्षा से कम लाभ मिल रहा है और उनका नुकसान अधिक हो रहा है.

नागपुर में पिछले शीतकालीन सत्र में विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री चव्हाण ने मिली शिकायतों के मद्देनजर कृषि बीमा योजना सर्कल निहाय की बजाय निजी रूप से फसलों का बीमा करने की घोषणा की थी. उसी दौरान तत्कालीन कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कृषि बीमा नीति में परिवर्तन करने की बात कही थी, लेकिन सत्र खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी घोषणा व आश्वासनों को भुला दिया है. इसीलिए तो कृषि बीमा योजना की नीति में अब तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. इसके कारण विदर्भ के किसान अपनी फसलों का बीमा कराने पर भी हुए नुकसान का अपेक्षित लाभ न मिलने से ठगा महसूस कर रहे हैं. उनके साथ बीमा कंपनियां न्याय नहीं कर रही हैं. इससे उनकी आर्थिक हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ गई है. कर्ज का बोझ अलग से सिर पर है. फिर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र की तैयारियां शुरू हो गई है, लेकिन किसानों को पिछले वर्ष मिले आश्वासन ही अब तक सरकार पूरा नहीं कर पाई है. इस स्थिति में वे न्याय के लिए किसके द्वार जाएं?

feedback@chauthiduniya.com

पिछले चार सालों में कृषि बीमा योजना

वर्ष	खरीफ	भरी गई बीमा रकम	रबी	बीमा रकम
2007	3684	15,45,000	95	11000
2008	5571	24,38,000	510	1,96,000
2009	11928	74,32,000	621	2,09,000
2010	8691	51,91,000	...	...
कुल	29874	1,66,06,000	1226	4,16,000

आवासीय योजना को ग्रहण लगा

ग़रीबों को अपना घर मयस्सर नहीं

राजेश नामदेव

ग़रीबों को एक अदद छत मुहैया कराने के लिए घरकुल (आवास) योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाती है. इस योजना को केंद्र व राज्य सरकार की ओर से धनराशि उपलब्ध कराई जाती है. शुरू में इस योजना के लागू होने से गरीबों को लगा था कि सरकार को उनकी फ़िक्र है. उन्हें उम्मीद थी कि सरकार से आर्थिक मदद मिलने से उन्हें अपना घर नसीब होगा, लेकिन राज्य सरकार की घोर लापरवाही के चलते आवासीय योजना दम तोड़ती नज़र आ रही है. दरअसल एक जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद इस तथ्य का खुलासा हुआ. इस अहम खुलासे में यह स्पष्ट हुआ कि महाराष्ट्र सरकार ने अपने हिस्से की धनराशि का आवंटन नहीं किया, जिस वजह से ग़रीबों के हित में बनाई गई घरकुल योजना पूरी तरह खटाई में पड़ गया है. इतना ही नहीं केंद्र सरकार की ओर से मिली राशि भी वापस लौट सकती है.

ग़ौरतलब है कि केंद्र सरकार ने ग़रीबों को घर उपलब्ध कराने के मक़सद से वर्ष 2005 में एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपड़पट्टी विकास योजना को पूरे देश में लागू किया था. इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने नगर विकास विभाग में 5 लाख 40 हजार 756 घरकुलों के निर्माण को मंजूरी दी थी, लेकिन इस योजना का हश्र भी अन्य योजना की तरह ही हुआ. अब तक पूरे देश में महज 1 लाख 33 हज़ार 748 घरकुलों का निर्माण कार्य शुरू हो सका है. महाराष्ट्र में यह योजना नौ दिन चले अढ़ाई कोस की गति से चल रही है. इस योजना के तहत महाराष्ट्र में 90,072 घरकुलों को मंजूरी दी गई थी, लेकिन वर्ष 2005 से अब तक राज्य में महज 1618 घरकुलों का ही आवंटन किया गया है. इससे पता चलता है कि राज्य में घरकुल योजना का संचालन किस गति से हो रहा है. एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री मुंबई-नागपुर में दलितों-पिछड़ों के कार्यक्रमों में चुनावी मौसम के मद्देनज़र वादों-आश्वासनों की खैरात बांटते घूम रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ग़रीबों के हित में संचालित योजनाओं का सत्यानाश किया जा रहा है. महाराष्ट्र में घरकुल योजना की हालत यह है कि मंजूर 90 हज़ार 72 घरकुलों में से अब तक मात्र 15 हज़ार 302 का निर्माण कार्य शुरू हो सका है. जिन 8 हज़ार 8 सौ 68 घरकुलों का काम पूरा हुआ है उनमें अभी तक सिर्फ 1618 लोगों को ही लाभ मिला है. बाकी 65 हज़ार 902 घरकुलों का अस्तित्व मात्र कागज़ों में ही है. शेष घरों के निर्माण का कार्य कब शुरू होगा यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि राज्य सरकार ने इस योजना के लिए अपने हिस्से की रकम अदा नहीं कर पाई है, जिस वजह से यह योजना अधर में लटक गया है. राज्य सरकार के नुमाइंदे भले ही ग़रीबों को वायदों की जाम पिला रहे हों, लेकिन हक़ीकत यह है कि उन्हें ग़रीबों की कोई चिंता नहीं है.

नगर विकास विभाग के सूत्रों के मुताबिक तकनीकी कारणों की वजह से घरकुल योजनाओं के तहत केंद्र सरकार द्वारा आवंटित राशि का उपयोग न कर पाने से कई नगर परिषदों ने निधि वापस लौटा दी है. योजना को मंजूरी मिलने के बाद निर्धारित समय में घरकुलों का निर्माण कार्य शुरू किया जाना था. निर्धारित समय पर कार्य न शुरू होने और महंगाई बढ़ने के साथ ही निर्माण सामग्री के दामों में भी काफी वृद्धि हुई. इसके अलावा मज़दूरी, रायल्टी में भी कई गुना बढ़ोतरी हुई है. लिहाज़ा कुछ नगर परिषदों द्वारा दो-तीन बार निविदा निकालने के बाद भी कोई ठेकेदार तय राशि में कार्य करने को तैयार नहीं है. यानी महंगाई के बढ़ने से बेहाल ग़रीबों के हित में लागू की गई घरकुल योजना भी महंगाई की शिकार हो गई है. वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि का आवंटन करने की इच्छुक नज़र नहीं आती. इन हालात में योजना का क्रियान्वयन कैसे किया जा सकता है. लिहाज़ा ग़रीबों को सरकारी मदद से घर मिलने का सपना साकार होता नज़र नहीं आता, क्योंकि योजना को महंगाई और सरकार की उदासीनता का ग्रहण लग गया है.

feedback@chauthiduniya.com

नए सिरे से मसौदा बने

घरकुल योजना के बारे में जानकारों व ठेकेदारों का कहना है कि यदि सरकार वाकई में ग़रीबों के प्रति फ़िक्रमंद है तो उसे अपनी योजनाओं में काफी बदलाव करना होगा. इसके अलावा राज्य सरकार को योजना के पूरा होने की समयावधि वर्ष 2012 से बढ़ाकर वर्ष 2014 करना होगा. साथ ही भवन निर्माण सामग्रियों की क़ीमतों में बढ़ोतरी के मद्देनज़र उसे योजना से संबंधित बजट को भी बढ़ाना होगा. पुरानी योजना और बजट के अनुसार घरकुल बनाना असंभव है. यदि सरकार घरकुल योजना का बजट बढ़ाकर उसे अमल में लाए तो यह संभव है कि हज़ारों ग़रीबों के घर का सपना साकार हो सकेगा.

महाराष्ट्र हलचल

नागपुर में आयोजित धम्मचक्र प्रवर्तन की वर्षगांठ समारोह में उपस्थित मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, श्रीमती गवई, केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक, भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी, महापौर अर्चना डेहनकर, स्मारक अध्यक्ष सदानंद फुलझेले व अन्य.

मुंबई के शिवाजी पार्क में शिवसेना की ओर से आयोजित दशहरा सभा में बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, मनोहर जोशी, आदित्य ठाकरे व अन्य गणमान्य लोग.

विजयादशमी के मौके पर नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आयोजित शस्त्रपूजन समारोह में मंचासीन अतिथिगण और अपने गणवेश में खड़े स्वयंसेवक.

कृष्णा-कोयना संगम पर स्थित पूर्व मुख्यमंत्री यशवंत राव चव्हाण के स्मारक स्थल पर भूमिपूजन समारोह में मौजूद मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, वनमंत्री पतंगराव कदम, सतारा जिले के पालक मंत्री रामराजे निवालकर और राज्यमंत्री सतेज पाटिल.

पुणे स्थित सिंबॉयसेस छायाचित्र महाविद्यालय का उद्घाटन करते शिवसेना के कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे. साथ में हैं शिव सेना युवा वाहिनी के प्रमुख आदित्य ठाकरे, संस्था के संस्थापक अध्यक्ष एस.वी मजूमदार, संचालिका डॉ. विद्या येरवाडकर और वीसी डॉ. भूषण पटवर्धन.

नागपुर जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित अनुसूचित जाति-जनजाति सम्मेलन में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक, नागपुर जिला पालक मंत्री शिवाजी राव मोघे, मंत्री नितिन राउत, राजेंद्र मुलक, विधायक सुनील केदार, एस.क्यू जामा, नीलेश पारवेकर और पूर्व सांसद बालकृष्ण वासनिक.

महाराष्ट्र विमानतल विकास कंपनी द्वारा प्रकल्पग्रस्तों के पुनर्वास योजना के तहत घरकुल भूमिपूजन समारोह में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक, राजेंद्र मुलक, पालकमंत्री शिवाजी राव मोघे और नितिन राउत.

भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (सेवानिवृत)

सैन्यबल का शौर्य मुख्यत: बलवान पुरुष मनोवृति और शरीर से संबंधित ही माना जाता है, लेकिन दो बच्चों की मां भी इस शौर्य में पुरुषों की बराबरी कर रही है. यह कर दिखाया भारतीय सेना में प्रवेश पाने वाली 35 वर्षीय सॉपेर शांति टिग्गा ने. शारीरिक क्षमता परीक्षण में वह अपने पुरुष सहयोगियों की अपेक्षा अधिक सक्षम साबित हुई. भारतीय सेना में प्रथम महिला सैनिक होने का सम्मान 35 वर्षीय सॉपेर शांति टिग्गा ने हासिल किया है. हालांकि रेलवे सैन्य रेजीमेंट में महिलाओं के लिए प्रवेश की कोई बाधा नहीं थी, लेकिन उसमें अधिकारी स्तर पर ही महिलाओं की बहाली की जाती थी. नई व्यवस्था के बाद अब यह क्षेत्र भी महिलाओं के हिस्से में आया गया है और उसकी शुरुआत शांति टिग्गा ने किया है. दो बच्चों की मां होने के बावजूद भी टिग्गा ने सैन्य रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट की परीक्षा उतीर्ण किया. अब तक सशस्त्र बलों में महिलाओं की नियुक्ति युद्ध में न जाने वाले विभागों में ही की जाती थी, लेकिन टिग्गा ने अपनी कार्यक्षमता से 12 लाख जवानों की संख्या वाले सशस्त्र सुरक्षा बल में प्रथम महिला जवान होने का सम्मान पाया है. उन्होंने शिविर में उत्कृष्ट प्रशिक्षणार्थी का भी पुरस्कार मिला है.

शिखा अवस्थी को स्वोर्ड ऑफ ऑनर

भारतीय सेना में महिलाओं का पहली बार प्रवेश मेडिकल कोर के जरिए हुआ. सैन्य चिकित्सक महाविद्यालय से सेना बल में वर्ष 1968 में पुनीता अरोड़ा लेफ्टिनेंट जनरल और नौसेना में वाइस एडमिरल जैसे उच्च पद पर पहुंचने वाली प्रथम महिला अधिकारी थीं. भारतीय वायुसेना में भी महिलाओं का समावेश अधिकारी पद तक ही सीमित रहा. युद्ध भूमि पर भी महिलाओं की बहाली भारत में आज तक नहीं हुई थी.

महिला पायलट

स्नेहा शेखावत और उसकी सहयोगी तेजश्री पाटिल ये दोनों ही फ्लाइंग ऑफिसर्स पायलट हैं. ऊंची उड़ान भरने का उनका सपना पूरा हुआ है. यातायात के काम में आने वाले हेलीकाप्टर्स और हवाई जहाज चलाने वाली महिलाओं की संख्या कम है पर निडर महिलाओं का समूह इसका प्रतिनिधित्व करता है. तेजश्री के अनुसार जम्मू-कश्मीर या जहां अच्छी चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, ऐसी जगहों से जख्मी सैनिकों को वापस लाने का काम बहुत साहसिक, नैतिक और समाधान कारक है. वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में प्रसिद्ध हुई महिला फ्लाइंग ऑफिसर गुंजन सक्सेना का चेहरा आज भी सबके स्मरण में है. उसके चीता हेलीकॉप्टर ने दुश्मन की सीमा मे प्रवेश कर अपने घायल जवानों को वापस लाने का साहसिक कार्य कर दिखाया था.

कुछ अनुत्तरित सवाल

प्रत्यक्ष लड़ाई में महिलाओं की सहभागिता अभी तक अधूरा सपना ही रहा है. शारीरिक रूप से पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कमजोर होती हैं, लेकिन वे बौद्धिक और मानसिक रूप से युद्धक्षेत्र में सक्षम होती हैं. यद्यपि अनुशासन पालन व सहयोगियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने में भी वे पुरुषों की तुलना में ज्यादा सक्षम मानी जाती हैं. गौरतलब है कि भारतीय सेना में 90 प्रतिशत जवान पुरूष प्रधान सामाजिक व्यवस्था वाले ग्रामीण भाग से आते हैं. भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पुरूष प्रधान संस्कृति है. घर का चूल्हा और बच्चों को संभालना ही महिलाओं का कर्तव्य है. ऐसी उनकी मानसिकता है. यह मानसिकता एक रात में बदलने वाली नहीं है. आज केंद्रीय अर्ध सैनिक बल और सीमा सुरक्षा बल में कुल 11 हजार 412 महिलाएं हैं. यह आंकड़ा कुल सैनिकों का 1.5 प्रतिशत है. सेना में 4,101 महिलाएं है, लेकिन वे सहायक विभाग, सिग्नल व्यवस्था, तकनीकी विशेषज्ञ और बारूदगोला आदि की आपूर्ति तक सीमित हैं. भारतीय नौसेना में 252 महिलाएं हैं, लेकिन वहां भी उनकी जहाज़ या पनडुब्बी में बहाली नहीं की जाती है. वायुसेना में 872 महिलाएं कार्यरत हैं. यहां युद्धक्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी विभागों में महिलाओं को शामिल किया जाता है. सेना में महिलाओं की इस तरक्की को मान लिया जाए, तब भी कुछ सवाल अभी भी अनुत्तरित ही हैं.

feedback@chauthiduniya.com

सुनहरा अवसर

चौथी दुनिया

पत्रकारिता में रूचि रखने वालों के लिए 'साप्ताहिक चौथी दुनिया' से जुड़ने का सुनहरा अवसर

1- वार्ड प्रतिनिधि : नागपुर के सभी वार्डों के लिए

2- कॉलेज प्रतिनिधि : नागपुर के सभी कॉलेज के लिए

वार्ड व कॉलेज प्रतिनिधि बनने के उम्मीदवार अपने बायोडाटा व दो पासपोर्ट फोटो के साथ आवेदन कर सकते हैं.

संपर्क- साप्ताहिक चौथी दुनिया

आशीर्वाद पब्लिकेशन

मुरलीधर कॉम्प्लेक्स, बुटीवाड़ा के सामने, होटल गणराज के बाजू में, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी नागपुर

E-mail : chauthiduniyaa@gmail.com

दीपावली की ख़ुशी किसके लिए

भ्रष्टाचार, हिंसाचार और अमानवीय कृत्यों का अंधेरा चारों तरफ पसरा हुआ है. हर जगह असहिष्णुता का वातावरण है. देश में आतंकवादी हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है. नक्सलियों का आदिवासी इलाकों में हिंसक तांडव हो रहा है. सभी ओर अशांति का आलम है. अमीरी-गरीबी की खाई कम होने की बजाय चौड़ी होती जा रही है. सत्ताधीश जनता से जुड़े मुद्दों के प्रति असंवेदनशील हैं. मंहगाई सुरसा की तरह मुंह फैलाती जा रही है. आम आदमी को दो वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ता है. नौजवानों को रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है. महिलाओं को घर से निकलने पर अपनी आबरू की चिंता सताती है. समाज में अपराध और दुराचार बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे हालात में दीपावली पर लाखों दीप जलाने के बाद भी अंधकार का साम्राज्य कायम रहता है. ऐसे में यह सवाल उठता है कि दीपावली पर ऐसा क्या किया जाना चाहिए ताकि लोगों के मन व्याप्त अंधेरा को मिटाया जा सके?

देश आर्थिक प्रगति कर रहा है. हर गांव और शहर में विकास भी हो रहा है. संसाधनों में वृद्धि हो रही है, लेकिन यह सब किसके लिए किया जा रहा है? देश की आम जनता को आज भी 20-30 रुपये में ही गुजारा करना पड़ रहा है. एक तरफ देश में अरबपति-करोड़पतियों की संख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर गरीबी में भी इजाफा हो रहा है. गरीब आदमी अपनी लाचारी में अपने बच्चों को पांच-दस हजार में बेचने को मजबूर हो रहे हैं. गरीबी की वजह से युवतियां प्राणों से प्रिय अपनी आबरू बेचने को मजबूर हैं. समाज में ऊंच-नीच की खाई पैदा हो रही है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि इन सामाजिक समस्याओं से बेफिक्र होकर नित्य नए घोटाले कर रहे हैं. ऐसे हालात में आम आदमी की दिवाली कैसी होगी?

दीपावली का पर्व जब भी आता है तो कुछ सवाल अक्सर लोगों के जेहन में उठते हैं कि आखिर दीपावली पर धन की पूजा क्यों? क्या पैसा ही आज भगवान है? यदि पैसा ही भगवान है तो लक्ष्मीपूजन का ढोंग क्यों? लक्ष्मी की पूजा करते हैं पर उसके वाहन उल्लू को अपशकुन क्यों मानते हैं? पटाखे फोड़कर वातावरण को प्रदूषित क्यों किया जाता है? क्यों अनावश्यक रोशनी करके बिजली का नुकसान किया जाता है? ऐसे तमाम सवालों को पूछने वालों को लोग पागल करार देते हैं. यह अफसोसनाक है कि जो लोग अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं वे भी इन सवालों का जवाब देने से कतराते हैं. सभी एश्वर्य पाने की होड़ में शामिल हैं. चारों तरफ अधिक से अधिक धन अर्जित करने की आपा धापी मची हुई है. आज देश में भ्रष्टाचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन घोटालेबाजों की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता सब कुछ चलता है की तर्ज पर उनका कारोबार बदस्तूर जारी रहता है. लोग जितने अधिक पढ़-लिखकर समझदार हो रहे हैं उनकी धन-दौलत जोड़ने की हवस भी बढ़ती जा रही है. इसके लिए वे किसी भी स्तर तक जा सकते हैं. इससे तो यही लगता है कि मौजूदा समय में पैसा ही भगवान बन गया है. इसलिए उसकी चाहत में मानवीय मूल्यों में गिरावट देखी जा रही है. यही वजह है कि आज समाज में चरित्र का संकट खड़ा हो गया है. पर्यावरण की चिंता सबको है, लेकिन दिवाली आते ही पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने की सीख सब भुला दिया जाता है. इसी तरह बिजली का मामला है. एक तरफ सरकार ऊर्जा बचाओ अभियान पर लाखों-करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन ऊर्जा बचाओ अभियान को सबसे अधिक चूना तो वही लोग लगा रहे है जो बिजली बचत करने का उपदेश देते हैं. पहले दीपावली पर दीपक जलते थे. आज बिजली का उत्पादन कम होने के बावजूद मंत्रियों के बंगलों पर दिवाली पर अद्भुत रोशनी की जाती है. दिवाली पर बिजली की बर्बादी होने के बाद जब देश के भविष्य कहलाने वाले नौनिहाल वार्षिक परीक्षा देने की तैयारी में जुटे रहते हैं तब लोडशेडिंग का कहर टूटता है. बिजली की आंखमिचौनी उनकी पढ़ाई में बाधक बन जाती है. महाराष्ट्र में लोडशेडिंग का कहर तो अभी से शुरू हो गया है. कहने का मतलब यह है कि दिवाली में चकाचौंध के बाद अंधकार और बढ़ जाता है.

इस लिहाज से देखा जाए तो दिवाली दिवाला निकालने वाला त्यौहार बनता जा रहा है. एक तो वैसे ही महंगाई से आम जनता परेशान है. उसके लिए तो दिवाली तो दिवाला निकालने वाली ही साबित हो रही है. यानि आज दीपावली का यह पर्व श्रीमंतों के लिए अपनी धन, गहनों के प्रदर्शन का है. घरों में खूब रोशनी रहती है पर मन में अंधेरा छाया रहता है. दीपावली की सार्थकता तब है जब बाहर की बजाय मन रौशन हो.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467

शिवसेना-भाजपा गठबंधन में अविश्वास

युधिष्ठिर जोशी

कुछ साल पहले तक महाराष्ट्र भाजपा शिवसेना की ताल पर थिरक रही थी. उन दिनों तब पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्य की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले भाजपा नेता प्रमोद महाजन का भारतीय जनता पार्टी में पूरा वर्चस्व था. महाजन की अंगुली के इशारे पर ही भाजपा का सारा कार्यभार चलता था. सियासी जानकारों की मानें तो शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे और प्रमोद महाजन के प्रयत्न से ही शिवसेना और भाजपा गठबंधन बना था, लेकिन पच्चीस सालों से भी अधिक समय से कायम गठबंधन में अब विवाद खड़े हो रहे हैं. दोनों दलों में गठबंधन होने के बावजूद भी कई मसले पर अविश्वास कायम है. प्रमोद महाजन जब तक जीवित थे, तब तक प्रदेश में भाजपा–शिवसेना गठबंधन में कोई दरार नहीं थी. अगर कुछ मुद्दे पर असहमतियां बनती भी थी तो प्रमोद महाजन उसे अपनी समझ से दूर करते थे. यही वजह था कि लोग उन्हें पार्टी का चाणक्य भी कहते थे. हालांकि राज्य में भारतीय जनता पार्टी को उनकी काफी कमी खल रही है. वहीं दूसरी तरफ शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे शरीर से थक गये हैं. उन्हें कई बीमारियों ने भी घेर रखा है. यही वजह है कि शिवसेना प्रमुख ने अपने बड़े बेटे उद्धव ठाकरे को पार्टी की कमान सौंप दी है. शिवसेना की पहली पीढ़ी के सहयोगी वृद्धावस्था की ओर बढ़ चले हैं. उसकी तुलना में दूसरी पीढ़ी के उद्धव के सहयोगियों का जोश बहुत ही कम है. शिवसेना के दबंग नेता राज ठाकरे ने शिवसेना को छोड़कर नई सेना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खड़ी की है. उद्धव और राज ठाकरे की तुलना करें तो राज ठाकरे के पास युवा कार्यकर्ताओं की ताकत अधिक हैं. मुंबईकरों को शिवसेना अपनी लगती है. राज और उद्धव के राजनीतिक क्षमताओं का परीक्षण करने पर जो नतीज़े सामने आते हैं, उनको देखा जाए तो राज को अधिक अंक मिलते हैं. राजनीतिक कुशलता में भी राज ठाकरे आगे हैं.

महाराष्ट्र में 10–15 साल पहले भाजपा का कोई खास वजूद नहीं था. इसीलिए भाजपा ने शिवसेना से गठबंधन कर पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया. इस गठबंधन को कामयाब बनाने में प्रमोद महाजन ने अहम भूमिका निभाई थी. हालांकि, एक सच्चाई यह भी है कि शिवसेना ने हमेशा भाजपा को दूसरे स्थान पर ही रखा. प्रमोद महाजन के निधन के बाद भाजपा के नये नेतृत्व ने कभी सीधे तौर पर तो कभी अप्रत्यक्ष से रूप से शिवसेना को समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन शिवसेना ने हमेशा उनकी बात अनसुनी की. वास्तव में देखा जाए तो विधानसभा और विधानपरिषद में भाजपा का संख्या बल शिवसेना से अधिक है. दोनों सदनों में भाजपा के नेता विपक्षी दल के नेता हैं. ऐसा होने पर भी शिवसेना भाजपा को खास भाव देने के मूड में नहीं है. भाजपा को नीचा दिखाने का एक भी अवसर शिवसेना नहीं छोड़ती. शिवसेना के पास मुंबई महानगर पालिका के साथ ही ठाणे और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की सत्ता है.

मुंबई महानगर पालिका की सत्ता होने का मतलब किसी राज्य का अपने कब्जे में होने के बराबर है. मुंबई महानगर पालिका का बजट करोड़ों रुपये का है. इसी तरह ठाणे और कल्याण–डोंबिवली महानगर पालिका भी शिवसेना के पास हैं. कल्याण–डोंबिवली महानगर पालिका में राज ठाकरे की मनसे के सबसे ज्यादा सदस्य चुन कर आए हैं बावजूद इसके उन्होंने सत्ता के किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं हैं. इस वजह से वहां की सत्ता शिवसेना को मिली है. ठाणे और मुंबई महानगर पालिका में मनसे के सदस्य कम होने के बावजूद चार साल पहले की स्थिति में आज जमीन–आसमान का फर्क है. पहले की अपेक्षा आज मनसे अधिक मजबूत है.

पिछले दिनों जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सद्भावना अनशन पर बैठे थे उससे ठीक पहले राज ठाकरे गुजरात में मौजूद थे. अहमदाबाद के उस कार्यक्रम में राज ठाकरे ने मोदी को शुभकामनाएं भी दी थी. उन्होंने गुजरात में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जमकर गुणगान किया. इसके चलते उद्धव ठाकरे को काफी तकलीफ हुई. इसे लेकर दोनों युवा ठाकरे बंधुओं में जमकर बहस भी हुई. राज ठाकरे जब गुजरात गए तब उन्होंने वहां के विकास कार्यों की प्रशंसा की. मोदी के काम और नीतियों की स्तुति भी की. राज ठाकरे के गुजरात दौरे के पीछे मक़सद मुंबई के गुजराती समाज में मनसे के प्रति सहानुभूति पैदा करना था. एक अनुमान के मुताबिक मुंबई में गुजराती समाज के लोग काफी संख्या में हैं. लगभग 30–40 प्रभाग निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी सफलता और असफलता गुजराती समाज के मतों पर निर्भर है. माना जा रहा है कि गुजराती युवा मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए राज ठाकरे ने यह चाल चली है.

राजनीति में आलोचनाएं कोई नई बात नहीं है. नरेंद्र मोदी की भी कई मसलों पर निंदा–शिकायत की जाती है. इसके बावजूद नई गुजराती पीढ़ी के दिलों में नरेंद्र मोदी के लिए काफी सम्मान है. दरअसल यह बात राज ठाकरे ने समझ ली है और अपनी इस चाल से शिवसेना को करारा झटका दिया है. इसी कारण से उद्धव ठाकरे असहज हो गए हैं. प्रमोद महाजन के निधन के पश्चात भाजपा–शिवसेना के बीच होने वाले संवाद का स्तर भी काफी नीचे गिर गया है. हालांकि गडकरी और गोपीनाथ मुंडे शिवसेना के व्यवहार से काफी आहत हैं. इधर शिवसेना में भी भाजपा के प्रति गंभीरता दिखाई नहीं देती है. जानकारों की मानें तो दोनों पुराने सहयोगियों के बीच चल रहे इस शीत युद्ध से गठबंधन में दरार और चौड़ी हो सकती है. जहां एक ओर शिवसेना अपना हठ छोड़ने को तैयार नहीं, वहीं भाजपा भी शिवसेना के आगे अब और झुकने को तैयार नहीं. इस वजह से पंद्रह साल पुराना भाजपा–शिवसेना गठबंधन कितने दिनों तक कायम रहता है यह एक बड़ा सवाल है.

इसमें कोई शक नहीं कि राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ताकत बढ़ रही है. इसके मद्देनज़र भाजपा के एक धड़े का मानना है कि शिवसेना के साथ गठबंधन करने की बजाय मनसे के साथ गठबंधन क्यों नहीं किया जाए? महाराष्ट्र और गुजरात पड़ोसी राज्य हैं. अहमदाबाद से मुंबई और मुंबई से हजारों लोग रोज आते–जाते हैं. दोनों राज्य के मध्य करोड़ों रुपयों का कारोबार होता है, जो दोनों राज्यों के बीच व्यवसायिक संबंधों को रेखांकित करता है. मुंबई शहर में गुजराती समाज की बहुलता को ध्यान में रखते हुए ही राज ठाकरे ने नरेंद्र मोदी का यशोगान किया. इसलिए भाजपा और मनसे की निकटता बढ़ना स्वाभाविक है. यह बात शिवसेना के ध्यान में आते ही उसने एक साथ मनसे और भाजपा पर हमला करना शुरू कर दिया है. इस स्थिति में गठबंधन से सहयोगी भाजपा को दूर जाने का आभास शिवसेना को जरूर हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा को शिवसेना की जरूरत पड़ेगी. यही कारण है कि बार–बार अपमानित होने के बाद भी भाजपा शिवसेना के साथ अपने गठबंधन को न चाहते हुए भी कायम रखना चाहती है. वैसे आगामी महानगर पालिका चुनाव में शिवसेना–भाजपा गठबंधन टूटेगा ऐसा नहीं लगता, लेकिन चुनाव में शिवसेना के हाथ से महानगर पालिका की सत्ता गई तो भाजपा और शिवसेना की मित्रता एक क्षण में ख़त्म हो सकती है. आगामी महानगर पालिका के चुनावों में शिवसेना–भाजपा गठबंधन नाम मात्र ही रहेगा, क्योंकि दोनों दल के कार्यकर्ता एक–दूसरे के उम्मीदवार को हराने के लिए पूरी ताकत लगा सकते हैं. अगर ऐसा हुआ तो इसका लाभ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को होना तय है.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिन्दी का पहला साप्ताहिक अखबार
महाराष्ट्र

सदस्यता फार्म (वार्षिक)

सदस्यता शुल्क- २५० /- रुपये
मैं "चौथी दुनिया" साप्ताहिक समाचार पत्र का सदस्य बनना चाहता/चाहती हूँ।
मेरा नाम श्री./ श्रीमती .....
मेरा पता .....
जिला.....राज्य .....पिन कोड.....
फोन (आ).....(का).....मोबाईल.....
ई -मेल.....
मैं रु. वार्षिक सदस्यता के लिए चेक क्रमांक.....
दिनांक .....बैंक.....शाखा..... द्वारा भेज रहा/ रही हूँ

नोट- यह सदस्यता शुल्क भारत में ही मान्य है तथा यह योजना सीमित अवधि के लिए है। समाचार पत्र केवल साधारण डाक द्वारा भेजा जाएगा।

सदस्यता शुल्क केवल चेक द्वारा आशीर्वाद पब्लिकेशन प्रा. लि. नागपुर के पक्ष में सदस्यता फार्म के साथ निम्नलिखित पते पर प्रषित करे या फिर हमारे प्रतिनिधी को फार्म कलेक्ट करने के लिए फोन पर सूचित करे.

कार्यालय
"चौथी दुनिया"- महाराष्ट्र,
आशीर्वाद पब्लिकेशन प्रा.लि.,
मुरलीधर कॉम्प्लेक्स, बुटीवाडा के सामने,होटल गणराज के बाजू में, टेम्पल बाजार रोड,सीताबर्डी, नागपुर.
फोन नं.-०७१२-२५४३१११ फैक्स- ०७१२-२५४७१११
Email: chauthiduniyaa@gmail.com

पाठक ध्यान दें
जिन पाठको कों चौथी दुनिया की वार्षिक सदस्यता चाहिए वे फार्म भरकर भेजें या कार्यालय में संपर्क करें.

चौथी दुनिया
हिन्दी का पहला साप्ताहिक अखबार

कार्यालय स्थानांतरित

साप्ताहिक चौथी दुनिया के कार्यालय का स्थानांतरण 28 सितंबर को सीताबर्डी स्थित मुरलीधर काम्प्लेक्स में हो गया है. अतः चौथी दुनिया के सभी पाठकों, एजेन्टों व हॉकरो से अनुरोध है कि वे कार्यालयीन कार्य के लिए नीचे दिए पते पर संपर्क करें–

साप्ताहिक चौथी दुनिया
आशीर्वाद पब्लिकेशन
मुरलीधर कॉम्प्लेक्स, बुटीवाड़ा के सामने, होटल गणराज के बाजू में, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी नागपुर
E-mail : chauthiduniyaa@gmail.com

Postal Regn. No.RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 24 अक्टूबर-30 अक्टूबर 2011

असिन ने अपनी फिल्म अम्मा नन्ना ओ तमिल अम्मई का चरित्र इस रीमेक फिल्म में भी निभाया, लेकिन यहां उन्हें तमिल लड़की की जगह मलयाली लड़की के रूप में चित्रित किया गया.

हॉलीवुड से...

ज़िद पर अड़ी हैं निकोल

एक ट्रांसजेंडर पेंटर पर आधारित निकोल किडमेन की फिल्म के निर्माण में आने वाली मुश्किलें बढ़ गई हैं. द डैनिश गर्ल नामक इस फिल्म में वह खुद आर्टिस्ट लिली एल्बे के ट्रांसजिशन के पहले और बाद के व्यक्तित्व का किरदार निभाने वाली हैं. यह फिल्म निकोल की प्रोडक्शन कंपनी द ब्लोसम फिल्म्स का एक महत्वाकांक्षी प्रोजक्ट है. यह फिल्म निर्माण से पहले ही विवादों में है और अब तक तीन बड़ी अभिनेत्रियों को एल्बे की पत्नी के रोल से हटाया जा चुका है. गायनथ पेल्ट्रा और चार्लीज थेरॉन का नाम भी सामने आया, लेकिन उनके पास समय की कमी के चलते बात नहीं बन सकी. रैशल वाइज को पिछले साल साइन किया गया था, लेकिन वह भी पीछे हट गईं. निकोल आज भी फिल्म बनाने के मूड में हैं. एल्बे वह पहली हस्ती हैं, जिन्होंने इस साल सर्जरी के जरिए लिंग परिवर्तन कराया था. एल्बे लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम से ग्रसित थीं. निर्देशन की कमान टॉमस एजफ्रेडसन को सौंपी गई है.

अभिनय का अर्जुन

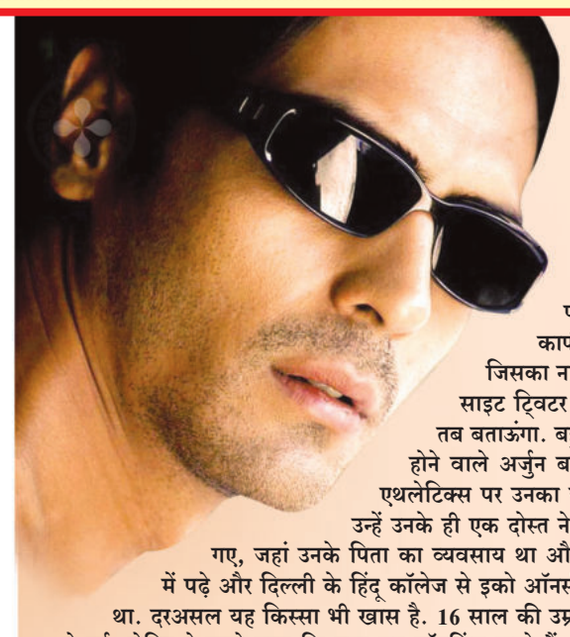

फैशन मॉडल से अभिनय की तरफ रुख करने वाले अर्जुन रामपाल काफी खुश हैं. इस खुशी का कारण उनकी नई फिल्म है, जिसमें वह एक नए लुक में नज़र आएंगे. यह दीपावली उनके लिए दो मायनों में खास है, पहला तो यह कि दीपावली उनका पसंदीदा पर्व है और दूसरा यह कि मोस्ट अवेटेड फिल्म रा-वन इसी दिन रिलीज होगी. पिछले काफी समय से अर्जुन इस फिल्म के प्रोमोशन में लगे हैं. इसमें उन्होंने विलेन की भूमिका निभाई है जिसका नाम रावण है. इसके अलावा और भी कारण हैं अर्जुन के खुश होने के. अर्जुन ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर लिखा है कि मैं स्टार वर्ल्ड पर एक शो करने जा रहा हूं. शो का नाम जब तय हो जाएगा, तब बताऊंगा. बहुत जल्द इसका प्रोमो लिंक भेजने वाला हूं. बच्चों की फिल्म में नजर आनेवाले बच्चों से उत्साहित होने वाले अर्जुन बचपन में काफी शरारती थे. दसवीं तक उनका ध्यान पढ़ाई पर नहीं था. उस वक़्त टेनिस एवं एथलेटिक्स पर उनका ज़्यादा ध्यान था. पढ़ाई से बचने के लिए खेल एक बहाना बन गया था. इस बात का एहसास उन्हें उनके ही एक दोस्त ने दिलाया. जबलपुर में उनके जन्म के बाद उनके माता-पिता नासिक के पास देवलाली में बस गए, जहां उनके पिता का व्यवसाय था और मां टीचर थीं. यहीं पर उनका बचपन बीता. उसके बाद वह कोडाईकनाल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े और दिल्ली के हिंदू कॉलेज से इको ऑनर्स किया. मॉडलिंग की शुरुआत में रोहित बल जैसे डिजायनर से टकराना एक खूबसूरत इत्तेफाक था. दरअसल यह किस्सा भी खास है. 16 साल की उम्र में जब वह मुंबई आए तो पहली बार एक डिस्कोथेक में गए, जहां उनकी मुलाकात रोहित बल से हुई. रोहित ने उनसे पूछा कि क्या वह मॉडलिंग करते हैं, लेकिन दिलचस्पी न होने की वजह से उन्होंने मना कर दिया. उनका मानना था कि मॉडलिंग लड़कियों के लिए ही ठीक है. उसके बाद जब वह हिंदू कॉलेज में मॉडलिंग करने लगे तब एक बार फिर डिस्कोथेक में उनकी मुलाक़ात रोहित बल से हुई, लेकिन मॉडलिंग में उनकी दिलचस्पी न होने की वजह से वह उब गए थे, पर रोहित ने अर्जुन को उनके नाम से पहचानते हुए अगले दिन शूटिंग पर आने का न्योता दे दिया. दरअसल वह कैमरे के पीछे रहना चाहते थे और फिल्म मेकिंग जैसी चीजों पर ध्यान देना चाहते थे. इसके लिए वह न्यूयॉर्क फ़िल्म स्कूल में भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन मॉडलिंग का सीधा रास्ता उन्हें बॉलीवुड की तरफ ले गया, जहां उन्होंने कई हिट और कई फ्लॉप जैसे उतार-चढ़ाव देखे. 2001 में फ़िल्म मोक्ष प्रदर्शित हुई, जिसे अशोक मेहता ने निर्देशित किया था. यह उनकी दूसरी फ़िल्म प्यार, इश्क़ और मोहब्बत के बाद रिलीज हुई. इसमें उन्होंने सुनील शेट्टी और आफ़ताब शिवदासानी के साथ काम किया था. हालांकि दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, पर आलोचकों ने दोनों ही फ़िल्मों में उनके अभिनय की सराहना की. 2002 में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय भारतीय फ़िल्म अकादमी से फ़ेस ऑफ़ द इयर पुरस्कार जीता. उन्होंने आंखें (2002), दिल है तुम्हारा (2002), और एक अजनबी (2005) जैसी फ़िल्मों में काम किया. अधिकांश फ़िल्मों में वह सहायक भूमिकाओं में नज़र आए. उन्होंने शाहरुख़ ख़ान, रानी मुखर्जी, सैफ़ अली ख़ान, प्रीति ज़िंटा और प्रियंका चोपड़ा जैसे सितारों के साथ मिलकर टेंपटेशन 2004 में भाग लिया. 2006 में उन्होंने मल्टी स्टारर फ़िल्म कभी अलविदा ना कहना में अतिथि भूमिका और 1978 में अमिताभ बच्चन अभिनीत फ़िल्म डॉन के रीमेक डॉन-द चेस बिगिन्स अगेन में एक सहायक की भूमिका निभाई. अर्जुन ने स्वयं के प्रोडक्शन हाउस चेसिंग गणेशा फ़िल्म्स के ज़रिए इसका निर्माण किया. उनकी पत्नी मेहर जेसिया सहनिर्माता थीं. इसके बाद फ़राह ख़ान की फिल्म ओम शांति ओम (2007) में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए उन्हें समीक्षकों ने काफी सराहा. यह बॉलीवुड के इतिहास में सबसे बड़ी हिट फ़िल्मों में से एक थी. 2007 में अर्जुन ने ऋतुपर्णो घोष कृत कलात्मक फ़िल्म द लास्ट लियर में अमिताभ बच्चन एवं प्रीति ज़िंटा के साथ अभिनय किया. 2008 में रामपाल ने रॉक ऑन में अभिनय किया. अर्जुन ने पूर्व मिस इंडिया मेहर जेसिया से शादी की. उनकी दो बेटियां हैं, माहिका और माइरा.

शीला की कहानी

राखी को रीयल किस देकर चर्चा में छाने वाले मीका अपनी आने वाली फिल्म में शीला की ड्रेस पहने एक लड़की को किस करते नज़र आएंगे. मीका ने बिना हिचक स्वीकार भी कर लिया कि वह शीला के नाम को भुनाना चाहते हैं. अब शीला यानी कैटरीना कैफ इस बात का क्या मतलब निकालती हैं, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल उनके पास इन सब बातों के समय नहीं है. यशराज फिल्म्स की इस फिल्म का नाम है एक था टाइगर, जो अगले साल एक जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब 2012 में ही ईद के दिन रिलीज होगी. चूंकि आमिर खान अगले साल एक जून को अपनी फिल्म, जो रीमा कागती द्वारा निर्देशित है, को रिलीज करना चाहते हैं. इसलिए उन्होंने सलमान खान और आदित्य चोपड़ा से अनुरोध किया कि वे एक था टाइगर की रिलीज डेट बदल दें. करीबी रिश्ते और आपसी सम्मान के चलते बात बन गई. कबीर खान द्वारा निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा प्रोड्यूस इस फिल्म में कैटरीना कैफ और सलमान खान लीड रोल में हैं. फिल्म आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखी कहानी पर आधारित है, पटकथा- संवाद लेखन कबीर खान एवं नीलेश मिश्रा का और संगीत दिया है सोहेल सेन ने.

भाग्यशाली अजय

अजय देवगन की गिनती बॉलीवुड के उन सितारों में होती है जो कम पैसा लेते हैं और सुपरहिट फिल्म देते हैं. अजय ने पिछले कुछ वर्षों में कई हिट फिल्में दी हैं. हाल में आईं उनकी फिल्म गोलमाल-3 और सिंघम ने 100 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का व्यवसाय किया, लेकिन अजय ने अपनी कीमत नहीं बढ़ाई, लेकिन इसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब समय आ गया है प्राइस बढ़ाने का. जब कम हिट फिल्म देने वाले हीरो दोगुनी कीमत वसूल रहे हैं तो अजय भला क्यों पीछे रहें. ख़बर है कि अजय ने वासु भगनानी की अगली फिल्म करने के बदले में 18 करोड़ रुपये वसूले हैं. यह फिल्म सुपरहिट फिल्म हिम्मतवाला (1983) का रीमेक है. हिम्मतवाला ने श्रीदेवी को स्टार बना दिया था और जितेंद्र के करियर को मजबूती दी थी. वासु को लगता है कि आज के दौर में हिम्मतवाला का रीमेक काम कर सकता है. जितेंद्र का रोल निभाने के लिए उन्होंने अजय को चुना. अजय ने बढ़ी हुई प्राइस बताई, वासु तुरंत तैयार हो गए. अजय के पास कई टीवी शो के भी ऑफर आ रहे हैं. अजय का मानना है कि कठिन परिश्रम के साथ-साथ आपकी तकदीर भी आपके साथ होनी चाहिए. मुझे तकदीर ने बहुत साथ दिया, बॉलीवुड में काम करने का ऑफर मिला. बीस वर्ष हो गए, लेकिन प्रशंसक मुझसे कभी निराश नहीं हुए.

बहन भरोसे शमिता

शिल्पा ने बॉलीवुड में जो मुकाम हासिल किया है, वहां तक पहुंचना शमिता के लिए लगभग नामुमकिन है. यशराज कृत मोहब्बतें जैसी फिल्म मिलने के बावजूद शमिता कोई कमाल नहीं दिखा पाईं. अनुभव सिन्हा की फिल्म दस में शमिता को रोल मिल पाया तो केवल शिल्पा शेट्टी की वजह से. जब शिल्पा शेट्टी यूके के रियलिटी शो बिग बॉस से लौटीं तो यहां के शो बिग बॉस में शमिता शेट्टी को भी एंट्री मिल गई. जब-जब शिल्पा शेट्टी हाईलाइट हुईं, तब-तब शमिता शेट्टी भी फ्रेम में नज़र आईं. चाहे वह आईपीएल मैच हो या शिल्पा की शादी. लगता है, बहन को कामयाब बनाने के लिए शिल्पा को फिल्म भी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी.

तुम जियो हजारों साल

असिन

अभिनेत्री असिन को कौन नहीं जानता. आमिर खान के साथ फिल्म गजनी करने के बाद वह पूरे देश में प्रसिद्ध हो गईं. इससे पहले वह दक्षिण फिल्मों की अभिनेत्री थीं. असिन थोट्टूमकल का जन्म केरल के कोची में 26 अक्टूबर, 1985 को हुआ था, संयोगवश इस साल इसी दिन दीवाली है. उनके जन्मदिन पर आपको बताते हैं कि वह बॉलीवुड से पहले क्या कर रही थीं. असिन थोट्टूमकल ने 2001 में सथ्यन अंथिक्कड़ी की मलयालम फिल्म नरेंद्र मकान जयकंथान वाका में सहायक अभिनेत्री की भूमिका करके अभिनय के क्षेत्र में प्रवेश किया, तब उनकी उम्र 15 साल की थी. एक साल तक फिल्म जगत से बाहर रहने के बाद असिन एक अभिनेत्री के रूप में फिल्म अम्मा नन्ना ओ तमिल अम्मई में रवि तेजा के साथ वापस आईं. तेलुगु भाषा में यह उनकी पहली फिल्म थी, जिसमें उन्होंने एक तमिल लड़की का चरित्र निभाया, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का तेलुगु फ़िल्म फेयर अवॉर्ड दिलाया. उसी साल उन्होंने अपनी दूसरी तेलुगु फिल्म शिवमणि में नागार्जुन के साथ अच्छे प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का संतोषम पुरस्कार जीता. इसके बाद आईं दो तेलुगु फिल्में, लक्ष्मी नरसिम्हा और घर्षण. दोनों में उन्होंने पुलिस अधिकारी की प्रेमिका की भूमिका निभाई और तेलुगु फिल्म उद्योग में एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में उनका स्थान मजबूत होता चला गया

असिन को पहली व्यवसायिक सफलता 2003 में अम्मा नन्ना ओ तमिल अम्मई नामक फिल्म से मिली. कई फ़िल्में प्रदर्शित होने के बाद तमिल फिल्म गजनी (2005) में अपने प्रदर्शन केलिए उन्हें दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दक्षिण फ़िल्म फयर पुरस्कार मिला. उन्होंने कई सफल फिल्में कीं. रोमांचक फिल्म गजनी (2005) और एक्शन कॉमेडी फिल्म वारालारू (2006) में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई. हाल में असिन ने फिल्म गजनी से बॉलीवुड में प्रवेश किया, जो उनकी इसी नाम की तमिल फिल्म की रीमेक है और इसके लिए उन्होंने प्रथम फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनय का फ़िल्म फेयर पुरस्कार भी जीता.

असिन की पहली तमिल फिल्म एम कुमारन सन ऑफ महालक्ष्मी थी, जिसमें उन्होंने जयम रवि के साथ अभिनय किया. असिन ने अपनी फिल्म अम्मा नन्ना ओ तमिल अम्मई का चरित्र इस रीमेक फिल्म में भी निभाया, लेकिन यहां उन्हें तमिल लड़की की जगह मलयाली लड़की के रूप में चित्रित किया गया. यह फिल्म 2004 के दौरान तमिल सिनेमा की सबसे सफल फ़िल्मों में से एक बन गई. एक संक्षिप्त अंतराल में तेलुगु फिल्म चक्रम करने के लिए लौटने के बाद वह उल्लम केटुकुमाए में भी दिखाई दीं. यह फिल्म 2002 में असिन को एक अभिनेत्री के रूप में स्थापित करने के लिए शुरू की गई थी, जिसमें उनके साथ नए कलाकार आर्य और पूजा उमा शंकर भी थे. जीवा द्वारा निर्देशित यह फिल्म प्रेम कहानी पर आधारित थी और काफी समय बाद पूरी हो पाई, लेकिन अंत में बॉक्स ऑफिस पर सफल उपक्रम बन गई.

प्रतिभा के बूते सफलता संभव

फिल्म ख्वाजा मेरे ख्वाजा से एंट्री कर रही वसुंधरा को पूरा भरोसा है कि सिर्फ अपनी प्रतिभा के बूते वो बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाने में कामयाब हैं. हलांकि मायानगरी में ये आसान नहीं वह भी तब जब वह फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कलाकारों के परिवारों के से नहीं आती बल्कि उत्तर प्रदेश से हैं. वसुंधरा आगरा में फिल्म ख्वाजा मेरे ख्वाजा की शूटिंग में व्यस्त हैं. मासूमियत और सौम्यता वसुंधरा विरासत में मिली है. हालांकि फिल्म ख्वाजा मेरे ख्वाजा उनकी पहली हिंदी फिल्म है. इससे पहले वह हॉलीवुड फिल्म नेवर से कांट टेल में काम कर चुकी है. अभिनय और गायन से उनका पुराना नाता है. बचपन से उन्हें गाने का शौक था. कई नाटकों में प्ले किया. वह मुंबई में सिर्फ़ अपनी प्रतिभा और लगन के बल पर टिकी हुई हैं. वसुंधरा उत्साह से लबरेज हैं और मानती हैं कि यदि आपमें प्रतिभा हो आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है.

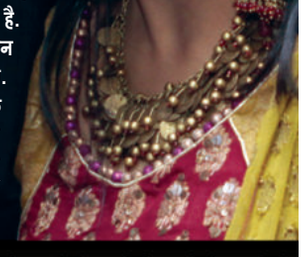

फिल्म प्रीव्यू

रा-वन

फिल्म की कहानी शेखर सुबह्मण्यम (शाहरुख खान) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक गेम डिजाइनर है, लेकिन अभी तक वह एक भी सफल वीडियो गेम नहीं बना पाया है. शेखर एक मस्तमौला आदमी है, लेकिन इसके बावजूद वह अपना ज़्यादातर समय गेम डिजाइन लैब में बिताता है, ताकि वह एक सफल वीडियो गेम बना सके. हां, उसकी एक आदत है खाना. वह खाने का बहुत शौकीन है जिससे सभी परेशान हैं. शेखर की बीवी का नाम है सोनिया (करीना कपूर), जो पंजाबी है. पंजाबी महिलाओं की तरह वह जिंदगी को भरपूर तरीके से जीने में विश्वास करती है. शेखर जो खुद दक्षिण भारतीय है, उसके साथ पंजाबी कुड़ी की जोड़ी बहुत दिलचस्प लगती है, लेकिन सोनिया का व्यवहार और आदतें शेखर से बिल्कुल उलट हैं. सोनिया किसी भी तरह की समस्या से निपट सकती है, सिवाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी के. इसके साथ ही सोनिया एक ऐसी किताब भी लिखना चाहती है जिसमें गालियां पुरुषों के ऊपर बनी हों. शेखर और सोनिया का एक बेटा है प्रतीक सुबह्मण्यम (मास्टर अमन वर्मा). प्रतीक को वीडियो गेम का बहुत शौक है. वह पूरे दिन वीडियो गेम ही खेलना पसंद करता है, लेकिन इसके साथ वह अन्य खेलों में भी रुचि रखता है, पर उसका पहला प्यार तो वीडियो गेम ही रहते हैं. प्रतीक की अपने मम्मी-पापा से नहीं पटती है. वह चाहता है कि उसके मां-बाप भी उसकी तरह रहें और जिएं. उसे अपनी लाउड पंजाबी मां पर शर्म आती है, जबकि पिता को वह बिल्कुल पसंद नहीं करता. वह चाहता है कि उसके पिता कूल दिखें, लेकिन उसके पिता शेखर (शाहरुख खान) अपने बेटे को खुश करने की सारी कोशिशें करते हैं. इसी बीच शेखर का डिजाइन किया एक गेम सफल हो जाता है. पूरा परिवार इस गेम को देखने के लिए इकट्ठा है. बीच गेम में हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाती है और तूफान आता है सुब्रह्मण्यम परिवार पर. गेम में जो भी कुछ होता है, वह इस परिवार के साथ असल में होने लगता है. यहां फिल्म कुछ-कुछ अजय देवगन की टूनपुर का सुपर हीरो की तरह लगती है. फिल्म में जी. वन (द गुड वन) नामक सुपर हीरो भी है. जी. वन बिजली से बना हुआ है और उसके अंदर रक्षा करने का प्रोग्राम फीड है. वह उड़ सकता है, कई भाषाएं बोल सकता है और कई चीजों को एक साथ नियंत्रित कर सकता है. सुब्रह्मण्यम फैमिली और जी. वन में क्या संबंध है, यह जी. वन कौन है? इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए आपको शाहरुख खान की यह बेमिसाल फिल्म देखनी होगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 24 अक्टूबर-30 अक्टूबर 2011 www.chauthiduniya.com दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

Website : sanjeevanibuildcon.in

"संजीवनी का है ऐलान, झारखण्ड-बिहार में हो सबका मकान"

AISHWARIYA RESIDENCY
Argora-Kathalmore Road, Ranchi
PLOT 6 LAC | DUPLEX 18 LAC

THE DYNASTY
Sidhu Kanhu Park, Kanke Road
PLOT 13 LAC | DUPLEX 25 LAC

SANJEEVANI HIGHWAY
Ranchi Patna Highway Road
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

SANJEEVANI TOWNSHIP
4 Lane, Kanke Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

SANJEEVANI STATION
BIT Pithoria, Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

9386045623/9470981772

9470943888, 9471763171

रोहतास में लूट की छूट

फोटो-संजय कुमार

लोकसभा अध्यक्ष के सामने भ्रष्टाचार का पिटारा खुला

30 करोड़ से अधिक की 35 सड़क योजनाओं पर काम चालू है, लेकिन ज़िला अनुश्रवण एवं निगरानी समिति बैठक में पेश हुई रिपोर्ट बताती है कि इन योजनाओं की निविदा या तो अपूर्ण है या फिर निकाले जाने की प्रक्रिया में है. इसके अलावा विधान पार्षद कृष्ण कुमार ने भी बैठक में विभिन्न योजनाओं में अधिकारियों द्वारा लगभग 15 लाख रुपये के गबन का आरोप लगाया है. रिपोर्ट में कई ग़लत तथ्यों का उजागर होना योजनाओं के प्रति जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों की लापरवाही का प्रमाण है.

सरोज सिंह

एक कहावत है, अंधेरपुर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा. अब इसकी प्रासंगिकता रोहतास ज़िले में अक्षरश: देखने व सुनने को मिल रही है. सड़कों का टेंडर निकला नहीं या मैनेज हो गया और कार्य शुरू हो गया या फिर कार्य हुआ नहीं और पैसा हजम हो गया.

काग़ज़ों पर आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चले. पेन पेपर में दुरुस्त दिखने वाली योजनाओं की हक़ीक़त जब सामने आई तो स्थानीय सांसद सह लोकसभा अध्यक्ष मीरा कमार भौचक्की रह गईं. यह वाकया ज़िला अनुश्रवण एवं निगरानी समिति बैठक का है. जिसमें समिति के सामने ज़िले की सभी योजनाओं की एकमुश्त रिपोर्ट पेश की गयी. वैसे तो हर विभाग में गड़बड़ी देखने को मिली. लेकिन ग्रामीण कार्य विभाग के कारनामों ने सबके होश उड़ा दिए. 30 करोड़ से अधिक की 35 सड़क योजनाओं के कार्य शुरू हुए थे, लेकिन रिपोर्ट में लिखा था कि इनकी निविदा ही अपूर्ण है या निकाले जाने की प्रक्रिया जारी है. यही नहीं कई सड़कों के निर्माण में लगे संवेदक या कंपनियां राशि की निकासी कर सड़क का निर्माण कर शुरू कर चुकी थीं. अब सवाल यह उठता है कि इन 35 सड़कों की निविदा नहीं निकली तो निर्माण कार्य शुरू कैसे हुआ, वह भी उसी विभाग के देख-रेख में. जिन 35 योजनाओं की हम बात कर रहे हैं वे सभी की सभी रोहतास ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों की अति महत्वपूर्ण सड़के हैं, जो ग्रामीण कार्य विभाग एक या दो के द्वारा संपादित किये जा रहे हैं. 2009 में कार्य शुरू करने के लिए इन 35 ग्रामीण सड़कों पर 30 करोड़ से ज़्यादा राशि ख़र्च करने हेतु ग्रामीण कार्य विभाग ने प्राक्कलन तैयार किया था. जिसकी कार्य समाप्ति अवधि 18 महीने की निर्धारित हुई थी. बरॉव-दिनारा पथ से मुजराढ़, दुधरा गांव तक नोखा प्रखण्ड की 4 किमी सड़क, नासरीगंज के इंटवा-बाराडीह रोड से मझरियां, सुकहरा तक 4 किमी सड़क, करगहर के सावांबहार से अकोढ़ा तक 3 किमी सड़क, करगाहर के पहाड़ी से सेन्दुआर तक 4 किमी, दिनारा के राजपुर से मुसवत तक 3 किमी सड़क, धनसोई रोड से सैसढ़ तक एक किमी सड़क, संझौली से तेन्दुआ तक 2 किमी सड़क, सासाराम के गोटपा से निमिया, शुम्भा तक 4 किमी सड़क, दरिगांव पथ से सोनगावां तक एक किमी सड़क आदि लगभग 35 सड़कें ऐसी देखने को मिली, जिनको लेकर अनुश्रवण रिपोर्ट में यह टिप्पणी की गई थी, उन सड़कों की निविदा प्रक्रिया अपूर्ण है. भौतिक सत्यापन पर नज़र दौड़ाने पर पता चला कि सड़कों का निर्माण कार्य चालू है और विभाग की तरफ से राशि निर्गत करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी है. अब इसे विभाग की लापरवाही कह लें या फिर सरकारी तंत्र की मनमानी. अगर सड़कों की निविदा नहीं हुई तो निर्माण कैसे शुरू हुआ. अगर निविदा हो गयी तो रिपोर्ट में यह गलती क्यों दोहराई गयी, यह यक्ष प्रश्न ज़िला प्रशासन ही नहीं ज़िला पदाधिकारी अनुपम कुमार के सामने भी अनुत्तरित स्थिति में खड़ा है.

उधर, बैठक में इस स्थिति को देखकर बौखलाईं लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने डीएम से कहा कि ऐसी लापरवाही करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. जब ग्रामीण कार्य विभाग 2 के कार्यपालक अभियंता मुद्रिका प्रसाद से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि सड़कों की निविदा पूर्ण है, रिपोर्ट में हुई गड़बड़ी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है. परंतु रिपोर्ट भी अगर ग़लत प्रस्तुत की गई तो यह भी बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि देश की सर्वोच्च संस्था लोकसभा के अध्यक्ष के सामने यह रिपोर्ट पेश की गई है. क्या एक ज़िम्मेदार विभाग लोकसभा अध्यक्ष को इतने हल्के से ले सकता है. अधिकारियों के रवैये पर मीरा कुमार काफ़ी ख़फ़ा दिखीं.

यह बात तो अभी सड़कों की थी. चर्चा जब जनप्रतिनिधियों के विकास मद के दुरुपयोग पर शुरू हुई तो स्वयं विधान पार्षद कृष्ण कुमार ने आगे आकर अनुश्रवण समिति की बैठक में अपनी विभिन्न योजनाओं के लगभग 15 लाख रुपयों का अधिकारियों द्वारा बिना कार्य कराए गबन कर लेने का आरोप सरेआम लगा डाला. यह कार्य भी ग्रामीण कार्य विभाग-2 के ही अधीन था. शहर के धार्मिक स्थल महावीर स्थान के लिए 10 लाख रुपये की लागत से बनने वाले अतिथिशाला की आधी राशि 5 लाख रुपये विभाग के अधिकारी हजम कर चुके हैं. मामले की जांच जब सदर अनुमंडलाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा से करायी गयी तो आरोप सही निकले और पता चला कि निर्माण स्थल पर एक ईंट भी नहीं रखी गयी है. साथ ही पैसा अधिकारियों ने हजम कर लिया है. इसी तरीके से श्री सिंह की योजना मद से गजराढ़ मोहल्ले में 2.5 लाख रुपये की लागत से बनने वाली सड़क का निर्माण का कार्य हुआ भी नहीं और इसके हिस्से की राशि निकालकर उसका वारा न्यारा कर दिया गया. अगरेर में आम लोगों के लिए बनाने वाले पेशाबखाने के लिए 25 हज़ार रुपये की राशि को अधिकारियों ने हजम कर लिया. योजनाओं में अनियमितता की फेहरिस्त इतनी लंबी हो चुकी है कि उसे उंगलियों पर नहीं गिनाया जा सकता. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण की तरफ से ज़िले में 2007 से 2010 के बीच शुरू की गई लगभग 30 पेय जलापूर्ति योजनाएं आज भी अपूर्ण हैं.

हालांकि सबकी प्रगति रिपोर्ट के सामने विद्युत कनेक्शन न होने का रोना रोया गया है. यहां तक कि मीरा कुमार द्वारा सासाराम एवं आस-पास के पहाड़ी क्षेत्रों में लगाने के लिए 5 दर्जन चापाकलों की अनुशंसा भी छह महीने तक धरी की धरी रह गयी. इस पर बैठक में मीरा कुमार ने कहा कि 15 दिनों के अंदर अगर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिखी तो बड़े पैमाने पर कार्रवाई की अनुशंसा हो सकती है. मालूम हो कि इन 30 पेय जलापूर्ति योजनाओं में सब की सब वैसे क्षेत्रों के लिए अनुशंसित है, जहां गर्मी के दिनों में लोग पेयजल के लिए 4-4 किमी की दूरी तय कर अपनी प्यास बुझाते हैं. बीते 10 अक्टूबर को ज़िले में हुई अनुश्रवण समिति बैठक की रिपोर्ट में कई ग़लत तथ्यों का उजागर होना योजनाओं के प्रति जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों की लापरवाही उजागर करता है. इस संदर्भ में डीएम अनुपम कुमार बताते हैं कि यह रिपोर्ट कार्य प्रगति के अनुरूप नहीं है क्योंकि कुछ अधिकारियों ने पुरानी रिपोर्ट प्रेषित कर डाली है. जिन पर कार्रवाई सुनिश्चित की गयी है. आरईओ 1 और 2 के कार्यपालक अभियंताओं से स्पष्टीकरण पूछा गया है, जबकि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता के वेतन पर रोक लगाने की अनुशंसा की गयी है.

ग़ौर करने वाली बात यह है कि यह तो बिहार के एक ज़िले का हाल है अगर एक एक कर सभी ज़िलों की परत खोली जाए तो पता चल जाएगा कि विकास के दावों व भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन की सच्चाई क्या है.

feedback@chauthiduniya.com

Launches

Shanti Kunj & Shanti Vihar

ON NH-23 AT KATHAL MORE

Luxury Living Redefined

1 BHK 866 Sqft
2 BHK 1035, 1072 1095, 1275 Sqft
3 BHK 1555, 1650 1885 Sqft

HIGHLIGHTS

• 1/2/3 BHK with SERVANT ROOM on each Floor • Next to INDIAN FOREST INSTITUTE (Govt. of India) & LALGUTWA VILL • DAV HEHAL SCHOOL RANCHI HOSPITAL Petrol Pump, Govt. School, ITI, Bus Stand PADOSAN Resturant • On NH-23 (Leading to GUMLA, CHATTISGARH & MUMBAI) • GREEN ORCHARDS in Neighbourhood • Hill View • Near RING ROAD (On NH-23) • All Basic Amenities

Guest House

Swimming Pool

Health Club

*Terms&conditions Apply

AARON DEVELOPERS

469 - C, Mandir Marg, Ashok Nagar, Ranchi - 834 002

Cell : 9199007777, 9955557740, 9570000154, Email : aaronranchi@gmail.com